चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

www.chauthiduniya.com

1986 से प्रकाशित

दिल्ली, 15 अगस्त-21 अगस्त 2011

मूल्य 5 रुपये

तिरंगे का इतिहास

पेज-3

क़िस्मत के मारे किसान

पेज-5

इस सर्वे का नतीजा क्या निकलेगा

पेज-6

साई की महिमा

पेज-12

षड्यंत्र के साये में इंडियन आर्मी

प्रधानमंत्री ख़ामोश क्यों हैं

जब लेफ्टिनेंट जनरल बिक्रम सिंह कांगो में भारतीय शांति सेना के चीफ थे तो वहां रहे कुछ सिपाहियों और अफ़सरों पर यौन शोषण का आरोप लगा था. इसकी जांच भारतीय सेना कर रही है.

आख़िर क्या वजह है कि ले. जनरल बिक्रम सिंह के गंभीर आरोपों में घिरे होने के बाद भी प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री उन्हें भावी सेनाध्यक्ष बनाना चाहते हैं. अपने बेटे की शादी पाकिस्तानी लड़की से करने के बाद भी वह सेनाध्यक्ष जैसे अति संवेदनशील पद पर बैठाए जा रहे हैं. क्या इसके पीछे सिर्फ़ उनका प्रधानमंत्री के समाज का होना कारण है या किसी बड़ी विदेशी ताक़त का भारत सरकार पर दबाव है? प्रधानमंत्री कार्यालय यूपीए के ही एक सांसद द्वारा उठाए सवाल पर ख़ामोश क्यों है?

कश्मीर में ही रहते हुए कैसे दुकानों के आवंटन में धांधली हुई और कैसे लेफ्टिनेंट जनरल बिक्रम सिंह इस मामले में शामिल थे, इस पर भी एक सांसद ने प्रधानमंत्री को ख़त लिखा, लेकिन प्रधानमंत्री ने उस ख़त का जवाब नहीं दिया.

संसद का एक वरिष्ठ सांसद यदि प्रधानमंत्री को ख़त लिखे और पूछे कि क्या सरकार द्वारा भारत के थल सेनाध्यक्ष पद के भावी उम्मीदवार लेफ्टिनेंट जनरल की बहू यानी उनके दुबई में काम करने वाले लड़के की पत्नी पाकिस्तान की नागरिक है? तो यह गंभीर मामला बन जाता है. प्रधानमंत्री कार्यालय इसका उत्तर देने की जगह उन सांसद पर उनकी पार्टी द्वारा दबाव डलवाता है कि वह इस ख़त को वापस ले लें. इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री के साथ जुड़े एक मंत्री नारायण सामी संसद में ही इस सांसद को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि आप ख़त वापस ले लीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री काफ़ी अपसेट हैं. सांसद कहते हैं कि अच्छा हो प्रधानमंत्री चार लाइन का उत्तर भेज दें कि उनके द्वारा ख़त में उठाए गए सवाल ग़लत हैं, पर प्रधानमंत्री अब तक ख़ामोश हैं, कम से कम इस रिपोर्ट के लिखे जाने के समय तक. दरअसल सेना का यह सख्त नियम है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो भारतीय सेना में है, वह या उसका परिवार किसी विदेशी नागरिक से शादी करता है तो उसे सूचना भी देनी होगी. यहां तो किसी भी विदेशी नागरिक से नहीं, पाकिस्तानी नागरिक से शादी का मामला है. अगर यह ख़बर सही है तो भारत के थल सेनाध्यक्ष के घर में पाकिस्तानी नागरिक होगा, जिसके पास सेना के सारे राज़ होंगे. हमेशा ख़तरा बना रहेगा कि ये राज़ या ख़ुफ़िया सूचनाएं पाकिस्तान न पहुंच जाएं. प्रधानमंत्री द्वारा अब तक ख़त का जवाब न देना बताता है कि आरोप सही हैं.

भारत के भावी थल सेनाध्यक्ष अक्सर अपने बेटे और पाकिस्तानी बहू से मिलने दुबई जाते रहते हैं. इसके बारे में अंग्रेजी के एक मशहूर साप्ताहिक ने रिपोर्ट छापी है कि जब यह कांगो में भारतीय शांति सेना के चीफ थे तो वहां रहे कुछ सिपाहियों और अफ़सरों पर यौन शोषण का आरोप लगा था. इसकी जांच भारतीय सेना कर रही है. जब बिल क्लिंटन राष्ट्रपति के रूप में भारत आए तो कश्मीर के छत्तीसिंह पुरा में सिखों की हत्या हुई थी. जांच में पता चला कि इसमें काफ़ी संदेह है कि ये हत्याएं आतंकवादियों ने की हैं. इसमें अनदेखी का आरोप इन्हीं ले. जनरल साहब पर लगा. जब यह कश्मीर के कोर कमांडर थे तो एक पैंसठ साल के व्यक्ति का एनकाउंटर हुआ. पुलिस ने जांच की तो पता चला कि यह फ़र्ज़ी एनकाउंटर था. अनंतनाग के डीआईजी ने जांच रिपोर्ट आने के बाद बाक़ायदा प्रेस कांफ्रेंस की. भारत के भावी थल सेनाध्यक्ष ने कोर कमांडर रहते हुए सेना से प्रशस्ति पत्र भी ले लिया. कश्मीर में ही रहते हुए कैसे दुकानों के आवंटन में धांधली हुई, इस पर भी सांसद ने प्रधानमंत्री को ख़त लिखा, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस ख़त का जवाब नहीं दिया.

हां, रक्षा मंत्री ने एक सांसद के ख़त का जवाब ज़रूर दिया है. रक्षा मंत्री को सांसद महोदय ने लिखा था कि जनरल दीपक कपूर के ख़िलाफ़ आदर्श मामले में क्या कार्रवाई की जा रही है. रक्षा मंत्री ने कहा कि उन्होंने सीवीसी और सीबीआई के पास मामला भेज दिया है. जब हमने इन दोनों संस्थाओं से पता किया तो मालूम हुआ कि वहां इस मामले पर पूरी ख़ामोशी भी है और गोपनीयता भी. लेकिन रक्षा मंत्री परेशान हैं. उन्होंने एक भूतपूर्व रक्षा मंत्री से कहा कि वह वर्तमान सेनाध्यक्ष जनरल वी के सिंह की जन्म तिथि को लेकर परेशान हैं और उन्हें मदद चाहिए. क्यों परेशान हैं भारत के रक्षा मंत्री? शायद इसलिए कि वह ऐसा काम कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए. जनरल वी के सिंह के जन्म तिथि विवाद में रक्षा मंत्रालय ने ग़लत और अनैतिक काम किया है. राजनीतिक हस्तक्षेप से पहले के काग़ज़ और बाद के काग़ज़ अलग-अलग कहानी कह रहे हैं. हमें मिले एक दस्तावेज़ के मुताबिक़, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, लीगल एडवाइज़र (डिफेंस) के पत्र Dy. No. 0486/XI/LA (Def) में इंदर कुमार लीगल एडवाइज़र डिफेंस ने 14.2.2011 को रक्षा मंत्रालय को अपने नोट के पैरा (डी) में लिखा, ***इट हैज आलसो बीन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द फाइल दैट इन द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ यूपीएससी इन 1965 प्रोबेबली फिल्ड बाई अनदर पर्सन (क्लर्क/टीचर) व्हेअरइन द डेट ऑफ बर्थ हैज बीन मेंशन्ड एज 10 मे 1950. इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट द यूपीएससी, व्हेन नोटिसिंग द डायकोटोमी रेज्ड द सेम क्वैरी हेन्स, इज सेफ टू प्रीज्यूम दैट यूपीएससी एक्सेप्टेड द डेट ऑफ बर्थ मेंशन्ड इन हाईस्कूल सर्टिफिकेट, राजस्थान बोर्ड एज द रूल्स ऑफ यूपीएससी क्लेयरली स्टेट दैट द डेट ऑफ बर्थ एज मेंशन्ड इन हाईस्कूल सर्टिफिकेट इज टू बी एक्सेप्टेड एज करेक्ट एंड लेजिटिमेट.***

लेकिन जब वाहनवती तस्वीर में आते हैं तो वह अपने विभाग द्वारा दी गई राय

जब बिल क्लिंटन राष्ट्रपति के रूप में भारत आए तो कश्मीर के छत्तीसिंह पुरा में सिखों की हत्या हुई थी. जांच में पता चला कि इसमें काफ़ी संदेह है कि ये हत्याएं आतंकवादियों ने की हैं. इसमें अनदेखी का आरोप इन्हीं लेफ्टिनेंट जनरल साहब पर लगा.

(शेष पृष्ठ 2 पर)

लेफ्टिनेंट जनरल बिक्रम सिंह और विवाद

(पृष्ठ 2 पर)

अनुभवी योद्धा लेफ्टिनेंट जनरल के टी परनायक

(पृष्ठ 2 पर)

पीएम के नाम यूपीए के एक सांसद का पत्र

(पृष्ठ 2 पर)

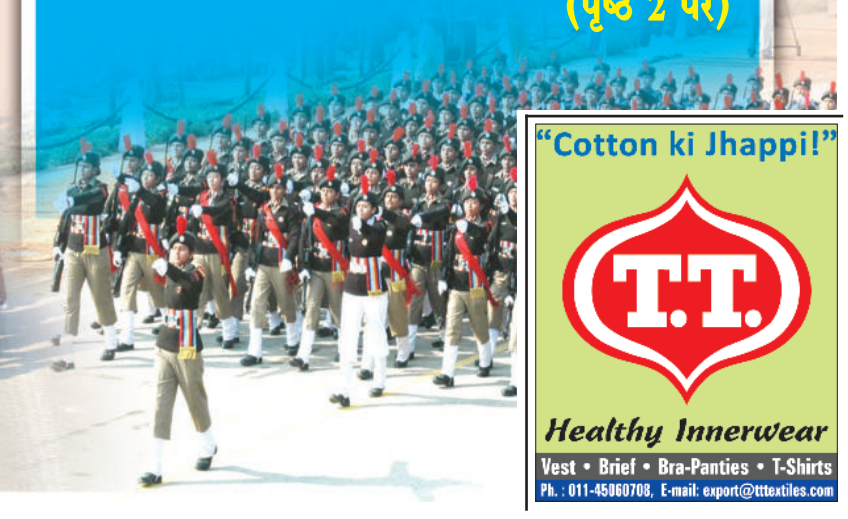

सूत्रों के मुताबिक, मंत्री समूह के अध्यक्ष प्रणब मुखर्जी इस मामले को योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया के पास ले जाने की योजना बना रहे हैं.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

आईएएस बनने का ख्वाब

भारत में नव उदारवाद के दौर के बाद से मध्य वर्ग में लोक सेवा का आकर्षण बहुत ज्यादा नहीं बचा. फिर भी अन्य लोगों में इसे लेकर अभी भी दिलचस्पी बची हुई है. हाल के वर्षों में ऐसी कई खबरें आईं, जहां आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कई उम्मीदवारों ने लोक सेवा की परीक्षा में अपने दम पर सफलता पाई है. इस साल मीर बसीत हुसैन, जो कभी भी स्कूल नहीं गए, यूपीएससी परीक्षा में सफल होने वाले 3 फीसदी मुस्लिम उम्मीदवारों में से एक हैं. हुसैन बचपन में केरल के एक अनाथालय में पले और वहीं पर उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा हासिल की. फिर इतिहास विषय से स्नातक बने, वह भी कालीकट विश्वविद्यालय की दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के तहत पढ़ाई करके. दिलचस्प रूप से जब हुसैन अपने प्रशिक्षण के लिए मसूरी पहुंचे, तब वह असल में औपचारिक रूप से पहली बार किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश कर रहे थे.

सरकार को मिली सीख

टू जी स्पैक्ट्रम घोटाले के बाद सरकार अपनी कुछ नीतियों में ऐसे बदलाव कर सकती है, जिनके बारे में शायद बाबुओं को भी अंदाजा नहीं होगा. कॉरपोरेट घराने से बाबुओं के संबंध सामने आने के बाद सरकार अपनी उन नीतियों पर पुनर्विचार करने को मजबूर हो गई है, जिनके तहत ये बाबू रिटायर होने के बाद कॉरपोरेट घरानों को अपनी सेवाएं देते हैं. फिलहाल यह प्रावधान है कि कोई बाबू रिटायर होने के एक साल के भीतर किसी कॉरपोरेट हाउस से नहीं जुड़ सकता है. सरकार के पास कॉरपोरेट हाउस से जुड़ने के लिए हर महीने करीब 10 से 12 अनुरोध रिटायर बाबुओं के आते हैं. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने अब ऐसे अधिकांश अनुरोधों को अस्वीकार करना शुरू कर दिया है और एक साल के प्रावधान में संशोधन करके उसे तीन साल करने का काम शुरू कर दिया है. स्पष्ट तौर पर सरकार अब कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती.

अपारदर्शी योजना आयोग

योजना आयोग में पारदर्शिता को लेकर बहस तेज हो गई है. आयोग में अपारदर्शी तरीके से सलाहकार की नियुक्ति को लेकर विवाद पैदा हो गया है और इस सबके खिलाफ आवाज उठाने का काम योजना आयोग की ही सदस्य-सचिव सुधा पिल्लई कर रही हैं, जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मंत्री समूह की बैठक में भाग ले चुकी हैं. ऐसा प्रतीत हो रहा है कि योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सहमति के बगैर ही आयोग में सलाहकारों की नियुक्ति कर दी गई है. ऐसा लग रहा है कि कुछ मामलों में नियमों के साथ छेड़छाड़ भी की गई. मसलन, अप्वायंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट से भी सहमति नहीं ली गई, जो कि जरूरी थी. सूत्रों के मुताबिक, मंत्री समूह के अध्यक्ष प्रणब मुखर्जी इस मामले को योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया के पास ले जाने की योजना बना रहे हैं.

dilipcherian@gmail..com

साउथ ब्लॉक

जवाहर प्रसार भारती के सीईओ

प्रसार भारती से बी एस लाली की विदाई के बाद से सीईओ का पद रिक्त था, लेकिन अब लगभग तय हो गया है कि पश्चिम बंगाल कैडर और 1975 बैच के आईएएस अधिकारी जवाहर सरकार प्रसार भारती के नए सीईओ होंगे. वह अभी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में सचिव हैं.

दिनेश नए जेएस

उत्तर प्रदेश कैडर और 1982 बैच के आईएएस अधिकारी दिनेश सिंह का नाम एमएसएमई के नए संयुक्त सचिव के लिए लगभग तय हो गया है. वह शेष कुमार पुलिपका की जगह लेंगे.

भट्ट डिफेंस डायरेक्टर

सूत्रों के मुताबिक, रमेश भट्ट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के नए निदेशक होंगे. वह 1995 बैच के आईसीएएस अधिकारी हैं. यह पद नवसृजित है.

मिश्रा बनेंगे सचिव

उत्तर प्रदेश कैडर और 1976 बैच के आईएएस अधिकारी ए के मिश्रा आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय में आवास सचिव बनाए जा सकते हैं. अभी तक उनके पास इस विभाग के सचिव पद का अतिरिक्त प्रभार था.

शंभू जेएस नहीं बनेंगे

तमिलनाडु कैडर और 1991 बैच के आईएएस अधिकारी भारत सरकार में शामिल नहीं होंगे. सूत्रों के मुताबिक, उनका नाम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव पद के लिए लगभग तय था.

प्रधानमंत्री ख़ामोश क्यों हैं

पृष्ठ एक का शेष

उलट देते हैं, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के ख़िलाफ़ कहते हैं कि जनरल वी के सिंह की जन्म तिथि न हाईस्कूल के सर्टिफिकेट वाली मानी जाए, न यूपीएससी वाली, बल्कि 1950 मानी जाए. वाहनवती ने सुप्रीम कोर्ट में सरकार की हार का दस्तावेज़ तैयार कर दिया है. अगर यह केस सुप्रीम कोर्ट जाता है तो?

चौथी दुनिया में जैसे ही यह सारी चोरबाज़ारी और घपलेबाज़ी छपी, वैसे ही दो महान पत्रकारों की दलाली ने सरकार को हिम्मत दी और उसने न्याय के ख़िलाफ़ फ़ैसला लिया और जनरल की डेट ऑफ बर्थ 1950 मान ली तथा घोषणा कर दी कि वह जून में रिटायर हो जाएंगे. अब इस फ़ैसले के आधार पर यदि यूपीएससी द्वारा सेना में जाने वाले कैंडीडेट यदि अपनी जन्म तिथि हाईस्कूल के सर्टिफिकेट से अलग लिखते हैं तो सरकार क्या करेगी? उन्हें मानेगी या नहीं? सरकार का यह फ़ैसला विवादों का, जन्म तिथि से जुड़े विवादों का पिटारा खोल देगा. सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगा ही और सुप्रीम कोर्ट का अपना फ़ैसला है कि जन्म तिथि विवाद में हाईस्कूल का सर्टिफिकेट अंतिम प्रमाण है. पर भारत की महान सरकार अपनी हार की इबारत ख़ुद लिख रही है, जिसकी स्याही वाहनवती, जो भारत के एटार्नी जनरल हैं, ने ख़ुद सप्लाई की है. वैसे वाहनवती साहब भी ख़ूब हैं. हाईकोर्ट में उन्होंने टूजी स्पैक्ट्रम का दो साल तक बचाव किया और अब सुप्रीम कोर्ट में उन्हें सरकार के लिए लड़ना है. वह इस केस में गवाह भी हैं और गवाही में उनका नंबर 125वां है.

हमने जनरल वी के सिंह के ख़िलाफ़ आरोप छान मारे, हमें एक भी आरोप नहीं मिला, जबकि उसी कड़ी में सरकार के चुने भावी थल सेनाध्यक्ष ले. जनरल बिक्रम सिंह के ख़िलाफ़ काफ़ी कुछ बातें संयोग से हाथ लग गईं. हम चाहेंगे कि जिनके पास जनरल वी के सिंह के ख़िलाफ़ आरोप हों, वे हमसे मिलें, हम उन्हें भी इंवेस्टीगेट कर छापना चाहेंगे. अभी तो हमें एक ही आरोप मिला कि उन्होंने अपनी जन्म तिथि पहले 1950 लिखी, बाद में 1951 कही. इस आरोप की सफ़ाई के लिए जनरल वी के सिंह सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते तो उन्हें यह दाग़ लिए रिटायर होना पड़ेगा. जनरल वी के सिंह को वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने बुलाया और बीच का रास्ता निकालने का सुझाव दिया. हालांकि प्रणव मुखर्जी ने कहा कि उन्हें लगता है कि अन्याय हुआ है. मैंने कांग्रेस के एक शक्तिशाली महासचिव से पूछा तो उन्होंने कहा कि जनरल वी के सिंह चाहें तो यह दाग़ लिए रिटायर हो जाएं, हम उन्हें राज्यपाल बना देंगे और चाहें तो सुप्रीम कोर्ट चले जाएं और अगर वह इसे दाग़ मानते हैं तो इसे वहां से साफ़ करा लें.

आख़िर क्या वजह है कि ले. जनरल बिक्रम सिंह के गंभीर आरोपों में घिरे होने के बाद भी प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री उन्हें भावी सेनाध्यक्ष बनाना चाहते हैं. उनके द्वारा अपने बेटे की शादी पाकिस्तानी लड़की से करने के बाद भी वह सेनाध्यक्ष जैसे अति संवेदनशील पद पर बैठाए जा रहे हैं. क्या इसके पीछे सिर्फ़ उनका प्रधानमंत्री के समाज का होना कारण है या इसके पीछे किसी बड़ी विदेशी ताक़त का भारत सरकार पर दबाव है? प्रधानमंत्री कार्यालय यूपीए के ही एक सांसद द्वारा उठाए सवाल पर ख़ामोश क्यों है? सुप्रीम कोर्ट में हार का ख़तरा उठाते हुए क्यों सरकार यह फ़ैसला करने पर उतारू है, जिसके परिणामस्वरूप रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा?

एक कारण और है. अगर सरकार जनरल वी के सिंह का जन्म वर्ष 1951 मान लेती तो ले. जनरल बिक्रम सिंह सेनाध्यक्ष नहीं बन सकते हैं, उस स्थिति में ले. जनरल के टी परनायक सेनाध्यक्ष बन सकते हैं. ले. जनरल के टी परनायक सेना में बहुत ही ज़्यादा ईमानदार और बहादुर अफ़सर माने जाते हैं. वह महाराष्ट्रियन हैं और उन पर कोई दाग़ नहीं है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय हथियार माफ़िया को ईमानदार अफ़सर पसंद नहीं आते. जनरल वी के सिंह के यहां ऐसे तत्वों की पहुंच नहीं है, ऐसा आईबी के अफ़सरों का कहना है, लेकिन जनरल जे जे सिंह और जनरल दीपक कपूर के यहां ऐसे तत्वों की पहुंच थी. ले. जनरल बिक्रम सिंह के सवाल पर वे ख़ामोश हो जाते हैं. ले. जनरल के टी परनायक को ख़ुफ़िया सूत्र मुख्य न्यायाधीश कपाड़िया की तरह ईमानदार बताते हैं.

हमारी पूरी जांच हमें बताती है कि जनरल वी के सिंह की जन्म तिथि का विवाद जानबूझ कर जनरल जे जे सिंह और जनरल दीपक कपूर का पैदा किया है. उनकी जन्म तिथि सभी सबूतों के अनुसार 10 मई, 1951 है. उनकी जन्म तिथि पर जल्दबाज़ी में फ़ैसला इसलिए लिया गया, क्योंकि चौथी दुनिया ने यह सारी कहानी छाप दी थी. फ़ैसले के पीछे अंतरराष्ट्रीय माफ़िया है, जिसने सारे दबाव बना दिए हैं. मीडिया भी, डिफेंस जर्नलिस्ट भी इनके संपर्क में हैं. अब जनरल वी के सिंह के हाथ में है कि वह सुप्रीम कोर्ट जाते हैं या राज्यपाल बनने का प्रस्ताव अपने ऊपर लगे दाग़ के साथ स्वीकार कर लेते हैं. पर प्रधानमंत्री को तृणमूल कांग्रेस के सांसद के ख़त का जवाब तो दे देना चाहिए कि क्या ले. जनरल बिक्रम सिंह की बहू पाकिस्तानी नागरिक है?

विशेष संवाददाता
feedback@chauthiduniya.com

लेफ्टिनेंट जनरल बिक्रम सिंह और विवाद

लेफ्टिनेंट जनरल बिक्रम सिंह एक कमीशंड ऑफिसर के तौर पर 1972 में सिख लाइट इंफैंट्री रेजीमेंट से जुड़े थे. फ़िलहाल वह ईस्टर्न कमांड के मुखिया हैं और सेनाध्यक्ष जनरल वी के सिंह के बाद सेनाध्यक्ष पद के मुख्य दावेदार भी हैं. लेकिन 38 साल के करियर में लेफ्टिनेंट जनरल बिक्रम सिंह का विवादों से रिश्ता मानो चोली-दामन जैसा रहा है. मसलन, फ़र्ज़ी मुठभेड़ के आरोपियों को बचाने के लिए बिक्रम सिंह (तब वह कश्मीर में तैनात थे और ब्रिगेडियर थे) ने सीबीआई को पत्र लिखा. पूरा किस्सा कुछ यूं है. 20 मार्च, 2000 को जब बिल क्लिंटन भारत के दौरे पर थे, आतंकवादियों ने कश्मीर के छत्तीसिंह पुरा में 36 सिखों की हत्या कर दी. इसके ठीक 5 दिनों बाद सेना के जवानों ने अनंतनाग के पथरीबल में 5 नागरिकों को इस आरोप में मार गिराया कि वे सिख नरसंहार की घटना में शामिल थे. 3 साल की जांच के बाद सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की, तब उसमें ब्रिगेडियर बिक्रम सिंह के उस पत्र (संख्या ए/38240/एमओ3ए, दिनांक 31 दिसंबर, 2004) को भी शामिल किया था, जिसमें यह लिखा गया था कि उक्त घटना में शामिल सेना के अधिकारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की जा सकती है, क्योंकि उन्हें अफसपा (आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट) के तहत विशेष अधिकार मिला हुआ है. सीबीआई ने इस पत्र के माध्यम से सेना की भूमिका पर सवाल खड़े किए थे. एक और गंभीर आरोप में बिक्रम सिंह फंस सकते हैं. मामला 2008 में यूएन की शांति सेना के तौर पर कांगो गए सिख रेजिमेंट के 51 अधिकारियों एवं जवानों द्वारा वहां पर बलात्कार और सेक्सुअल मिसकंडक्ट के आरोप का है. मेरठ स्थित आर्मी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इस मामले की जांच कर रही है. ग़ौरतलब है कि इस रेजिमेंट के 120 अधिकारियों और जवानों की एक कंपनी कांगो गई थी, जिसकी कमान लेफ्टिनेंट जनरल बिक्रम सिंह संभाल रहे थे. जाहिर है, अगर जांच में उक्त आरोप सही पाए गए तो यह लेफ्टिनेंट जनरल बिक्रम सिंह के करियर पर काला धब्बा साबित होगा.

अनुभवी योद्धा लेफ्टिनेंट जनरल के टी परनायक

नॉर्दन कमांड के मुखिया लेफ्टिनेंट जनरल के टी परनायक का विभिन्न परिस्थितियों में लंबे समय तक काम करने का अनुभव उन्हें अन्य सैन्य अधिकारियों से अलग करता है. लेफ्टिनेंट जनरल के टी परनायक को विद्रोहियों और काफी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में युद्ध करने का एक लंबा अनुभव है. कश्मीर से लेकर सुदूर उत्तर-पूर्व तक उन्होंने एक सक्षम सेना अधिकारी के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. परनायक नेशनल डिफेंस अकादमी, खड़गवासला से पढ़कर 1972 में कमीशंड ऑफिसर बने. उन्होंने डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन से स्नातक भी किया. वह ऑपरेशन पराक्रम के भी महत्वपूर्ण हिस्सा रहे. लेफ्टिनेंट जनरल परनायक अपने करियर के दौरान सेना के महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित पदों पर रहे. मसलन, मिलिट्री इंटेलिजेंस के एडीजी रहे, साथ ही इंडियन मिलिट्री अकादमी और आर्मी वॉर कॉलेज को भी अपनी सेवाएं दीं. लेफ्टिनेंट जनरल परनायक को उत्तर-पूर्व क्षेत्र में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से दो बार प्रशंसा पत्र भी मिल चुके हैं. ऑपरेशन पराक्रम में विशेष योगदान के लिए 2003 में उन्हें युद्ध सेवा मेडल भी मिल चुका है.

पीएम के नाम यूपीए के एक सांसद का पत्र

चौथी दुनिया के पास उपलब्ध एक पत्र, जो तृणमूल सांसद अंबिका बनर्जी द्वारा 7 जुलाई, 2011 को प्रधानमंत्री को लिखा गया, लेफ्टिनेंट जनरल बिक्रम सिंह पर एक और संगीन आरोप का ख़ुलासा करता है. हावड़ा से तृणमूल कांग्रेस के सांसद अंबिका बनर्जी अपने इस पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लेफ्टिनेंट जनरल बिक्रम सिंह के एक कारनामे के बारे में सूचित करते हैं और कार्रवाई की मांग करते हैं. बनर्जी अपने पत्र में लिखते हैं कि कोर कमांडर पद पर रहते हुए बिक्रम सिंह ने एच क्यू 15 कोर (श्रीनगर) में 10 दुकानें आवंटित की थीं. वह आगे लिखते हैं कि मुझे बताया गया है कि बिक्रम सिंह ने इस आवंटन के बदले हर एक दुकान के लिए 3 से 5 लाख रुपये लिए. बनर्जी इसे शर्मनाक बताते हुए प्रधानमंत्री से इस मामले को देखने के लिए कहते हैं और यह भी अनुरोध करते हैं कि जब तक जांच पूरी न हो जाए, तब तक के लिए बिक्रम सिंह को उनकी संवेदनशील पद पर तैनाती से हटा दिया जाए. बहरहाल, प्रधानमंत्री की ओर से इस मसले पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है, किसी को नहीं पता. क्या इस मामले पर अब भी कोई कार्रवाई होगी, कहा नहीं जा सकता.

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 3 अंक 23
दिल्ली, 15 अगस्त–21 अगस्त 2011
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार–झारखंड)

प्रबंध संपादक
श्रीनिवास गुप्ता (उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड)

प्रबंध संपादक (महाराष्ट्र)
प्रवीण महाजन

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के– 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय

के –2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा
गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.
संपादकीय 0120–4783999/011–23418962
0120–6450888, 0120–6452888
0120–6451999
विज्ञापन व प्रसार +91 120–4783999
+91 9266627366
फैक्स न. 0120–4783950

पृष्ठ–16+4 (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड एवं महाराष्ट्र)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.
समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

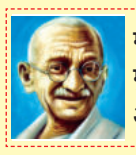

महात्मा गांधी का मानना था कि लाल व हरा रंग तो हिंदू और मुस्लिम समुदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के लिए सबसे ऊपर सफ़ेद रंग भी जोड़ा जाए.

तिरंगे का इतिहास

रीतिका सोनाली

किसी भी देश का राष्ट्रीय ध्वज उसकी पहचान ही नहीं, बल्कि उसके इतिहास और विचार को भी दर्शाता है. दुनिया भर में झंडे का इस्तेमाल प्राचीन काल से हो रहा है. जब राष्ट्र का निर्माण भी नहीं हुआ था, तब झंडे का इस्तेमाल कबीलाई समाज के लोग किया करते थे. कबीले के नेता या लोग उस कबीले के प्रति अपनी निष्ठा या वफादारी के प्रमाण स्वरूप अपने घरों के बाहर झंडा लगाया करते थे. जब लोग कबीलाई जीवन व्यतीत करते थे, तब वे आपस में लड़ते भी थे. लोगों को ऐसे प्रतीक की ज़रूरत महसूस हुई, जो कबीले की पहचान बने. लड़ाई में पराजित कबीले के क्षेत्र में विजेता कबीला अपने झंडे लगा देता था. भारत में झंडे का इतिहास ऋग्वेद काल से शुरू होता है, जब धूमकेतु झंडे का इस्तेमाल होता था. रामायण में भी शहर, शिविर, रथयात्रा और रण क्षेत्र के बारे में झंडे का ज़िक्र मिलता है. रामायण में निषादराज गुह की नावों में स्वास्तिक ध्वज, महाराजा जनक का सीरध्वज और उनके भाई के कुशध्वज का वर्णन है. महाभारत काल में तो ध्वज का भरपूर विवरण है. हर योद्धा का अलग-अलग झंडा था. समय के साथ झंडे का रिश्ता सेना से जुड़ गया. जब जनसंख्या बढ़ने लगी और राष्ट्र का उदय हुआ, तब झंडा राष्ट्र का प्रतीक बन गया. हर देश का अपना झंडा होना अनिवार्य हो गया. माना यह जाता है कि डेनमार्क दुनिया का पहला देश है, जिसने सबसे पहले अपना राष्ट्रीय ध्वज बनाया.

आज दुनिया के हर देश का अपना ध्वज है, जिसे संप्रभुता का प्रतीक माना जाता है. भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा कहलाता है, जिसे पिंगली वैंकैयानंद ने बनाया. भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तीन रंग की पट्टियां हैं. सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी है. सफ़ेद पट्टी के बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र है, जिसे अशोक स्तंभ से लिया गया है. इसमें 24 तीलियां हैं. ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है. 15 अगस्त, 1947 से पहले तिरंगे को 22 जुलाई, 1947 को भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया. स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत के प्रतीक के रूप में अलग- अलग झंडों का प्रयोग हुआ. आज भारत का जो तिरंगा है, वह अचानक ही किसी परिकल्पना का परिणाम नहीं है. हमारा राष्ट्रीय ध्वज आज़ादी की लड़ाई के दौरान विकसित हुआ है. 22 जुलाई, 1947 को संविधान सभा ने इसे स्वतंत्र भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया. स्वतंत्रता मिलने के बाद इसके रंग और उनका महत्व बना रहा. केवल ध्वज में चलते हुए चरखे के स्थान पर सम्राट अशोक के धर्मचक्र को दिखाया गया. इस प्रकार कांग्रेस पार्टी का तिरंगा ध्वज अंततः स्वतंत्र भारत का तिरंगा ध्वज बना. यह ध्वज भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का चिन्ह भी था. हमारे राष्ट्रीय ध्वज के विकास में कुछ ऐतिहासिक पड़ाव इस प्रकार हैं:

सबसे पहले 1904 में स्वामी विवेकानंद की शिष्या सिस्टर निवेदिता ने एक झंडा प्रस्तुत किया. लाल और पीले रंग के इस झंडे में वज्र और कमल के फूल भी थे. लाल रंग स्वतंत्रता संग्राम का तो पीला विजयी होने का प्रतीक था. वज्र शक्ति को और कमल शुद्धता को दर्शाता था. झंडे पर बंगाल की पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास आनंदमठ के गीत के शीर्षक वंदे मातरम को लिखवाया गया. इस झंडे को कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में दिसंबर 1906 में प्रदर्शित किया गया. उस समय भारत का कोई एक झंडा नहीं हुआ करता था तो हर कोई अपने सुझाव दे रहा था. उन्हीं में से सचिंद्र नाथ बोस का तिरंगा एक था, जो उन्होंने 7 अगस्त, 1906 को बंगाल के विभाजन के विरोध में पारसी बागान चौक (ग्रीन पार्क) कोलकाता में फहराया था. इस झंडे के सबसे ऊपर संतरी रंग, बीच में पीला और सबसे नीचे हरा रंग था. संतरी रंग की पट्टी में 8 आधे खिले हुए कमल के फूल थे. सबसे नीचे सूरज और चंद्रमा था और बीच में देवना-गरी में वंदे मातरम लिखा हुआ था.

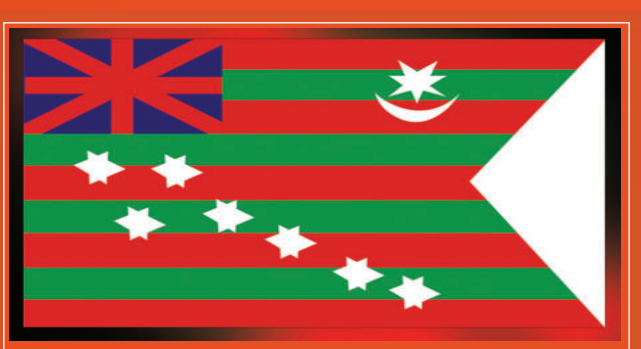

उसके बाद भीकाजी कामा ने 22 अगस्त, 1907 को एक और तिरंगा जर्मनी में फ़हराया. इसमें हरा रंग सबसे ऊपर, बीच में केसरिया और सबसे नीचे लाल रंग था. हरा रंग इस्लाम और केसरिया हिंदू एवं बौद्ध धर्म का प्रतीक कहा गया. हरे रंग की पट्टी में आठ कमल थे, जो ब्रिटिश हुकूमत के समय भारत के आठ प्रांतों को दर्शाते थे. लाल रंग की पट्टी पर चांद और सूरज बने हुए थे. इस तिरंगे को भीकाजी के साथ वीर सावरकर और श्याम जी कृष्ण वर्मा ने मिलकर बनाया था. 1917 में एक और झंडा आया, जिसे डॉ. एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने होम रूल लीग के आंदोलन के दौरान फहराया. इस ध्वज में एक के बाद एक 5 लाल और 4 हरी क्षैतिज पट्टियां थीं और सप्तऋषि को दर्शाने के लिए सात सितारे बने थे. इस झंडे के बाएं और ऊपरी किनारे पर यूनियन जैक था. साथ ही एक कोने में सफ़ेद अर्द्ध चंद्र और सितारा भी था. इसी तरह गदर पार्टी ने अपना झंडा निकाला और बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने मिलकर अपने ध्वज का इस्तेमाल किया. यह झंडा सबको मान्य था, पर इससे जो राजनीतिक संदेश मिलता था, वह ज़्यादा लोकप्रिय नहीं था.

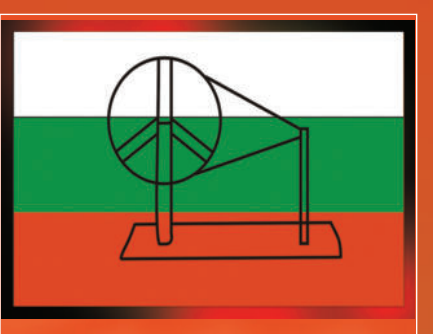

1916 में पहली बार कांग्रेस ने एक ध्वज का निर्माण करने का फ़ैसला किया. यह कार्य आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम के लेखक पिंगली वैंकैया को सौंपा गया. महात्मा गांधी ने उन्हें ध्वज में चरखा इस्तेमाल करने की हिदायत दी. वैंकैया ने खादी का ध्वज बनाया और उसमें लाल व हरे रंग की पट्टियों पर चरखा लगाया. महात्मा गांधी का मानना था कि लाल व हरा रंग तो हिंदू और मुस्लिम समुदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के लिए सबसे ऊपर सफ़ेद रंग भी जोड़ा जाए. इस ध्वज को 1917 में होम रूल आंदोलन के दौरान अपनाया गया. इसे कांग्रेस के अहमदाबाद सम्मेलन में फ़हराया गया, किंतु यह झंडा कांग्रेस का आधिकारिक झंडा नहीं बन सका. बहुत से लोग झंडे की सांप्रदायिक व्याख्या से नाख़ुश थे. कई संगठनों ने राय दी कि गेहुंआ रंग हिंदू संन्यासी और मुस्लिम फ़कीर दोनों का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए झंडे में यह रंग होना चाहिए. इसके बाद सिख भी झंडे में पीले रंग को अपनाने की जिद करने लगे. 1931 में कांग्रेस की कार्यकरिणी ने सात सदस्यीय कमेटी का गठन करने का निर्णय किया, जिसमें सरदार पटेल, नेहरू, मौलाना आज़ाद, मास्टर तारा सिंह, काका कालेलकर, डॉ. हार्डिकर एवं पट्टाभी सीतारमैया जैसे दिग्गज शामिल थे. इस कमेटी ने केसरिया रंग के झंडे का निर्माण किया, जिसमें ऊपर चरखा बना हुआ था.

राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास में 1931 एक यादगार वर्ष है. तिरंगे ध्वज को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया. 1931 का ध्वज सही मायने में तिरंगे का पूर्वज है. 1931 में ही कराची में फिर कमेटी बैठी और पिंगली वैंकैया को फिर कमान सौंपी गई. इस झंडे में केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग की पट्टी थी और मध्य में चलता हुआ चरखा था. इस झंडे को अपनाने के दौरान यह स्पष्ट रूप से बताया गया कि इसका कोई सांप्रदायिक महत्व नहीं है. इस ध्वज को 1931 में गैर आधिकारिक रूप से अपनाया गया. स्वतंत्रता प्राप्ति के 24 दिनों पहले आनन-फ़ानन में एक कमेटी गठित की गई, जिसकी अध्यक्षता डॉ. राजेंद्र प्रसाद को दी गई. इस कमेटी के सदस्य सी राजगोपालाचारी, सरोजिनी नायडू, अबुल कलाम आज़ाद, के एम मुंशी एवं बी आर अंबेडकर थे. इस झंडे को स्वीकृति मिली और यही झंडा आज का तिरंगा बना.

“यह ध्वज आज़ादी और कॉमरेडशिप का संदेश देगा. यह संदेश कि भारत विश्व के सभी देशों के साथ मित्रता करना चाहता है और उन सभी देशों की मदद करना चाहता है, जो ग़ुलामी की ज़ंजीर से आज़ाद होने की इच्छा रखते हैं.”

-पंडित जवाहर लाल नेहरू

“इस राष्ट्रीय ध्वज के नीचे खड़े लोगों में राजा और रंक, सामंत और किसान, पुरुष और महिला के बीच किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है. मैं निवेदन करती हूं कि सभी खड़े होकर इस ध्वज को सलाम करें.”

-सरोजिनी नायडू

ध्वज संहिता

26 जनवरी, 2002 को भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया गया और स्वतंत्रता के कई वर्षों बाद भारतीय नागरिकों को अपने घरों, कार्यालयों और फैक्ट्रियों में न केवल राष्ट्रीय दिवसों पर, बल्कि किसी भी दिन बिना किसी रुकावट के तिरंगा फहराने की अनुमति मिल गई. अब भारतीय नागरिक राष्ट्रीय झंडे को शान से कहीं भी और किसी भी समय फहरा सकते हैं. बशर्ते, वे ध्वज संहिता का कठोरतापूर्वक पालन करें और तिरंगे की शान में कोई कमी न आने दें. सुविधा की दृष्टि से भारतीय ध्वज संहिता, 2002 को तीन भागों में बांटा गया है. संहिता के पहले भाग में राष्ट्रीय ध्वज का सामान्य विवरण है. दूसरे भाग में जनता, निजी संगठनों, शैक्षिक संस्थानों आदि के सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन के विषय में बताया गया है. संहिता का तीसरा भाग केंद्रीय और राज्य सरकारों, उनके संगठनों एवं अभिकरणों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन के विषय में जानकारी देता है.

क्या करें

राष्ट्रीय ध्वज को शैक्षिक संस्थानों (विद्यालयों, महाविद्यालयों, खेल परिसरों, स्काउट शिविरों आदि) में सम्मान देने की प्रेरणा देने के लिए फहराया जा सकता है. विद्यालयों में ध्वजारोहण में निष्ठा की एक शपथ शामिल की गई है. किसी सार्वजनिक, निजी संगठन या एक शैक्षिक संस्थान के सदस्य द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का आरोहण/प्रदर्शन सभी दिनों, अवसरों और आयोजनों पर अथवा राष्ट्रीय ध्वज के मान-सम्मान और प्रतिष्ठा के अनुरूप अवसरों पर किया जा सकता है. नई संहिता की धारा 2 में सभी नागरिकों को अपने घरों-परिसरों में ध्वज फहराने का अधिकार देना स्वीकार किया गया है.

क्या न करें

इस ध्वज को सांप्रदायिक लाभ, पर्दे या वस्त्रों के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. जहां तक संभव हो, इसे मौसम से प्रभावित हुए बिना सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाना चाहिए. इस ध्वज को आशयपूर्वक भूमि, फर्श या पानी से स्पर्श नहीं कराया जाना चाहिए. इसे वाहनों के हुड, ऊपर और बगल या पीछे, रेलों, नावों या वायुयान पर लपेटा नहीं जा सकता. किसी अन्य ध्वज या ध्वज पट्ट को हमारे ध्वज से ऊंचे स्थान पर लगाया नहीं जा सकता है.

“यह ध्वज हमें बताता है कि जब भी कोई क़दम बढ़ाएं, हमेशा सतर्क रहें. एक मुक्त, स्थिति के अनुरूप ढलने वाले, संवेदनशील, मर्यादित और लोकतांत्रिक समाज के लिए काम करें, जिसमें ईसाई, सिख, मुस्लिम, हिंदू और बौद्ध धर्म के लोग सुरक्षित आश्रय पाएं.”

-डॉ. एस राधाकृष्णन

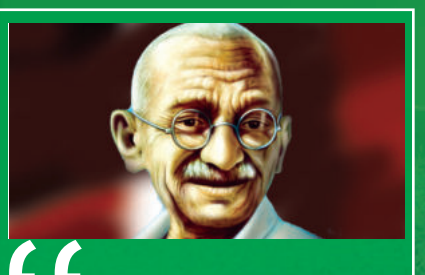

“मैं यह कहना चाहूंगा कि भारत देश के झंडे में यदि राष्ट्रीय चिन्ह के तौर पर चरखा न हो तो मैं उसे सलाम नहीं करूंगा. आप जानते हैं कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का ख्याल सबसे पहले मेरे मस्तिष्क में आया और मैं भारत के राष्ट्रीय ध्वज की कल्पना चरखे के बिना नहीं कर सकता.”

-महात्मा गांधी

ritika@chauthiduniya.com

संत पूर्णानंद के अनशन ने उसके इस आरोप का भी जवाब दे दिया है. मातृ सदन के इस सत्याग्रही संत के चेहरे पर ग़ज़ब का तेज और आत्मविश्वास झलक रहा है.

उत्तराखंड

पूर्णानंद दिलाएंगे निगमानंद के हत्यारों को सज़ा

राजकुमार शर्मा

धर्मनगरी हरिद्वार में गंगा और पर्यावरण की रक्षा की मांग को लेकर शहादत देने वाले युवा संत निगमानंद की समाधि की मिट्टी अभी सूखी भी नहीं थी कि मातृ सदन के दूसरे युवा संत स्वामी पूर्णानंद सरस्वती ने अपने गुरुभाई की मौत के लिए ज़िम्मेदार लोगों को सज़ा दिलाने और गंगा रक्षा के संकल्प के साथ सत्याग्रह शुरू कर दिया. गंगा की रक्षा के लिए मातृ सदन अब तक दो शहादत दे चुका है. पहले उसने संत स्वामी गोकुलानंद को खोया, जो कालीढूंगी के जंगलों में मृत पाए गए थे. वह अपने गुरु की भावना के अनुरूप गंगा की रक्षा के लिए सत्याग्रह करके अर्से से खनन माफ़िया की आंखों की किरकिरी बने हुए थे. इसके बाद युवा संत निगमानंद ने अपनी जान दे दी. वह गंगा में हो रहे अवैध खनन के मामले को लेकर बीती 19 फरवरी से अनशन पर थे. खनन माफ़ियाओं ने एक महिला स्वास्थ्यकर्मी (नर्स) को माध्यम बनाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया. इस नर्स ने इलाज के नाम पर निगमानंद को ज़हर का इंजेक्शन दे दिया. इसके बाद निगमानंद कोमा में चले गए और अनशन के 115वें दिन उनका निधन हो गया.

राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ. हरक सिंह रावत ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान संत निगमानंद को ज़हर देने का आरोप लगाते हुए निशंक सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था, लेकिन सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगी. इस मामले को मुख्यमंत्री ने पूरी तरह अनसुना कर दिया. जनता के हितों के लिए किए जाने वाले विभिन्न आंदोलनों से संत निगमानंद का गहरा नाता रहा है. इससे पहले भी वह दो बार अनशन कर चुके थे. उन्हें कतई पता नहीं था कि उनका यह अनशन उनके लिए काल सिद्ध होगा. अभी तक उनके हत्यारों के ख़िलाफ़ कोई ठोस कार्रवाई न होते देखकर उनके गुरुभाई एवं युवा संत स्वामी पूर्णानंद सरस्वती ने सत्याग्रह के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया. अनशन के तीसरे दिन उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष यशपाल आर्या, जयराम संस्थाओं के दिव्यपीठाधीश्वर ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी एवं अन्य कांग्रेसियों ने मातृ सदन पहुंच कर उनका समर्थन किया. कांग्रेस इस प्रकरण पर पहले भी ज़िला स्तर पर धरना-प्रदर्शन कर चुकी है.

मुख्यमंत्री निशंक ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की घोषणा की थी, जो अभी तक हवा-हवाई सिद्ध हुई. आर्या ने कहा कि सूबे में संत विरोधी सरकार काम कर रही है, जिसका खनन माफ़ियाओं से गहरा नाता है. उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति रहे ब्रह्मचारी का आरोप है कि राज्य सरकार धर्म, संस्कृत और संस्कृति विरोधी आचरण में संलिप्त है और संत विरोधी हरकतें कर रही है. हरक सिंह रावत का मानना है कि सरकार ने इस मामले में जो थोड़ी-बहुत कार्रवाई की, वह भी सही दिशा में नहीं की. मुख्यमंत्री को सीबीआई जांच के लिए भारत सरकार के सचिव अथवा पीएमओ को पत्र भेजना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सीधे सीबीआई को लिख भेजा. इसी के चलते जांच आज तक शुरू नहीं हो पाई. रावत का मानना है कि सरकार एक ओर हरिद्वार में अवैध खनन बंद करने की बात करती है, वहीं इसके लिए संतों को अपनी कुर्बानी देनी पड़ रही है.

ज़िला प्रशासन मातृ सदन के संस्थापक संत शिवानंद सरस्वती पर युवा संतों को बरगला कर आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का आरोप लगाता रहा है. संत पूर्णानंद के अनशन ने उसके इस आरोप का भी जवाब दे दिया है. मातृ सदन के इस सत्याग्रही संत के चेहरे पर ग़ज़ब का तेज और आत्मविश्वास झलक रहा है. सत्याग्रह को हिंसा के ज़रिए कुचला नहीं जा सकता, मातृ सदन के इस तीसरे संत ने पुन: सत्याग्रह की राह पर चलकर यही बताने की कोशिश की है. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जब उत्तराखंड आए थे, उसी समय संत निगमानंद की शहादत हुई थी. गडकरी इस संत की समाधि पर न जाकर परिवार सहित प्रकृति का आनंद लूटते रहे और फिर वापस चले गए. पूर्व गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती कहते हैं कि निगमानंद के मामले में सरकार को सीबीआई जांच कराकर हत्यारों को सज़ा दिलाने में देरी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा अपराधी पकड़ से बाहर हो जाएंगे. उत्तरकाशी के गीतास्वामी दिव्यधाम के पीठाधीश्वर स्वामी कमलेशानंद सरस्वती का कहना है कि संत निगमानंद की मौत के लिए ज़िम्मेदार लोगों की शीघ्र गिरफ्तारी होनी चाहिए और साथ ही गंगा को खनन माफ़ियाओं के चंगुल से आज़ाद कराने के लिए ठोस क़दम उठाए जाने चाहिए.

feedback@chauthiduniya.com

महाराष्ट्र

हर्षवर्द्धन को हाईकोर्ट की फटकार

युधिष्ठिर जोशी

मुंबई हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एस सी धर्माधिकारी ने सहकारिता मंत्री हर्षवर्धन पाटिल के होश उड़ा दिए हैं. सिर्फ़ हर्षवर्धन पाटिल ही ऐसे मंत्री नही हैं. अगर आप मंत्रियों के वातानुकूलित कक्ष के पास से गुजरें तो आपको हर जगह एक जैसा अनुभव होगा. अधिकतर मंत्री विलासी प्रवृत्ति के होते हैं. उनकी इस प्रवृत्ति से आम आदमी अचंभित और हैरान-परेशान होता है, परंतु सत्ताधीशों को इस संदर्भ में कोई अफसोस नहीं होता. यदि कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति किसी कारण उनके सामने अधिक देर तक खड़ा रहे तो चिड़चिड़ाहट उनके चेहरे पर साफ नज़र आने लगती है. इस संबंध में आम आदमी क्या सोचता है, इसकी उन्हें ज़रा भी परवाह नहीं होती. आम आदमी के काम भी अधिकतर साधारण होते हैं, लेकिन अधिकारी-कर्मचारी जानबूझ कर उनके काम में अड़ंगे डालते हैं. ऐसे में भुक्तभोगी के पास संबंधित मंत्रालय और मंत्री की शरण में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता. ऐसा भी नहीं है कि मंत्रियों के दरबार में उसे न्याय मिल ही जाता हो. यह बात अलग है कि ग्रामीण सीधे-सादे होते हैं, ज़्यादा चालाक नहीं होते, लेकिन हमेशा उनकी बात सुने बिना टालमटोल करके आगे निकल जाना भी न्याय नहीं है. नैसर्गिक न्याय आम आदमी का अधिकार है. अगर वह सत्ताधीशों से अपमानित होकर न्यायालय की तरफ़ भागता है और अदालत मंत्री विशेष पर मुकदमा चलाने का आदेश देती है तो सरकार हाय-तौबा करने लगती है कि अदालत अपनी सीमा पार कर रही है. ऐसा ही हुआ हर्षवर्द्धन पाटिल के मामले में.

हर्षवर्धन पाटिल के सामने सहकारिता विभाग से संबंधित मामले आते हैं. यह रोज की बात है. फरियादी अपने वकील से विचार-विमर्श कर अपना पक्ष उनके सामने रखता है. एक दिन 46 मामलों की सुनवाई होनी थी. दोपहर 2 बजे का समय दिया गया था, लेकिन मंत्री डेढ़ घंटे देर से आए. आते ही उन्होंने शिकायतकर्ताओं से कहा कि आज समय कम है, इसलिए आप एक-एक मिनट में अपनी बात कह सकते हैं. जैसे स्कूल में बच्चों की हाजिरी ली जाती है, वैसे ही 46 मामलों का निपटारा पाटिल ने एक झटके में कर दिया. मंत्री का ऐसा न्याय देखकर शिकायतकर्ता अचंभित रह गए. एक शिकायतकर्ता ने मंत्री के इस रवैये के ख़िलाफ़ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया. अदालत ने उसकी पूरी बात सुनी और नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि शिकायतकर्ताओं की सुनवाई करने की यह कोई नैसर्गिक न्याय प्रक्रिया नहीं है. यदि ऐसा होगा तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा. न्यायमूर्ति धर्माधिकारी ने मंत्रालय में होने वाली सुनवाई के तरीक़े के प्रति नाराजगी व्यक्त की. इस पर हर्षवर्धन पाटिल ने सफाई दी कि उस दिन पुणे में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था और वहां उपस्थिति अनिवार्य होने की वजह से वह सुनवाई के लिए ज़्यादा समय नहीं दे सके.

अब सवाल यह उठता है कि अगर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था भी, तो वह कम से कम सप्ताह भर पहले तय किया होगा. ऐसे में सुनवाई टाली जा सकती थी या फिर अगर देर से शुरू भी हुई तो उसे पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए था. दूसरी बात यह है कि मंत्रालय कोई भी हो, संबंधित मंत्रियों, उनके सचिवों के आसपास परिचितों और उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोगों का जमावड़ा लगा रहता है. चूंकि जमावड़े का हर सदस्य मंत्री से चिपका रहता है, इसलिए उनसे पूरा स्टाफ परिचित रहता है. इस बीच अगर गड़चिरोली, कोंकण या सोलूर-सांगली से कोई ज़रूरतमंद आदमी आ जाता है तो उस पर मंत्रियों की चमचामंडली टूट पड़ती है. यह एक कटु सत्य है. मंत्रालय में जो मंत्री बैठे हैं, वे केवल अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए नहीं हैं, उन पर 288 विधानसभा क्षेत्रों की जवाबदेही है, लेकिन पिछले 15-20 सालों से मंत्रियों ने अपने दायित्व भुला दिए हैं. यह राज्य का दुर्भाग्य नहीं तो क्या है? अपने निर्वाचन क्षेत्र का लालन-पालन और संवर्धन करना चाहिए, लेकिन शेष 287 निर्वाचन क्षेत्रों की उपेक्षा करके नहीं. मंत्रियों के एंटी चेंबर्स सिर्फ़ बातें करने के लिए नहीं हैं.

हर्षवर्धन पाटिल के सामने सहकारिता विभाग से संबंधित मामले आते हैं. यह रोज की बात है. फरियादी अपने वकील से विचार-विमर्श कर अपना पक्ष उनके सामने रखता है. एक दिन 46 मामलों की सुनवाई होनी थी. दोपहर 2 बजे का समय दिया गया था, लेकिन मंत्री डेढ़ घंटे देर से आए. आते ही उन्होंने शिकायतकर्ताओं से कहा कि आज समय कम है, इसलिए आप एक-एक मिनट में अपनी बात कह सकते हैं.

मंत्रालय में मंत्रियों की उपस्थिति भी एक बड़ा सवाल है. वे बुधवार को कैबिनेट की बैठक के पूर्व मंत्रालय जाते हैं और फिर एक दिन बाद. क्या राज्य सरकार ने कामकाज निपटाने के लिए मात्र 3 दिनों का सप्ताह तय किया है? उत्पाद शुल्क मंत्री गणेश नाईक और अन्न एवं औषधि विभाग के मंत्री मनोहर नाईक मंत्रालय के सामने स्थित अपने बंगलों से अपना कारोबार संभालते हैं, वे सिर्फ़ कैबिनेट की बैठक के लिए मंत्रालय की सीढ़ियां चढ़ते हैं. ये दोनों मंत्री राष्ट्रवादी कांग्रेस के हैं. पिछले 12 सालों में मनोहर नाईक विधानसभा में कितनी बार बोले होंगे, यह शोध का विषय है. मंत्रालय में मंत्रियों की अनुपस्थिति एक गंभीर मुद्दा है और इस पर अंकुश लगना ज़रूरी है. सरकार में शामिल राजनीतिक दलों द्वारा अपने मंत्रियों को इस बारे में सख्त हिदायत दी जानी चाहिए, लेकिन कोई भी दल ऐसा करता नज़र नहीं आता. मनोहर नाईक बंजारा समाज के हैं और बंजारा समाज का समर्थन राकांपा को मिलता रहा है. कहीं यह समर्थन हाथ से फिसल न जाए, इसलिए अखिल भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार अपने चहेते मनोहर नाईक को जरा भी नाराज़ नहीं करना चाहते.

feedback@chauthiduniya.com

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चार जिलों अलीगढ़, मथुरा, हाथरस और आगरा के 850 गांवों की लाखों हेक्टेयर कृषि भूमि को एक्सप्रेस-वे परियोजना के लिए अधिग्रहण संबंधी कार्रवाई का किसानों ने क्रमबद्ध विरोध दर्ज करना शुरू कर दिया है.

क़िस्मत के मारे किसान

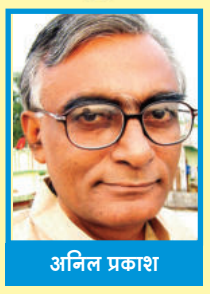

अनिल प्रकाश

राज्य सरकार के कृषि विभाग के अधिकारियों ने आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से बड़ी-बड़ी कंपनियों के मूंग के बीज मंगवा कर किसानों के बीच उनका मुफ्त वितरण कराया. साथ ही खाद, कीटनाशक एवं खरपतवार नाशक भी वितरित किए गए. पौधे ख़ूब लहलहाए, उन्हें देखकर किसान हर्षित थे, लेकिन उन पौधों में दाने नहीं आए. जिन किसानों ने राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा-समस्तीपुर के एसएमएल- 668 और सोना नामक बीज या अपने स्थानीय बीजों का प्रयोग किया, उनके पौधों में ख़ूब दाने आए. मुज़फ्फरपुर ज़िले के एक हज़ार किसान आज रो रहे हैं. मधुबनी, दरभंगा, सुपौल एवं बक्सर के किसानों ने बताया कि उनके यहां भी मूंग की फ़सल में दाने नहीं आए. राज्य के कृषि विभाग को अपनी इस नाकामी की पूरी जानकारी है, लेकिन वह छिपाने की कोशिश कर रहा है और किसानों की फ़सल क्षति का मुआवज़ा देने से भी इंकार कर रहा है. संयुक्त कृषि निदेशक राजेंद्र दास का कहना है कि रबी या खरीफ फ़सल में क्षतिपूर्ति अनुदान की व्यवस्था है, लेकिन गरमा फसल मूंग दाल में क्षतिपूर्ति की व्यवस्था सरकार ने नहीं की है. कृषि विभाग को किसने यह अधिकार दिया कि वह इतने बड़े पैमाने पर किसानों को अंधेरे में रखते हुए मूंग के बीज का ट्रायल कराए?

अभी कुछ महीने पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश को पत्र लिखकर ड्यूपौंट, पायोनियर एवं मोंसाटो आदि कंपनियों के बीजों के ट्रायल पर रोक लगवाने के लिए पत्र लिखा था. मक्के के बीज का ट्रायल रुक भी गया. नीतीश कुमार ने पत्र में लिखा था कि इन कंपनियों के जीएम एवं हाइब्रिड बीजों के कारण मक्के के पौधों में दाने नहीं आए थे, इनसे खेती बर्बाद होती है. हालांकि नीतीश कुमार ने उन कंपनियों को न तो काली सूची में डाला और न उन पर जुर्माना लगवाया. सच तो यह है कि ड्यूपौंट की सब्सिडियरी कंपनी पायनियर के महंगे धान के बीजों और अन्य कंपनियों के गेहूं और दलहन बीजों को भारी सब्सिडी देकर राज्य का कृषि विभाग किसानों को इन बीजों का वितरण करा रहा है. क्या यह नीतीश कुमार की जानकारी में नहीं है, क्या नीतीश कुमार इसके लिए ज़िम्मेदार लोगों को दंडित कराएंगे?

मक्के की बर्बादी

वर्ष 2010 में यहां के किसानों ने लगभग दो लाख एकड़ में ड्यूपौंट की सब्सिडियरी पायोनियर के पायोनियर-92, डी काल्ब कंपनी की सब्सिडियरी लक्ष्मी के लक्ष्मी डी काल्ब-198 और पिनकोल जैसी कंपनियों के बीजों का प्रयोग किया था, लेकिन उनमें दाने नहीं आए. किसानों ने इन बीजों को 180 रुपये से लेकर 285 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से ख़रीदा था. खाद, बीज, सिंचाई और मेहनताना सब मिलाकर लगभग 10 हज़ार रुपये प्रति एकड़ की लागत आई थी यानी 25 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की लागत. 80 प्रतिशत किसानों ने महाजनों से 5 रुपये प्रति सैकड़ा प्रति माह की दर से क़र्ज़ लेकर यह खेती की थी. उन्हें कंपनियों के एजेंटों ने यह भरोसा दिलाया था कि फ़सल इतनी होगी कि वे मालामाल हो जाएंगे. जिन किसानों ने राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा, सबौर कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर या पतंग नगर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित बीजों और रबी हाईस्टार्च, गंगा इलेवन, त्रिसुप्ता हेमंत, देवकी, राजेंद्र संकर मक्का-12, वसंती, गरमा सुआन या दियारा कंपोजिट, गंगा सफेद-2 या स्थानीय बीजों का प्रयोग किया था, उनमें दाने भरपूर आए थे.

शुरू में राज्य कृषि विभाग के अधिकारी एवं तत्कालीन कृषि मंत्री रेणु देवी ने मक्के के पौधों में दाना न आने की बात को ही झुठला दिया. बड़ी जद्दोज़हद के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में स्वीकार किया था कि 63 हज़ार हेक्टेयर (1 लाख 59 हज़ार एकड़) में मक्के की फ़सल में दाने नहीं आए. सरकार ने 10 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवज़ा देने की घोषणा की थी. यह रकम लागत से आधी से भी कम थी, जबकि मुआवज़ा लागत के अतिरिक्त फ़सल की संभावित उपज के मूल्य के आधार पर दिया जाना चाहिए था. काफी किसानों को वह मुआवज़ा नहीं मिला. बटाईदार को तो एक पाई भी नहीं मिली. कृषि विभाग के जो अधिकारी इन बीजों के प्रयोग की छूट देने के लिए ज़िम्मेदार थे, उन्हें दंडित किया जाना चाहिए था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. ड्यूपौंट, मोंसाटो एवं डी काल्ब जैसी विशालकाय कंपनियां अपने टर्मिनेटर और हाईब्रिड बीजों के सहारे बाज़ार पर क़ब्ज़ा करना चाहती हैं. इन कंपनियों की वैश्विक आय का आधा खरपतवार नाशकों एवं अन्य रसायनों से आता है. ये कंपनियां राजनेताओं, नौकरशाहों एवं कृषि वैज्ञानिकों के एक तबके को बड़े पैमाने पर आर्थिक लाभ पहुंचा कर अपने पक्ष में फ़ैसला कराने के लिए दुनिया भर में कुख्यात हैं. मक्के से शराब और एथनॉल बनाने में सहूलियत हो, इसके लिए जीएम बीजों का प्रयोग बढ़ाने की कई साजिशें पिछले एक दशक में उजागर हुई हैं. जीएम बीजों से उत्पादित अनाज खाने से बीमारियों की आशंका रहती है, इसलिए अमेरिका में इस प्रकार के अनाज का इस्तेमाल शराब और एथनॉल बनाने में किया जाता है. हालांकि इससे वैश्विक खाद्य संकट पैदा हो गया है.

बिहार में मक्का और दुर्लभ फल लीची से शराब बनाई भी जाने लगी है. पिछले साल एक हज़ार एकड़ में लगी लीची के हरे-भरे कच्चे फलों को तोड़कर शराब बनाई गई और इस साल तीन हज़ार एकड़ में लगी लीची की शराब बनाई गई. सरकार ने इसकी इजाज़त दी. काफी लोग इसके विरोध में खड़े हैं और कहते हैं कि मक्के को अनाज, पशुचारा और ग्लूकोज आदि बनाने के काम में लाया जाए. लीची से स्क्वैश बने, शराब नहीं. आलू के लिए कोल्ड स्टोरेज बनें. इसका उपयोग सब्जी और चिप्स बनाने में हो, शराब बनाने में नहीं. राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय एवं सबौर कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विभिन्न इलाक़ों की मिट्टी के अनुकूल बीजों की तलाश एवं शोध करके उन्हें विकसित किया है, जिनकी प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बड़ी कंपनियों के बीजों से ज़्यादा है. विडंबना यह है कि राज्य का कृषि विभाग इन बीजों को किसानों के बीच वितरित करने में बहुत कम दिलचस्पी लेता है. भारी सब्सिडी देकर बड़ी-बड़ी देसी-विदेशी कंपनियों के महंगे बीजों को बेचा या मुफ्त में बांटा जाता है. इस बात की गारंटी भी नहीं होती कि इन पौधों में दाने निकलेंगे भी या नहीं.

जिस पायोनियर ड्यूपौंट के मक्के के बीज से पिछले साल लगभग दो लाख एकड़ में लगे पौधों में दाने नहीं आए थे, उसी कंपनी के धान के महंगे बीज भारी सब्सिडी देकर बिकवाए गए. कई जगह गेहूं में क्रौप फेल्योर की शिकायत आ रही है. राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा के पास 15-20 प्रकार के धान के बीज हैं. भगवती नामक एक सुगंधित धान भी है, जिसकी पैदावार 24 क्विंटल प्रति एकड़ होती है. मूंग, अरहर मसूर, चना, मक्का एवं गेहूं के बेहतर बीज भी उपलब्ध हैं, लेकिन इस विश्वविद्यालय के केवल 4 हज़ार क्विंटल बीजों का प्रयोग कराया गया है. पिछले वर्ष की तुलना में कृषि क्षेत्र के लिए योजना व्यय की राशि दोगुनी कर दी गई है. इस साल का हिस्सा 846 करोड़ 86 लाख रुपये है, लेकिन इस राशि का ज़्यादा हिस्सा बीज कंपनियों को मिल जाता है और किसान रोते हैं. पिछले 6 वर्षों में यह साबित हो गया है कि कृषि और उससे जुड़े छोटे उद्योग ही बिहार की तकदीर बदल सकते हैं. 24 हज़ार करोड़ के योजना व्यय में कृषि का हिस्सा बहुत कम है, लेकिन उसका फ़ायदा किसानों को कैसे पहुंचे, यह देखना सरकार का काम है, क्योंकि आज भी बिहार की 88 फ़ीसदी आबादी गांवों में रहती है.

feedback@chauthiduniya.com

अब यमुना एक्सप्रेस-वे के ख़िलाफ़ शंखनाद

ग्रेटर नोएडा मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा किसानों को राहत मिलने के बाद अब यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण से प्रभावित किसानों ने भूमि अधिग्रहण को लेकर आंदोलन का शंखनाद कर दिया है. नतीजतन नोएडा विस्तार की तरह यमुना एक्सप्रेस-वे पर बसाई जा रही एशिया की सबसे बड़ी शहरी बस्ती पर ख़तरे के बादल मंडराने लगे हैं. अट्टा गुजरान गांव में 45 गांवों के किसानों ने एक महापंचायत की, जिसमें ज़मीन अधिग्रहण के ख़िलाफ़ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का निर्णय लिया गया. इस प्राधिकरण ने 2008 में किसानों की ज़मीन यमुना एक्सप्रेस-वे बनाने के लिए अधिग्रहीत की थी. ज़मीन के दाम किसानों को तो 850 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से दिए गए, लेकिन जब यही ज़मीन जेपी समूह से साठगांठ करके उद्योग लगाने और बस्ती बसाने के लिए बड़े उद्योगपतियों एवं कालोनाइजरों को दी गई तो 11,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बिकी. जब किसानों ने ज़मीन का उपयोग बदले जाने को लेकर प्राधिकरण में आपत्तियां दर्ज कराने का प्रयास किया तो उन्हें सुनना भी उचित नहीं समझा गया. अब किसान पंचायत ने फ़ैसला लिया है कि नोएडा से आगरा जाने वाले महामार्ग के अलावा उद्योग और नगर बसाने के लिए एक इंच ज़मीन नहीं दी जाएगी.

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चार ज़िलों अलीगढ़, मथुरा, हाथरस और आगरा के 850 गांवों की लाखों हेक्टेयर कृषि भूमि को एक्सप्रेस-वे परियोजना के लिए अधिग्रहण संबंधी कार्रवाई का किसानों ने क्रमबद्ध विरोध दर्ज करना शुरू कर दिया है. दरअसल यमुना एक्सप्रेस-वे के नाम पर औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना 2008 में जारी की थी. योजना से हाथरस ज़िले के 300, अलीगढ़ के 105, मथुरा के 183 और आगरा के 171 गांव प्रभावित हुए हैं. यदि इस योजना पर अमल होता है तो कई गांव पूरी तरह नेस्तनाबूद हो जाएंगे, क्योंकि इन्हीं चार ज़िलों की उपजाऊ भूमि राज्य सरकार आवासीय और महामार्ग योजनाओं के लिए पहले ही हथिया चुकी है. अब 850 गांवों की कृषि भूमि यमुना एक्सप्रेस मार्ग के बहाने हड़पने की तैयारी है. गांव और किसानों को उजाड़ने वाली भूमि अधिग्रहण की इतनी बड़ी कार्रवाई इससे पहले कभी किसी राज्य में नहीं हुई. यह क्षेत्र आलू की उम्दा किस्म की पैदावार के लिए जाना जाता है और आलू की थाली कहा जाता है. यदि इस मार्ग के निर्माण और उद्योग एवं कालोनी बनाने के मकसद में राज्य सरकार सफल हो जाती है तो गंगा-यमुना का यह दोआब प्रदेश कृषि के मानचित्र से विलुप्त हो जाएगा. इसलिए किसानों ने अपना वजूद बचाने की लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है.

बावजूद इसके प्रदेश सरकार ख़ामोश है. वह उस रिलायंस पॉवर प्रोजेक्ट से भी सबक लेने को तैयार नहीं है, जिसके लिए किसानों से जबरन भूमि छीन ली गई थी. इस भूमि अधिग्रहण के परिणामस्वरूप किसान आंदोलित हुए और उन्होंने मुलायम सिंह सरकार को सत्ता से बेदखल करके ही दम लिया था. अब तक रिलायंस की बिजली परियोजना की बुनियाद नहीं रखी जा सकी है. अलबत्ता रिलायंस ने उस भूमि पर आवासीय बस्ती बनाए जाने की परिकल्पना ज़रूर शुरू कर दी है. यह भी ख़ुलासा हुआ है कि इस ऊर्जा परियोजना के संयंत्र लगाने के लिए केवल ढाई सौ हेक्टेयर ज़मीन पर्याप्त थी, जबकि दस हज़ार हेक्टेयर भूमि अधिग्रहीत की गई. लिहाज़ा ज़रूरी है कि भूमि का स्वरूप बदल कर आवासीय बस्ती बनाकर रिलायंस समूह करोड़ों-अरबों के वारे-न्यारे करने का जो मंसूबा पाले हुए है, उस पर अदालत के दख़ल से अंकुश लगे. यमुना एक्सप्रेस-वे की तरह ही उत्तर प्रदेश सरकार की विनाशकारी प्रस्तावित परियोजना गंगा एक्सप्रेस हाइवे है. इसके तहत नोएडा और बलिया के बीच गंगा नदी के चौड़े पाट के बीचोबीच आठ कतारों वाली सड़क बनाई जानी है. यह परियोजना अमल में आती है तो दोआब क्षेत्र की 10 लाख 47 हज़ार वर्ग मीटर यानी 5863 हेक्टेयर भूमि डामरीकरण युक्त काली पट्टी में तब्दील हो जाएगी. इस कारण सिंधु-गंगा के इस दोआब क्षेत्र में कई तरह के पर्यावरणीय संकट खड़े हो जाएंगे. कृषि की दृष्टि से यह भूमि बेहद उपजाऊ है, क्योंकि गंगा और यमुना प्रति वर्ष बरसात में ताजी मिट्टी अपनी लहरों के साथ बहाकर लाती हुई इस दोआब क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से बिछाती रहती हैं. नतीजतन, इस क्षेत्र की उर्वरा शक्ति हर साल बहाल हो जाती है. इसके अलावा यहां सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता भी भरपूर है.

दरअसल इस योजना की पृष्ठभूमि में योजनाकारों की कुटिल औद्योगिक मंशा निहित है. इस मंशा के अनुसार, पांच सौ बड़े और सात छोटे उद्योगों को लगाना परियोजना का हिस्सा है, जिसमें भारी पूंजी निवेश की उम्मीद है. यदि यह योजना फलीभूत हो जाती है तो उद्योगों से अपशिष्ट के रूप में निकलने वाला मलबा पवित्र गंगा-यमुना को तो प्रदूषित करेगा ही, चिमनियों से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण फैलाने के साथ-साथ फ़सलों के लिए भी संकट बनेगा. गंगा-यमुना में मलबा भरते रहने से भविष्य में इनकी सतह उथली हो जाएंगी, नतीजतन कालांतर में बरसात के मौसम में ये नदियां अपना परंपरागत रास्ता भी बदल सकती हैं. अगर ऐसा होता है तो इनके मार्ग में आने वाले कई शहरों एवं कस्बों की आबादी बाढ़ का कहर झेलने को भी विवश होगी. अदूरदर्शिता और तात्कालिक लाभ के चलते वैसे भी हम जीवनदायी नदियों को संकट में डाल चुके हैं. अब यदि एक्सप्रेस हाइवे भी इन्हीं नदियों की धार में बना दिए जाते हैं तो इनका अस्तित्व ख़त्म होना तय है. कृषि की अनदेखी करके औद्योगिक विकास के नाम पर नदियों को चौपट करना विनाश को खुला आमंत्रण देना है. प्राकृतिक संपदा के रूप में नदियों को बचाए रखना हमारा राष्ट्रीय दायित्व होना चाहिए.

प्रमोद भार्गव
feedback@chauthiduniya.com

अन्ना टीम दिल्ली में बैठकर मीडिया और तकनीक के सहारे यह लड़ाई लड़ रही है. शायद सरकार को भी इस सच्चाई का पता है, तभी वह अन्ना टीम को अपने लिए एक बड़ा ख़तरा नहीं मान रही है.

जन लोकपाल

इस सर्वे का नतीजा क्या निकलेगा

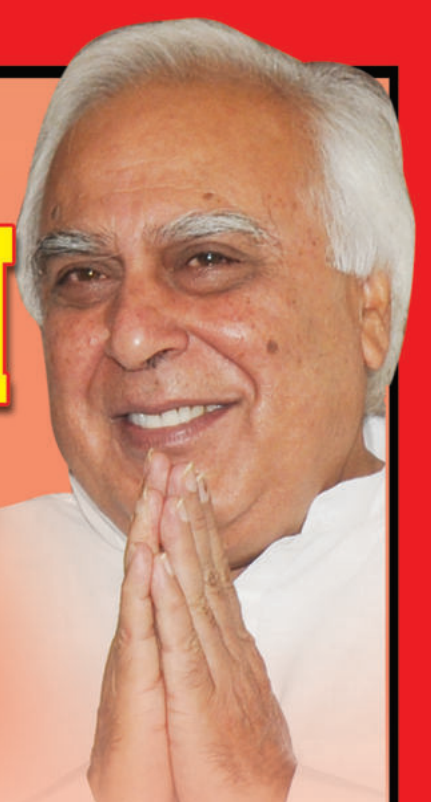

शशिशेखर

भारत में सर्वे अमूमन राजनीतिक पार्टियां या उपभोक्ता उत्पाद बेचने वाली कंपनियां करती हैं. मकसद साफ होता है, एक अपनी राजनीतिक ताक़त के आकलन के लिए तो दूसरा पैसा कमाने की संभावना तलाशने के लिए सर्वे कराता है. किसी जनांदोलन की ओर से सर्वे कराने की घटना शायद पहली बार देखने-सुनने को मिल रही है. दरअसल, जन लोकपाल के मुद्दे पर अन्ना हजारे की टीम ने दिल्ली के चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में एक सर्वे कराया है. चांदनी चौक इसलिए, क्योंकि इसी क्षेत्र से कपिल सिब्बल चुन कर आते हैं. सिविल सोसायटी (टीम अन्ना) के एक अहम सदस्य अरविंद केजरीवाल के मुताबिक़, सर्वे के लिए कपिल सिब्बल का चुनाव क्षेत्र इसलिए चुना गया, क्योंकि वह सरकार का चेहरा बन गए थे. दरअसल, कपिल सिब्बल ही वह सरकारी नुमाइंदे हैं, जो जन लोकपाल के मुखर विरोधी के तौर पर सामने उभर कर आए हैं. इस हिसाब से देखें तो इस सर्वे का सबसे महत्वपूर्ण मकसद कपिल सिब्बल को चेतावनी देना था या कहें कि सर्वे के परिणाम (जो अप्रत्याशित नहीं है) से सिब्बल और सरकार पर नैतिक दबाव बनाना था, लेकिन क्या सचमुच ऐसा हुआ?

बहरहाल, इस सर्वे परिणाम का नतीजा चौंकाता नहीं है. कारण, आख़िर वह कौन सी जनता होगी, जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर टीम अन्ना का साथ न दे या फिर टीम अन्ना द्वारा तैयार जन लोकपाल के प्रावधानों का समर्थन न करें. लेकिन घूम-फिर कर वही सवाल फिर से सिर उठाता है कि आख़िर इस सर्वे का नतीजा क्या निकलेगा? क्या इससे जन लोकपाल पास हो पाएगा? लोकपाल के मुद्दे पर जब ज्वाइंट ड्राफ्ट कमेटी की अंतिम बैठक हुई और जब यह साफ हो गया कि सरकार जन लोकपाल के महत्वपूर्ण प्रावधानों को नहीं मानने जा रही है, तब पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुरूप अन्ना हजारे ने घोषणा की कि वह 16 अगस्त से जंतर-मंतर पर आमरण अनशन पर बैठेंगे और इससे पहले जन लोकपाल के मुद्दे पर देशव्यापी भ्रमण करेंगे, ताकि आम लोगों को जागरूक किया जा सके, लेकिन अन्ना ने ऐसा नहीं किया. वह सिर्फ राले गांव सिद्धी तक सिमटे रहे या महाराष्ट्र में कुछ जगहों पर गए. दूसरी ओर अन्ना टीम के सदस्य अरविंद केजरीवाल देश के कुछ हिस्सों (कुछ राज्यों की राजधानियों) में जाकर ज़रूर कुछ मीटिंग वग़ैरह कर आए. लेकिन जैसा कि दावा किया गया था, अन्ना टीम एक बार फिर जन लोकपाल के मुद्दे पर जनता के बीच नहीं जा सकी. कुल मिलाकर जन लोकपाल का आंदोलन इंटरनेट और दिल्ली तक ही सिमटा रहा. मोबाइल पर मैसेज भेजकर युवाओं से चांदनी चौक में सर्वे के लिए स्वयंसेवक बनने का आग्रह किया गया. दरअसल, अन्ना टीम ने एक मौक़ा और गंवा दिया. उसके पास एक महीने का समय था, जिसका इस्तेमाल वह जन जागरण के लिए कर सकती थी, देशव्यापी दौरा करके लोकशक्ति का निर्माण कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया. ऐसा नहीं है कि जन लोकपाल के मुद्दे पर जनता जागरूक नहीं हुई है, लेकिन इसमें अन्ना टीम से ज़्यादा मीडिया की भूमिका रही है.

सर्वे परिणाम

चांदनी चौक में जनमत संग्रह के लिए चार लाख फॉर्म बांटे गए थे, जिसमें आठ सवाल थे. इसमें से 86 हज़ार लोगों ने अपने जवाब दिए. इस सर्वे परिणाम के लिए 72 हज़ार फॉर्म का अध्ययन किया गया. 14 हज़ार फॉर्म बारिश की वजह से गीले हो गए थे, जिन्हें इस परिणाम में शामिल नहीं किया गया. चांदनी चौक के 85 प्रतिशत मतदाता जन लोकपाल विधेयक के पक्ष में हैं. 82 फ़ीसदी लोग प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में रखना चाहते हैं. परिणाम के मुताबिक़, 85 प्रतिशत लोग चाहते हैं कि यदि नागरिकों के चार्टर का उल्लंघन हुआ तो दोषी अधिकारियों पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए और वह पैसा नागरिकों में मुआवज़े के रूप में लौटाया जाना चाहिए. 89 फ़ीसदी लोग मानते हैं कि सभी वर्ग के अधिकारियों को लोकपाल के दायरे में लाना चाहिए. 85 फ़ीसदी लोगों के मुताबिक़ हर राज्य में भी जन लोकपाल की तर्ज पर लोकायुक्त का गठन होना चाहिए, जबकि 88 फ़ीसदी यह मानते हैं कि संसद के भीतर सांसदों के आचरण की जांच का अधिकार लोकपाल को होना चाहिए. वहीं न्यायपालिका को लोकपाल के दायरे में लाने की वकालत करने वाले लोगों की संख्या 86 फ़ीसदी है. भ्रष्ट अधिकारियों को उनके पद से हटाने का अधिकार लोकपाल को होना चाहिए, ऐसा मानने वालों की संख्या 84 फ़ीसदी है. टीम अन्ना का कहना है कि चांदनी चौक के अलावा महाराष्ट्र के अमरावती में 98 प्रतिशत लोग जन लोकपाल का समर्थन कर रहे हैं, वहीं नागपुर में 81 प्रतिशत, वर्धा में 95 प्रतिशत लोग जन लोकपाल के समर्थन में हैं. इस सर्वे के बाद अन्ना टीम ने एक सवाल खड़ा किया है कि क्या लोकपाल विधेयक का सरकारी वर्जन सचमुच जनभावना का प्रतिनिधित्व करता है. दूसरी ओर कांग्रेस ने अन्ना को चांदनी चौक से चुनाव लड़ने की चुनौती दे डाली है. जबकि ख़ुद कपिल सिब्बल ने इस सर्वे रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुझे आश्चर्य है कि यह सिर्फ़ 85 फ़ीसदी ही क्यों है.

सर्वे परिणाम का नतीजा चौंकाता नहीं है. कारण, आख़िर वह कौन सी जनता होगी, जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर टीम अन्ना का साथ न दे या फिर टीम अन्ना द्वारा तैयार जन लोकपाल के प्रावधानों का समर्थन न करें. ऐसा लगता है कि इस सर्वे का मकसद कपिल सिब्बल को चेतावनी देना था या कहें कि सर्वे के परिणाम (जो अप्रत्याशित नहीं है) से सिब्बल और सरकार पर नैतिक दबाव बनाना था, लेकिन क्या सचमुच ऐसा हुआ? घूम-फिर कर वही सवाल फिर से सिर उठाता है कि आख़िर इस सर्वे का नतीजा क्या निकलेगा? क्या इससे जन लोकपाल पास हो पाएगा?

दरअसल, जन लोकपाल के मुद्दे पर 64 सालों से परेशान जनता के गुस्से का यह स्वत:स्फूर्त प्रकटीकरण है. अन्ना टीम दिल्ली में बैठकर मीडिया और तकनीक के सहारे यह लड़ाई लड़ रही है. शायद सरकार को भी इस सच्चाई का पता है, तभी वह अन्ना टीम को अपने लिए एक बड़ा ख़तरा नहीं मान रही है. एक और अहम मुद्दा है. अन्ना टीम यह घोषणा करती रही है कि उसकी यह लड़ाई जनता की लड़ाई है और व्यवस्था के ख़िलाफ़ है, न कि सरकार या किसी राजनीतिक दल के ख़िलाफ़. ऐसे में चांदनी चौक में सर्वेक्षण करा कर अन्ना टीम ने सीधे-सीधे राजनीति करने का ही काम किया है, सरकार के एक विशेष चेहरे (कपिल सिब्बल) पर निशाना साधने का काम किया है. डर इस बात का है कि कहीं अन्ना टीम की यह चाल उल्टी न पड़ जाए और जन लोकपाल को लेकर जनता की जो उम्मीदें अन्ना टीम से हैं, कहीं टूट न जाएं.

shashishekhar@chauthiduniya.com

मेरी दुनिया.... कर्नाटक और उत्तर प्रदेश

जंगल दुधवा का हो या राजा जी का, वन्यजीवों को अगर बचाना है तो इस बात का जवाब सरकार को देना होगा कि जिस जंगल में वनाश्रितों की मौजूदगी को अपराध के रूप में देखा जाता है.

हाथियों का हत्यारा कौन

रोमा

नेपाल सीमा से लगे उत्तर प्रदेश के जनपद खीरी के दुधवा नेशनल पार्क में पिछले दिनों बिजली के हाईटेंशन तारों के कारण एक साथ तीन हाथियों की दर्दनाक मौत हो गई. इस घटना में सबसे हृदय विदारक मौत उस गर्भवती हथिनी की हुई, जिसकी कोख से अपरिपक्व बच्चा बिजली के तेज़ झटके लगने के कारण मां के पेट से बाहर आ गया. हाथियों के झुंड का गुस्सा रास्ते के जंगल में लगे हाईटेंशन पोल पर तब उतरा, जब वे गांव में अपने भोजन की तलाश में गए थे. हाथी इन तारों की चपेट में आ गए और यह दर्दनाक हादसा घटित हो गया. यह पहला मौक़ा नहीं है, जब इस तरह की घटनाओं में हाथी मारे गए हों, लेकिन इस तरह की तमाम घटनाओं को महज़ हादसा मानकर लगातार नज़रअंदाज़ किया जाता रहा है.

अभी पिछले साल पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी ज़िले में रेल की चपेट में आकर एक साथ सात हाथियों की मौत हो गई थी. इसी तरह उत्तराखंड स्थित राजा जी नेशनल पार्क में देहरादून जाने के लिए बिछाई गयी रेल लाइन पर आएदिन हाथियों की मौत होती रहती है. यह सब घटनाएं तब घटित हो रही हैं, जब देश के ऐसे तमाम संरक्षित वन्य क्षेत्रों में विभिन्न बाघ और हाथी परियोजनाओं के तहत इन्हें बचाने के नाम पर हर साल करोड़ों रुपये पानी की तरह बहाए जा रहे हैं. ज़ाहिर है, ऐसी स्थिति में वन्यजीवों की हादसों में होने वाली हर मौत एक बड़ा सवालिया निशान छोड़ती है. उत्तर प्रदेश के दुधवा नेशनल पार्क को ही लें तो 1978 में इसकी स्थापना के समय से ही कहा जा रहा है कि पार्क के अंदर और इसके इर्द-गिर्द बसे थारू आदिवासी गांवों के लोगों को अगर खदेड़ दिया जाए, तभी यहां के बाघ और हाथी जैसे जंगली जानवरों को बचाया जा सकता है. हाथियों और बाघों के संरक्षण के लिए बनाई गई तमाम परियोजनाओं में इस बात पर खास ज़ोर दिया जाता है कि संबंधित वन्य क्षेत्रों से वहां बसे लोगों को हटा दिया जाए, तभी वन्य प्राणियों को बचाया जा सकेगा, लेकिन यहां सवाल यह है कि क्या ऐसा कर देने से इस बात की गारंटी मिल सकती है कि जंगलों के अंधाधुंध कटान के कारण वन्य जीव बिजली के तारों और जंगल में सरपट दौड़ने वाली रेलों की चपेट में आकर नहीं मरेंगे?

असल में यह वन विभाग और तथाकथित वन्यजीव-जंतु प्रेमियों द्वारा बड़े पैमाने पर फैलाया गया ऐसा सफेद झूठ है, जिसे बाहरी शहरी समाज भी सच के रूप में स्वीकार करता है. जबकि सच यह है कि आज देश के जंगलों और उनमें रहने वाले वनाश्रित समुदायों की दयनीय स्थिति की सबसे बड़ी ज़िम्मेदार सरकारें हैं, जिन्होंने विकास का पैमाना केवल अभिजात्य एवं मध्यम वर्ग को ध्यान में रखकर तय किया. जंगल दुधवा का हो या राजा जी का, वन्यजीवों को अगर बचाना है तो इस बात का जवाब सरकार को देना होगा कि जिस जंगल में वनाश्रितों की मौजूदगी को अपराध के रूप में देखा जाता है, उसमें से गुज़र कर आख़िर हाईटेंशन विद्युत तार क्यों जा रहे हैं? अगर जा भी रहे हैं तो आख़िर कहां? क्या इन लाइनों से जंगल में बसे गांवों को बिजली मुहैय्या कराई जा रही है या बड़े-बड़े प्रोजेक्टों और कारखानों को? जंगल के अंदर के गांवों की स्थिति का अगर जायज़ा लिया जाए तो इन तमाम गांवों में बिजली की व्यवस्था न होने के कारण सूरज डूबते ही इनकी ज़िंदगी अंधेरे में डूब जाने की वजह से एकदम ठहर जाती है. रोशनी भर के लिए भी इन्हें बिजली मुहैय्या नहीं कराई जाती. ऐसे में अगर विकास के नाम पर बिछाए गए इन बिजली के तारों और रेल लाइनों का विरोध किया जाए तो इन्हीं वन्यजीव-जंतु प्रेमियों और सरकार द्वारा तुरंत उसे विकास विरोधी होने की संज्ञा दे दी जाएगी.

विकास, विनाश और हाथी

लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में गुज़र कर जाने वाली शारदा नदी पर विशालकाय बांध और हाईडल प्रोजेक्ट बना दिए गए हैं, जिनके कारण हज़ारों हेक्टेयर खेती, रिहाइश और सामुदायिक इस्तेमाल की ज़मीनें डूब में आकर गर्क हो गई हैं. इससे भारत-नेपाल सीमा के जंगलों में होने वाली हाथियों की आवाजाही पर भी गहरा असर पड़ा है. जबकि हिमालय की तलहटी शिवालिक पहाड़ियों से लेकर तराई जंगलों का जम्मू से लेकर भूटान तक पूरा क्षेत्र हाथियों की आवाजाही का रास्ता है. पुराने समय से जंगली हाथियों द्वारा अपने आने-जाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है. हाथी अपने

लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में गुज़र कर जाने वाली शारदा नदी पर विशालकाय बांध और हाईडल प्रोजेक्ट बना दिए गए हैं, जिनके कारण हज़ारों हेक्टेयर खेती, रिहाइश और सामुदायिक इस्तेमाल की ज़मीनें डूब में आकर गर्क हो गई हैं. इससे भारत-नेपाल सीमा के जंगलों में होने वाली हाथियों की आवाजाही पर भी गहरा असर पड़ा है. जबकि हिमालय की तलहटी शिवालिक पहाड़ियों से लेकर तराई जंगलों का जम्मू से लेकर भूटान तक पूरा क्षेत्र हाथियों की आवाजाही का रास्ता है.

सामाजिक झुंड में भोजन की तलाश में इस कारीडोर में हजारों मील की यात्रा अपनी अनुवांशिक याद्दाश्त के सहारे करते हैं. एक हाथी को कम से कम 60 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की ज़रूरत होती है, जिसमें वह निर्बाध विचरण कर सके. लेकिन आज़ादी के बाद पिछले 60 सालों में इस पूरे कारीडोर में शहरों, शारदा-गंगा जैसी नदियों से नहरों एवं उन पर बिजली परियोजनाओं के विस्तार और लगातार बढ़ते घने ट्रैफिक के चलते अब हाथियों के लिए इन नदियों और शहरों को पार करके जंगलों में विचरण करना बहुत मुश्किल काम हो गया है. यही कारण है कि अपने प्राकृतिक विचरण क्षेत्र छिन जाने से वे लगातार हिंसक होते जा रहे हैं, लेकिन इसका खामियाजा उस शहरी समाज या सरकार को नहीं भुगतना पड़ता, जिनके अंधे लालच के कारण ये सारी परियोजनाएं लगाई जाती हैं, बल्कि इसका नुक़सान भी सदियों से वन्य क्षेत्रों में तमाम जंगली जानवरों के साथ सह अस्तित्व बनाकर रहने वाले उस वनाश्रित समाज को होता है, जिन्होंने हमेशा जंगल की रक्षा करके प्राकृतिक संतुलन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और जिन्हें कभी भी सरकार द्वारा देश की ग़रीब जनता पर थोपे गए तथाकथित विकास का लाभ नहीं मिलता. पिछले कुछ सालों में सरकारें विकास के नाम पर लगातार वनों को काटती रही हैं. एक-एक जंगल से हजारों पेड़ काटकर जंगलों को मरघट में तब्दील किया जाना आज भी जारी है. प्राकृतिक जंगलों का सर्वनाश करके उन्हें महज़ व्यवसायिक पेड़ों के जंगल में तब्दील कर दिया गया और यह सारी कहानी वन विभाग द्वारा ही बनाई गई तमाम कार्ययोजनाएं बयान करती हैं.

विकास की प्राथमिकता

इस तरह एकप्रजातीय पेड़ों का लगाना और प्राकृतिक जंगलों का सर्वनाश एक ही समय में साथ-साथ किया जाता रहा और हाथियों के लिए जंगल में खाने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा गया. नतीजतन वे भोजन की तलाश में गांवों और बस्तियों की ओर रुख़ करने लगे. जंगलों के भीतर लगातार बढ़ रहा मानव और वन्यजीव-जंतुओं के बीच का द्वंद्व सरकार द्वारा थोपे गए तथाकथित विकास और वन विभाग द्वारा बड़े पैमाने पर की गई लूट का ही नतीजा है. इसके ठीक उलट बड़े-बड़े तथाकथित पर्यावरणविद् एवं वन वैज्ञानिक इसका सारा दोष वनाश्रित समुदायों के सिर पर मढ़ते हैं और उन्हें वन्य क्षेत्रों से खदेड़ देना ही एकमात्र इलाज मानते हैं. 2006 में वनाधिकार क़ानून आ जाने के बावजूद यह लॉबी आज भी वनाश्रितों को 10 लाख रुपये का लालच देकर जंगल छोड़ने के लिए विवश करने की कोशिशों में लगी हुई है. वनाधिकार क़ानून के अनुसार, जंगलों में पीढ़ियों से बसे आदिवासियों और अन्य परंपरागत निवासियों को उनकी जोत, निवास और ग़लत तरीक़े से छिनी हुई ज़मीनों पर मालिकाना हक़ दिलाया जाना है. इसके अलावा जंगल से प्राप्त होने वाली तमाम वनोपज एवं सामुदायिक इस्तेमाल की ज़मीनों पर भी उनके अधिकारों का पुनर्स्थापन किया जाना है.

अगर तथ्यों को ग़ौर से देखा जाए तो पता चलता है कि जंगलों में लगातार हो रही वन्यजीव-जंतुओं की मौतों के लिए प्रशासन-सरकार और इनके द्वारा बनाई गई नीतियां ज़िम्मेदार हैं, न कि स्थानीय लोग. सरकार जंगलों के भीतर से हाईटेंशन विद्युत तारों और रेल पटरियों को हटाने की बात नहीं करती, लेकिन वह पीढ़ियों से इन जंगलों में रहने वाले नूर आलम, नूर जमाल एवं जहूर हसन जैसे हज़ारों वनगूजरों को हटाए जाने को ही जंगल और वन्य प्राणियों को बचाने का एकमात्र उपाय बताती है, लेकिन हक़ीक़त यह है कि जंगल में रहने वाले लोगों के कारण ही जंगल और जंगल के प्राणी बचे हुए हैं. राजा जी पार्क में करोड़ों रुपये की बावड़ियां सरकार द्वारा बनाई गई हैं, लेकिन जंगल में ये बावड़ियां कहीं नज़र नहीं आतीं, क्योंकि वे सिर्फ़ काग़ज़ों पर बनी हैं. यह तो भला हो वनगूजरों का, जिन्होंने अपने जानवरों के लिए पानी की बावड़ियां बनाई हुई हैं और उन्हीं पर हाथियों के झुंड भी जाकर अपनी प्यास बुझाते हैं. दरअसल जंगलों, वन्यजीवों और वनाश्रित समुदायों के लिए सरकारों द्वारा विकास का जो पैमाना तय किया गया है, उस पर फिर से विचार करने की ज़रूरत है. अगर जंगलों, वन्यजीव-जंतुओं, वनाश्रित समुदायों और पर्यावरण को बचाना है तो हमें ग़ैर बराबरी के सिद्धांत पर टिकी हुई विकास की अवधारणा को चुनौती देनी होगी.

feedback@chauthiduniya.com

मुस्लिमों का सवाल पूरे पश्चिमी विश्व में छाया हुआ है. जब नस्ल का मुद्दा गहराया हुआ था तो उदार समाज इसका सामना करने के योग्य था.

टीम हजारे और रामदेव के साथ जुटने वाले लोग नव उदारवाद विरोधी राजनीति के साथ भी जुट सकते हैं, जोड़ने वाला होना चाहिए.

महावीर प्रसाद आर मोरारका

सामाजिक विषमता मानव नस्ल का नासूर

आप पूछ सकते हैं कि भाई, जिन आदमियों के पास खाने को पर्याप्त रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, उन सबको समान बंटवारा कर देने से क्या सब ठीक हो जाएगा? क्या आप मानते हैं कि वे उस प्राप्त धन का दुरुपयोग नहीं करेंगे? क्या उन्हें प्राथमिकता का ज्ञान या ध्यान रहेगा? ये लोग मिली हुई धनराशि जुए या अन्य किसी दुर्व्यसन में ख़र्च करके फिर उसी तरह रोटी-कपड़े के मोहताज नहीं बन जाएंगे? यह हालत तो बहुत बुरी होगी, इसकी क्या गारंटी है कि वे लोग सही रास्ते पर ही रहेंगे. समान बंटवारा हो जाने पर आप कैसे कह सकते हैं कि नए रोज़गार ग़लत तरीक़े के नहीं होंगे? प्रश्न आपका बड़ा उचित है, उत्तर सहज नहीं. जब मानव का धरातल ही दूषित हो गया हो, पृष्ठभूमि ही बिगड़ गई हो तो कोई ज़िम्मेदारी नहीं ले सकता. कह नहीं सकते, इन सबसे वांछित फल होगा भी क्या? पर इसके लिए मार्ग है ख़ानदानी आदमी पैदा करना, शिक्षा-दीक्षा के अलावा इंसान की नस्ल सुधारना.

मानव की विचारधारा सही और वैध मार्ग पर ही चले, इसके लिए वातावरण बनाना होता है. नस्ल सुधारने की भी ख़ूब ही कही. ये कोई घोड़े, गाय, मुर्गे या सुग्गे तो हैं नहीं कि जिन जोड़ों के संयोग से अच्छे पशु-पक्षी पैदा कर लें. ये भी अच्छे इसी मानव हैं कि तेज़ दौड़ सकते हों, बोझा ढोने में बलवान हों या लड़ाकू हों. उन्हें बुद्धि का विकास तो होना ही है. अतएव नस्ल की और कोई क़िस्म देखने की ज़रूरत नहीं रहती. मानव की नस्ल तो आप बना या बिगाड़ सकते नहीं हैं. कारण किसी भी जोड़े का यौन संयोग आप स्वेच्छा से नहीं कर सकते और पुत्रोत्पत्ति या संतानोत्पत्ति का नियमन नहीं कर सकते. विवाह एक ऐसी प्रथा है, जिसके द्वारा आप पति-पत्नी को अमुक क़िस्म के ही बच्चे पैदा करने पर बाध्य नहीं कर सकते. फिर मां-बाप जैसे हों, वैसे ही बच्चे भी हों, ज़रूरी नहीं है. प्राचीन भारत में नस्ल शुद्धि यहां तक विद्यमान थी कि एक ही मनुष्य के पुत्र और उसके पुत्र और उनके पुत्र, इस तरह से परंपरागत सैकड़ों-हज़ारों वर्षों तक उन्हीं गुण-दोषों की पीढ़ी-दर-पीढ़ी बन जाती थी. महर्षि वशिष्ठ, जाबालि या भारद्वाज किन्हीं को ले लीजिए. यह नाम किसी एक व्यक्ति विशेष का न होकर एक परिवार का था, पिता के बाद पुत्र उसी नाम से प्रख्यात होता था और हर माने में वह पिता अपने पुत्र के शरीर में ज़िंदा या विद्यमान था.

यह संतति या नियमन या स्वेच्छा कंट्रोल आज भारत से लुप्तप्राय हो गया है, पर फिर भी दूसरे देशों की तुलना में यहां आज भी किसी सीमा तक मौजूद है. आज भी भारत का एक लोहार का लड़का जितना अच्छा लोहार होगा, उतना अच्छा अन्य शिक्षित बलवान युवक भी नहीं होगा. दर्ज़ी का लड़का जितना अच्छा कपड़ा सिलने का काम करेगा, उतना दूसरा न कर पाएगा इत्यादि, इत्यादि. कई बातें मिलती हैं, जिनसे नस्ल की पवित्रता भारत में दिखाई देती है. कारण स्पष्ट है, यहां विवाह प्रथा को अभी भी संस्कार माना जाता है. विवाह लड़के-लड़कियों के माता-पिता निश्चित कर देते हैं, वे स्वयं स्वेच्छा से विवाह नहीं कर पाते. अतएव जातिवादी नस्ल क़ायम रहती है. विवाह प्रथा में व्यक्ति स्वातंत्र्य भारत में बहुत कम है. सामाजिक स्थिति भारत में अपने समान आर्थिक या सामाजिक स्थिति वाले लड़के-लड़कियों का संबंध ही होता है. अतएव जो अलगाव हमेशा से सामाजिक श्रेणियों में होता रहा है, वह होता रहेगा. आज एक मज़दूर किसी धनी सेठ की लड़की से विवाह कर सकने का स्वप्न नहीं देख सकता, न ही एक धनिक सेठ का लड़का किसी रास्ते चलते मज़दूर की लड़की से वैवाहिक संबंध करने की सोच सकता है. नतीजा यही हुआ कि नस्ल सुधरे तो कैसे सुधरे? प्रधान कारण मनोवृत्ति दूषित होने का है, जो मैंने पहले बतलाया था वह है. निर्धनता या मानव मात्र की आवश्यकताओं का पूर्ण न होना. अगर एक बार इस वृत्ति का इलाज हो गया तो नस्ल भारत में इतनी बिगड़ी नहीं है कि इलाज ही न हो पाए. यह घातक मनोवृत्ति कि हम धनिक या ओहदेदार हमेशा सत्य बोलते हैं और हमारे नौकर या मोटर ड्राइवर झूठ बोलते हैं, उनका कथन हमारे जितना विश्वसनीय नहीं है, यह भेद मिटाए बिना पिछड़े हुए वर्ग की नस्ल सुधारने की बात करना ही व्यर्थ है. पहले तो बड़ों की नस्ल सुधारने की आवश्यकता है, जिन्हें धन मद या सत्ता मद हो गया है. उनके दिमाग़ से अहंकार की भावना की बू निकालनी होगी, तब कहीं कालांतर में दूसरी, तीसरी या चौथी श्रेणियों की नस्ल सुधर पाएगी.

असल में नस्ल सुधारने की यह बात ही व्यर्थ है. असमान द्रव्य वितरण ही प्रधान कारण है, जिससे प्रजा की नस्ल बनने नहीं पा रही है. हर एक प्राणी का आर्थिक धरातल अगर समाज में समान या लगभग समान हो जाए और वैचारिक संबंधों के लिए श्रेणी विभाजन न रहे तो संभव है, कालांतर में नस्ल एक तरह की या लगभग एक तरह की हो जाए. भारत में जाति प्रथा या वर्ण व्यवस्था इस भेदभाव को क़ायम रखने के लिए ज़्यादा उत्तरदायी है. संभवत: किसी समय में वर्ण व्यवस्था या जातिवाद बहुत ही उपयोगी रहा हो. अगर इस वर्ण व्यवस्था को तत्वमूलक मानकर आज भी उसके मूल आदर्श को समझ कर उपयोग में लाया जाए तो शायद बहुत उपयोगी हो, पर वह समय गया. आज का युग विशुद्ध भौतिकवाद का युग है. इसमें तत्वान्वेषण करने के बाद उस गली-सड़ी रूढ़िवादी जाति प्रथा या वर्ण व्यवस्था को फिर से कौन दोहराए, जिसका अंतिम स्वरूप भ्रष्ट रूप में हमारे सामने उपस्थित है. मानव जाति की नस्ल को न सुधरने देने का उत्तरदायित्व भी असमान वित्त वितरण व्यवस्था पर ही है.

महावीर प्रसाद आर मोरारका का जन्म 12 अगस्त, 1919 को नवलगढ़ (झुंझनू) राजस्थान में हुआ था. उद्योगपति, स्वप्नदृष्टा और लेखक से कहीं अधिक वह उदात्त मानवीय मूल्यों के संवाहक थे. उनकी गणना भारत के प्रमुख उद्योगपतियों में की जाती है.

feedback@chauthiduniya.com

मेघनाद देसाई

चरमपंथ के ख़तरे और उदारवादी सरकार

नार्वे में एंडर्स बेहरिंग ब्रीविक ने जो किया, वैसा पहले भी कई बार किया गया है. यह कोई पहली घटना नहीं है. 50 साल पहले इसी तरह के उन्मादी दक्षिणपंथी यहूदियों और मार्क्सवादियों को बदनाम किया करते थे और अब वे मुसलमानों और मार्क्सवादियों को बदनाम कर रहे हैं. वहाबियों की तरह ओसामा बिन लादेन उन सभी लोगों से घृणा करता था, जो सुन्नी नहीं थे. ब्रीविक एक पूरी तरह से गोरी यूरोपीय सभ्यता चाहता था और ओसामा भी वैसे विश्व की कामना करता था, जो वहाबियों के सामने नतमस्तक हो, जो वहाबियों की विचारधारा को ही मानने को बाध्य हो. ऐसे लोग अपनी संकीर्ण दृष्टि के प्रति अत्यधिक समर्पित होते हैं और किसी प्रकार का कोई छोटा विभेद भी बर्दाश्त नहीं कर सकते. किसी भी आधुनिक उदारवादी समाज के लिए विभेदों के बीच सामंजस्य स्थापित करना सबसे मूलभूत ज़रूरत है. यह विभेद धार्मिक हो सकता है और सांस्कृतिक भी. असहिष्णुता पूरे यूरोप में धीरे-धीरे फैल रही है. फ्रांस और बेल्जियम में बुर्क़े पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. इन देशों ने इस तथ्य को दरकिनार कर दिया कि कुछ मुस्लिम महिलाएं ही बुर्क़ा पहनती हैं और वह भी कभी-कभी. अत: इसे पहनना या न पहनना उनकी रुचि पर छोड़ देना चाहिए. बुर्क़ा पहनने को ये देश इस बात का प्रतीक समझते हैं कि ये लोग उनके यहां रहकर भी उनके समाज को स्वीकार नहीं कर पाए हैं, लेकिन ये देश समरूपता नहीं रखते हैं, ये तो विविधता ही पसंद करते हैं. आख़िरकार क्यों ये लोग मुस्लिम महिलाओं को अलग-थलग रखते हैं.

मुस्लिमों का सवाल पूरे पश्चिमी विश्व में छाया हुआ है. जब नस्ल का मुद्दा गहराया हुआ था तो उदार समाज इसका सामना करने के योग्य था. पश्चिमी विश्व में काले और अन्य अल्पसंख्यकों की उपस्थिति से यहां के समाज में जो परेशानी उत्पन्न हुई, उससे बहु संस्कृतिवाद के माध्यम से निपटा जा सका था. ये लोग रंग के आधार पर संख्या के कम होने को नापसंद नहीं करते थे. इस प्रकार सांस्कृतिक विभेद का सम्मान करते-करते नस्लीय भेद भी समाप्त होने लगे. वैसे कोई भी व्यवस्था पूर्ण नहीं होती और यही बात इसके लिए भी लागू होती है. जब यूरोप में धर्म ने पहचान बनाने वाले के रूप में प्रवेश किया तो यहां समस्याएं शुरू हुईं. इस्लाम अब्राहम में विश्वास करने वाला धर्म है जो कि न्यू और ओल्ड टेस्टामेंट के पैग़ंबरों को स्वीकार करता है. यूरोप में तीन सौ वर्षों तक धर्म युद्ध हुआ और उसे समाप्त करने में संस्कृति के रूप में धर्म की उपयोगिता का राजनीति से अधिक योगदान रहा. उदारवादी नास्तिक तो नहीं हो सकते, लेकिन उन्होंने धर्म को अपने सुधार के रास्ते में नहीं आने दिया.

अमेरिका में कुछ नास्तिक हैं, लेकिन वहां चर्च और राज्य को अलग रखा गया है, क्योंकि मुसलमान धर्म के माध्यम से अपनी पहचान स्थापित करते हैं. अत: पश्चिमी उदारवादियों के लिए तटस्थ होना मुश्किल होता है.

बेशक यह मुद्दा इस्लामिक आतंकवाद के कारण एक-दूसरे के साथ मिल गया है. यूरोपीय समाज में उदार और उग्र मुसलमानों के बीच अंतर करने और उदार मुसलमानों को उग्र मुसलमानों से अलग करने के मुद्दे को लेकर एक अंतहीन बहस छिड़ी हुई है, लेकिन मुसलमानों के अलावा अन्य संप्रदायों के लिए भी ऐसी बहस क्यों नहीं होती? ब्रीविक आख़िरकार एक ग़ैर उदारवादी नार्वेजियन ईसाई ही था. क्या पूरे मुस्लिम समुदाय के लिए बुर्क़े पर प्रतिबंध लगाना उदार समाज का काम है, जबकि किसी भी अन्य समाज के लोगों के लिए किसी भी प्रकार की पोशाक पहनने पर कोई प्रतिबंध नहीं हैं. अन्य संप्रदाय के लोगों की पोशाक के लिए भी ऐसा क़ानून क्यों नहीं बनाया जाता? यह तो शोषक क़ानून है. क्यों किसी की पहचान किसी धर्म, जाति या नस्ल द्वारा की जाती है, क्यों नहीं सभी नागरिकों को मानवाधिकार के योग्य समझा जाता है? भारत में भी मुसलमानों के साथ ऐसा ही होता है.

दारुल उलूम ने मुहम्मद वस्तानवी को विश्वविद्यालय के उप कुलपति के पद से हटाने का निर्णय लिया है, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि गुजरात के मुसलमानों को 2002 के गुजरात दंगे से इतर भी सोचना चाहिए. उन्हें तो बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन उन्होंने जो कहा, वह कोई तथ्य नहीं, बल्कि एक विचार था. क्या किसी सिख उप कुलपति को, 1984 के सिख दंगों को बार-बार न उभारे जाने की बात कहने अथवा राजीव गांधी की प्रशंसा करने के लिए, जो उन दंगों के समय प्रधानमंत्री थे, उसके पद से हटाने की बात सोची जा सकती है? कोई भी शरद पवार की प्रशंसा के लिए इस प्रकार दंडित नहीं किया जाता है, जो 1993 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे. 1993 में मुंबई के दंगे में प्रशासन की भूमिका संदिग्ध रही. फिर नरेंद्र मोदी के साथ ऐसा क्यों? क्या भारत की धर्मनिरपेक्षता का यही मतलब है कि जिन दंगों में ग़ैर कांग्रेसी नेतृत्व हो, उसकी आलोचना की जाए और जिसमें कांग्रेस का हाथ हो, उसे भूल जाओ. भारत के साथ त्रासदी यही है कि भारतीय मुसलमान यह जानते हैं कि वे जो करते हैं, उस पर उन्हीं के दोस्तों द्वारा नज़र रखी जाती है. अगर वे मुस्लिम की तरह नहीं, बल्कि स्वतंत्र नागरिक की तरह व्यवहार करने का निर्णय लेते हैं तो वे परेशानी में पड़ जाएंगे. दारुल उलूम भी अपने इसी ऊपरी आवरण की सुरक्षा कर रहा है.

feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

सर्वश्रेष्ठ पत्र

चीन से सावधान रहने की ज़रूरत

भारत को हर तरफ़ से घेरने की कोशिश कर रहा है चीन. पाकिस्तान तो पहले से ही चीन के साथ है. उसने अपने क़ब्ज़े वाले कश्मीर (पीओके) में चीन को खुली छूट दे दी है. चीन यहां हाई स्पीड रेल ट्रैक बिछाकर खाड़ी देशों तक पहुंचने की मंशा रखता है. यह क्षेत्र सामरिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है. इस क्षेत्र में पीपुल्स रिपब्लिक आर्मी के हज़ारों सैनिकों की घुसपैठ होने की ख़बर है. रिपोर्ट के मुताबिक़, पाकिस्तान के रास्ते चीन सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इस क्षेत्र में बेरोकटोक सड़क और रेल संपर्क सुनिश्चित करने के लिए अपनी पकड़ बनाना चाहता है. चीन इस क्षेत्र में 22 सुरंगों के निर्माण के प्रयास में है. संभव है कि ये सुरंगें मिसाइल स्टोर करने के लिए इस्तेमाल हों. इससे पहले चीन ने जुलाई 2009 और नवंबर 2009 में घुसपैठ करके लद्दाख के डेमचोक क्षेत्र में सड़क निर्माण को रुकवाया था. यहां चुमूर में चीनी सैनिक जगह-जगह चीन लिख गए थे. सरकार को इस बारे में कारगर क़दम उठाना चाहिए.

-नोमान क़ैसर, जामिया नगर, दिल्ली.

जकात, फ़ितरा और सदक़ा

हमारे देश में लगभग 18 से 20 करोड़ मुसलमानों की आबादी है और हर साल ग़रीब हो या अमीर, वह ईद की नमाज़ से पहले अढ़ाई किलो गेहूं के बराबर का पैसा बतौर फ़ितरे के रूप में देता है. ज़्यादातर पैसे ऐसे लोगों को दिए जाते हैं, जो कभी उसका हिसाब नहीं देते. किसी को कोई पता नहीं कि यह रक़म कहां ख़र्च होती है, इसका इस्तेमाल जायज़ कामों में होता है या नाजायज़ कामों में? अनुमान है कि यह रक़म अरबों रुपयों में होती है. इस रक़म के लिए एक ऐसा कोष बनाया जाए और इस्लामिक शरीयत के अनुसार उन लोगों पर ख़र्च किया जाए, जो इसके असली हक़दार हैं.

-मो. रफ़ीक़ चौहान, ईमेल से.

एकपक्षीय लेख

चौथी दुनिया में छपने वाले कुछ लेख एकपक्षीय होते हैं. निष्पक्ष और सार्थक पत्रकारिता के लिए यह ठीक नहीं है. जो सरकार टाडा और पोटा जैसे कानूनों को समाप्त करती है, वहीं सांप्रदायिक दंगे रोकने के लिए क़ानून बना रही है. हिंदी विरोध या उत्तर भारतीय विरोधी अभियान किसी को चर्चा दिला सकता है, सफलता या स्थिरता नहीं. रामदेव एवं अन्ना हज़ारे अपनी उपलब्धियों के कारण किसी भी सरकार पर भारी हैं.

-विमल चंद्र पांडे, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश.

आज़ादी के दीवाने नन्हूक मियां

जंगे-आज़ादी के सिपाही 105 वर्षीय हाजी नन्हूक मियां 15 अगस्त, 2002 को उस वक़्त स्वर्ग सिधार गए, जब सासाराम रेलवे स्टेशन मैदान में तिरंगा फहराया जा रहा था. प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में उन्हें तोपों की सलामी देने के बाद उनके पैतृक गांव के क़ब्रिस्तान में दफ़नाया गया था. बिहार के रोहतास ज़िले के गांव चेनारी में 26 जनवरी, 1897 को जन्मे हाजी नन्हूक मियां ने गांधी जी के आह्वान पर भारत छोड़ो अभियान में शिरकत की थी. मजिस्ट्रेट एचबी मार्टिन ने 3 फरवरी, 1943 को उन्हें छह माह की बामशक्कत क़ैद और 150 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई थी. राष्ट्रपति द्वारा उन्हें ताम्रपत्र देकर सम्मानित किया गया. अप्रैल 1988 में बिहार कांग्रेस कमेटी के तत्कालीन अध्यक्ष एवं सांसद तारिक अनवर ने उन्हें स्वतंत्रता सेनानी का प्रमाणपत्र दिया. पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र ने भी उन्हें सम्मानित किया था. हाजी नन्हूक मियां ने 1955-56 में संत विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी उनके नाम पर पार्क बनाने की घोषणा की थी, जिस पर अभी तक अमल नहीं किया गया.

-चंद्रजीत कुमार सिंह, चेनारी, रोहतास, बिहार.

भाजपा में अंतर्द्वंद्व

भारतीय जनता पार्टी में अंतर्द्वंद्व चल रहा है. नेता प्रतिपक्ष और पार्टी अध्यक्ष में महीनों बात नहीं होती. अध्यक्ष सबकी राय सुनने के चक्कर में कोई निर्णय नहीं कर पाते. प्रभात झा ने महंगाई के मामले में राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की तो जहां कांग्रेस ने इसे नौटंकी बताया, वहीं भाजपा नेताओं ने भी इस पर विरोध जताया. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब कोई जनहित की बात करता है तो उसकी अनदेखी कर दी जाती है. भाजपा आज दिशाहीन, अंतर्द्वंद्व से ग्रस्त और असंगठित नज़र आ रही है. भाजपा को कलह से उबर कर देशहित में सोचना चाहिए.

-अरुण सरोहा, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली.

क़ानून नहीं, इंसाफ़ चाहिए

देश में समय-समय पर सांप्रदायिक दंगे होते रहे हैं, जिनमें हज़ारों बेक़सूर लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी. सरकार सांप्रदायिक दंगा निरोधक क़ानून लाने की बात कर रही है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन साथ ही यह भी देखने की ज़रूरत है कि क्या यह क़ानून वाक़ई अल्पसंख्यकों की जान, माल और उनके सम्मान को सुरक्षित रख पाने में सक्षम है? इस क़ानून को ईमानदारी और सख़्ती से लागू किए जाने के लिए सरकार की क्या नीति है?

-सनव्वर ख़ान, दिल्ली.

राजकमल प्रकाशन समूह

चौथी दुनिया में प्रकाशित सप्ताह के सर्वश्रेष्ठ पत्र को राजकमल प्रकाशन की ओर से 700 रुपए की किताबें दी जाएंगी.

राजकमल प्रकाशन की किसी भी पुस्तक की समीक्षा चौथी दुनिया को भेजें. हर महीने की सर्वश्रेष्ठ समीक्षा को 1100 रुपए की पुस्तकें दी जाएंगी.

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें :
चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301
ई मेल : feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

लोकतंत्र की गुंजाइश ख़त्म हो रही है

क्या कहें, अपना माथा पीटें, भगवान को, अल्लाह को, गॉड को दोष दें, किस पर अपनी खीज निकालें? सीएजी की रिपोर्ट आ गई. रिपोर्ट में क्या नहीं है! देखने पर लगता है कि हम जिस देश में रह रहे हैं, उसमें ईमानदार प्रबंधन नाम की कोई चीज ही नहीं बची है. यह टू जी स्पेक्ट्रम का मसला नहीं है, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया. लोग उनको धमकाते रहे. उनके मंत्री ही उनको धमकाते रहे. प्रधानमंत्री ख़ामोश रहे. देश को एक लाख छिहत्तर हज़ार करोड़ रुपये का घाटा हो गया. प्रधानमंत्री जी के पास वक़्त नहीं था कि वह इस ओर ध्यान दे पाते. उन्होंने देश से माफ़ी मांग ली, देश ने उन्हें माफ़ भी कर दिया, पर अब क्या है? अब सीएजी की रिपोर्ट आ गई और यह कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर है. इसमें सीएजी दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर भी सवाल उठा रहा है और प्रधानमंत्री कार्यालय पर भी. उसकी रिपोर्ट साफ़-साफ़ कह रही है कि प्रधानमंत्री कार्यालय की कोताही और काहिली इसके लिए ज़िम्मेदार है. अफ़सोस इसलिए होता है कि प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ आदमी अगर देश में चलने वाले ऐसे काम पर नज़र नहीं रख सकता, जिसका रिश्ता देश की इज़्ज़त के साथ है तो उस प्रधानमंत्री को क्या कहें? सीएजी की यह रिपोर्ट केंद्रीय सरकार के प्रबंधन के मुंह पर, जिसमें प्रधानमंत्री सीधे तौर पर शामिल हैं, एक तमाचा है. इस तमाचे की गूंज देश के लोगों के कानों में तो पहुंची, लेकिन जिसे तमाचा लगा, वह बेशर्मी के साथ अपनी सफ़ाइयां दे रहा है.

हम जब यह बात कह रहे हैं, तब हम विपक्ष की भाषा नहीं बोल रहे, क्योंकि देश में विपक्ष कहलाने वाले यानी लोकसभा में जो विपक्षी दल हैं भारतीय जनता पार्टी और दूसरे राजनीतिक दल, वे तो इतने गए-गुज़रे हैं कि उन्हें जनता का दर्द, जनता की तक़लीफ और जनता के आंसू दिखाई ही नहीं देते. महंगाई पर संसद में बहस होती है, वोट पड़ते हैं और मुख्य विपक्षी दल द्वारा लाया हुआ प्रस्ताव धराशायी हो जाता है. यही शायद सीएजी की कॉमनवेल्थ गेम्स की रिपोर्ट में भी होने वाला है. इसलिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेता भी कॉमनवेल्थ आयोजन समिति में थे और उनमें कइयों ने बहती गंगा में हाथ धोया, लूट के हिस्सेदार बने. इसीलिए आज आपको कहीं पर भी ज़ोरदार सवाल उठते हुए नज़र नहीं आ रहे होंगे. मीडिया कितना करे? क्योंकि हमारे लोगों को भी तो कहीं न कहीं, कुछ न कुछ इसमें हिस्सा मिला है. मीडिया घरानों के कुछ लोग मीडिया के अलावा भी बिज़नेस करते हैं. चूंकि वे वहां व्यापार करते हैं, इसलिए उन्हें उसमें फ़ायदा भी मिलता है. एक नेक्सस बन गया है. यह स्थिति हमारे देश में निराशा का माहौल पैदा कर रही है और इस कहावत को सही साबित कर रही है कि हमाम में सब नंगे हैं. निराशा की यह स्थिति देश के लिए ख़तरनाक है, क्योंकि लोगों को लगता है कि चाहे कितनी भी बड़ी लूट हो, चाहे कोई पकड़ा जाए, चाहे कोई कितना भी बड़ा अपराध करे, उसका कुछ नहीं होगा. साधारण आदमी की कोताही व चोरी और देश चलाने वालों की कोताही व उनमें पैदा हुई चोरी की आदत एक पैमाने की नहीं हैं. देश चलाने वालों का पैमाना भी बड़ा है और उनकी ज़िम्मेदारी भी बड़ी है. कितनी आसानी से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम अब सबकी ज़ुबान पर आ रहा है. क्या इनकी साख दोबारा बनाने की कोशिश नहीं की जा सकती?

हम जब यह बात कह रहे हैं, तब हम विपक्ष की भाषा नहीं बोल रहे, क्योंकि देश में विपक्ष कहलाने वाले यानी लोकसभा में जो विपक्षी दल हैं भारतीय जनता पार्टी और दूसरे राजनीतिक दल, वे तो इतने गए-गुज़रे हैं कि उन्हें जनता का दर्द, जनता की तक़लीफ और जनता के आंसू दिखाई ही नहीं देते. महंगाई पर संसद में बहस होती है, वोट पड़ते हैं और मुख्य विपक्षी दल द्वारा लाया हुआ प्रस्ताव धराशायी हो जाता है. यही शायद सीएजी की कॉमनवेल्थ गेम्स की रिपोर्ट में भी होने वाला है. इसलिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेता भी कॉमनवेल्थ आयोजन समिति में थे और उनमें कइयों ने बहती गंगा में हाथ धोया, लूट के हिस्सेदार बने. इसीलिए आज आपको कहीं पर भी ज़ोरदार सवाल उठते हुए नज़र नहीं आ रहे होंगे.

मुझे लगता है कि फ़िलहाल तो नहीं की जा सकती. अगर यह कोशिश नहीं की जा सकती, तभी डर लगता है कि देश की जनता अगर निराश होकर उन रास्तों को आशा की नज़र से देखने लगे, जो लोकतांत्रिक नहीं हैं तो क्या इसमें जनता का दोष है या उन लोगों का, जो जनता के मन में निराशा पैदा कर रहे हैं? निराशा का हद से गुज़र जाना विद्रोह का आधार बनता है. ऐसा भी नहीं है कि निराशा एक जगह हो, देश में हर जगह निराशा है. अगर सत्ता पक्ष से निराशा है तो विपक्ष से भी निराशा है. लोगों ने सवाल करने बंद कर दिए हैं. लोगों ने भ्रष्टाचार पर बात करनी बंद कर दी हैं. यह सरकार या विपक्ष की काहिली की सफलता नहीं है, यह लोगों के मन में पैदा हो रहे गुस्से का पूर्वाभास है. अगर यह गुस्सा देश में रहने वाले किसी भी वर्ग में फूटने की कगार पर पहुंच जाए तो हमारे लोकतंत्र के लिए परेशानियां पैदा हो जाएंगी. जिन देशों में लोकतंत्र नहीं है, वहां के लोग लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं और हमारे देश में जहां लोकतंत्र है, वहां हम लोकतंत्र की न इज़्ज़त कर रहे हैं और न लोकतंत्र को जी रहे हैं. हम लोकतंत्र में मिली आज़ादी का दुरुपयोग कर रहे हैं और इस हद तक दुरुपयोग कर रहे हैं कि लूट की कोई सीमा बची ही नहीं है. जो लूट में शामिल हैं, उनका कहना है कि ये वक़्ती बातें हैं. लोग भूलने के आदी हैं, बहुत जल्दी भूल जाएंगे.

अगर ऐसा है तो फिर यह देश शायद लोकतंत्र के काबिल नहीं है. हमारे लोकतंत्र में फ़ैसला पांच साल के बाद ही होता है या तब होता है, जब जनता के हाथ में वोट देने के अधिकार का इस्तेमाल करने की स्थिति आती है. जनता अपने वोट का इस्तेमाल किसके ख़िलाफ़ करे और किसके पक्ष में करे, एक सवाल यह भी खड़ा हो रहा है. जो भी लोग अपनी भाषा से, अपने कर्मों से जनता के मन में निराशा पैदा कर रहे हैं, वे जनता के दुश्मन हैं. सीएजी की रिपोर्ट देश के लोगों के मन में अगर निराशा पैदा करने की जगह गुस्सा पैदा करे, तो मैं समझूंगा कि हमारे देश में अभी कुछ सालों तक लोकतंत्र के लिए काफ़ी गुंजाइश बची है. अगर लोग ख़ामोश हो गए और न बोले तो मानना चाहिए कि लोकतंत्र की गुंजाइश धीरे-धीरे ख़त्म हो रही है.

संपादक
editor@chauthiduniya.com

नव उदारवाद की प्रयोगशाला में भ्रष्टाचार

प्रेम सिंह

एक दशक पहले यह ख़तरा पहचान में आने लगा था कि अगर नव उदारवादी नीतियों के मुक़ाबले में खड़े होने वाले जनांदोलनों का राजनीतिकरण और समन्वयीकरण नहीं हुआ तो नव उदारवाद के दलाल, चाहे वे नेता हों, नौकरशाह हों, बुद्धिजीवी हों, एनजीओबाज हों, धर्मगुरु हों, कलाकार हों या खिलाड़ी, विरोध के सारे प्रयास नाकाम कर देंगे. वही हो रहा है. आज नव उदारवाद के वास्तविक विरोधी रहे कतिपय समूह और व्यक्ति भी राजनीति को कोसने वालों के पीछे चलते नज़र आते हैं. इस पीछे चलने में अलग-अलग मुद्दों पर और क्षेत्रों में सक्रिय जनांदोलनों की एकजुटता से नव उदारवाद को पोसने वाली राजनीति के विकल्प की संकल्पना भी पीछे चली गई है. पिछले दो दशकों के संघर्ष में बाजी नव उदारवादियों के हाथ रही है. लोकपाल विधेयक और विदेशों में जमा काला धन वापस लाने के मुद्दों के इर्द-गिर्द चलने वाले भ्रष्टाचार विरोधी अभियान ने नव उदारवाद के पक्ष को और मज़बूत किया है. यह अभियान चलाने वाले प्रकटत: या प्रच्छन्नत: नव उदारवाद के समर्थक हैं.

पिछले दो दशकों से देश पूरी दुनिया के साथ नव उदारवाद की प्रयोगशाला में तब्दील हो गया है. आरएसएस की पिछले क़रीब सौ वर्षों की कोशिशों के बावजूद जनता ने देश को सांप्रदायिकता की प्रयोगशाला नहीं बनने दिया, लेकिन पूंजीवादी साम्राज्यवाद के एजेंटों ने महज़ 20-25 सालों में इसे नव उदारवाद की प्रयोगशाला बना डाला. नव उदारवादी आर्थिक नीति से शुरू हुआ सिलसिला राजनीति, शिक्षा, भाषा, संस्कृति, कला, खेल, पत्रकारिता, धर्म एवं अध्यात्म आदि को अपनी जद में ले चुका है. सिविल सोसायटी एक्टिविस्टों का भ्रष्टाचार विरोधी अभियान नव उदारवादी शिकंजे को कहीं ज़्यादा गहराई में कस रहा है. साथी कहते हैं कि देश गर्म हो रहा है, जो चाहे इसका उपयोग कर ले. टीम हजारे और रामदेव के साथ जुटने वाले लोग नव उदारवाद विरोधी राजनीति के साथ भी जुट सकते हैं, जोड़ने वाला होना चाहिए. ऐसे साथियों की सदाशयता से इंकार नहीं किया जा सकता. वे वाकई कुछ सार्थक होता देखना चाहते हैं. सबसे बड़ी बात है कि वे काफ़ी बिगड़ चुकी स्थिति में भी निराश नहीं होना चाहते. लेकिन क्या वे नहीं जानते कि यह नव उदारवादी व्यवस्था के पेटे की गर्माहट है, जो उसने अपने बचाव के लिए पैदा की है? वरना नव उदारवाद की मार खाने वाले तो शुरू से संघर्ष कर रहे हैं और हताशा में आत्महत्या भी. कई लोग हैं, जो नव उदारवादी निजाम द्वारा संविधान की मूल आत्मा को नष्ट करने के प्रति आगाह करने में लगे हैं. इन सबका संघर्ष सीधे राजनीतिक भी नहीं है, लेकिन हजारे और रामदेव के हिमायतियों को इनका संघर्ष साथ देने लायक नहीं लगता. नव उदारवाद के चरित्र और प्रभावों को समझने और बताने के उद्देश्य से भारतीय भाषाओं में काफ़ी सामग्री (पर्चे, फोल्डर, पुस्तिकाएं, पत्रिकाएं, वेबसाइट) लगातार प्रकाशित हो रही है, लेकिन देश गरमाने वालों को इससे कोई सरोकार नहीं है. जाहिर है, देश को गरमाने का इनका एजेंडा अलग है, बल्कि जहां वास्तविक गर्माहट है, सिविल सोसायटी एक्टिविस्ट उस पर पानी डालने की कोशिश करते हैं.

सिविल सोसायटी उपनिवेशवादी व्यवस्था कायम होने के साथ बनना शुरू हो गई थी, लेकिन वह इस कदर मुटाई पिछले क़रीब 25 सालों से जारी उस नव उदारवादी व्यवस्था के पेट में रहते हुए, जिसमें भ्रष्टाचार भी ख़ूब पला-बढ़ा. अब वह भ्रष्टाचार रहित नव उदारवादी व्यवस्था चाहती है. भारत में यह कैसे संभव हो सकता है, जहां अर्थव्यवस्था केवल एक चौथाई आबादी के लिए बनाई और चलाई जाती हो? सभी जानते हैं कि नव उदारवादी व्यवस्था देश की तीन चौथाई आबादी को बाहर रखकर चलती है. नव उदारवादी आर्थिक सुधार अथवा नई आर्थिक नीतियां ज़्यादा से ज़्यादा 25 प्रतिशत आबादी को कवर करती हैं और लूटती समस्त संसाधनों और श्रम को हैं. बाकियों के लिए अपने असंगठित और फुटकर धंधे हैं या फिर गांधी समेत कांग्रेसी नेताओं के नाम पर चलाई जाने वाली कतिपय कल्याणकारी योजनाएं. उनमें भी बराबर भ्रष्टाचार होता रहता है. माना कि एक चौथाई आबादी की व्यवस्था में भ्रष्टाचार रोकने का पुख्ता इंतजाम हो भी जाता है तो इससे बाकी आबादी को क्या मिलने वाला है? इससे एक चौथाई आबादी के सुकून और संपन्नता में जरूर बढ़ोत्तरी हो जाएगी. क्या हम सिविल सोसायटी के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का यह अर्थ निकालें कि राजनीति, नौकरशाही और व्यापार में उच्च पदों पर आसीन हस्तियों के भ्रष्टाचार पर लगाम रहेगी तो सिविल सोसायटी, विशेषकर एक्टिविस्टों को नव उदारवादी नीतियों का फायदा और ज़्यादा मिलेगा? वेतन-भत्ते और बढ़ेंगे, एनजीओ को और फंड मिलेगा, देश-विदेश घूमना ज़्यादा सुविधाजनक और आरामदेह होगा, मौजमस्ती ज़्यादा हो पाएगी, बेटा-बेटी जल्दी और अच्छे से सेटल होंगे और महंगे से महंगा इलाज होने के बाद भी जब मौत आ ही जाएगी तो संततियों के लिए बड़ी संपत्ति छोड़ कर जाएंगे?

काला धन वापस लाकर जनता का दरिद्रय हरने की वकालत करने वाले दरअसल झांसा देते हैं. काला धन जमा करने वाले स्विस अथवा अन्य बैंक इस व्यवस्था का स्वीकृत हिस्सा हैं. यह व्यवस्था धन को काला कर सकती है, लेकिन जिन्होंने वह पैदा किया है, उन पर ख़र्च नहीं कर सकती. वह खाद्यान्नों को बर्बाद कर देगी, उनका उत्पादन घटा देगी, लेकिन भूखी और कुपोषित जनता को उपलब्ध नहीं होने देगी. आप मारें या छोड़ें, कहना होगा कि भ्रष्टाचार के विरोध में जो देश गरमा रहा है, उसकी सच्चाई यही है. पिछले तीन दशकों से ज़्यादा की छोटी-मोटी राजनीतिक सक्रियता के अनुभव के आधार पर हमारा मानना है कि भ्रष्टाचार विरोध का यह अभियान वास्तव में राजनीति के विरोध का अभियान है. अमेरिका से भारत तक नव उदारवाद स्वतंत्र राजनीति की इजाज़त नहीं देता. बराक ओबामा को राष्ट्रपति बने दो साल हुए हैं. अगला चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने रिकॉर्ड धन इकट्ठा कर लिया है. अमेरिका में यह चल सकता है, लेकिन भारत में स्वतंत्र राजनीति का न रहना, भारत का न रहना हो जाएगा. नव उदारवाद की प्रयोगशाला में अर्थ नीति के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, भाषा, कला, साहित्य, संस्कृति, यहां तक कि नागरिक बोध और जीवन मूल्यों को भी नव उदारवादी मोल्ड में ढाला जा रहा है. अगर राजनीति भी इसी मोल्ड में ढल में जाएगी तो नव उदारवाद का प्रयोग पूरा हो जाएगा. राजनीति से नफ़रत का आलम देखिए. पिछले दिनों दिल्ली में ख़ूनी दरवाज़े के पास शहीदी पार्क में जेपी की मूर्ति के साये में आयोजित एक सभा में टीम हजारे के एक प्रमुख नुमाइंदे स्वामी अग्निवेश के राजनीति और लोकशक्ति पर विचार सुनने को मिले. अवसर कुछ साथियों द्वारा पटना से दिल्ली तक की गई संपूर्ण क्रांति संकल्प यात्रा के समापन का था. अग्निवेश ने राजनीति को बुरा और लोकशक्ति को अच्छा बताया. अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हुए ख़ुद को और भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के संचालक अपने साथियों को लोकशक्ति का सच्चा प्रतिनिधि और भ्रष्टाचार विरोधी अभियान को सच्चा अभियान घोषित किया, बिना किसी संदेह के. गोया लोकशक्ति रसगुल्ला हो, उठाया और गप से खा लिया. लोकशक्ति के गुणगान में गांधी का हवाला ज़रूर दिया जाता है. नव उदारवाद की प्रयोगशाला में गांधी को ऐसी गरीब गाय बना दिया गया है, जिसकी रस्सी खींचकर कोई भी अपने खूंटे से बांध लेता है, मनमोहन सिंह-सोनिया गांधी से लेकर अन्ना-रामदेव तक.

अमेरिका से भारत तक नव उदारवाद स्वतंत्र राजनीति की इजाज़त नहीं देता. बराक ओबामा को राष्ट्रपति बने दो साल हुए हैं. अगला चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने रिकॉर्ड धन इकट्ठा कर लिया है. अमेरिका में यह चल सकता है, लेकिन भारत में स्वतंत्र राजनीति का न रहना, भारत का न रहना हो जाएगा. नव उदारवाद की प्रयोगशाला में अर्थ नीति के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, भाषा, कला, साहित्य, संस्कृति, यहां तक कि नागरिक बोध और जीवन मूल्यों को भी नव उदारवादी मोल्ड में ढाला जा रहा है. अगर राजनीति भी इसी मोल्ड में ढल में जाएगी तो नव उदारवाद का प्रयोग पूरा हो जाएगा.

नव उदारवाद की प्रयोगशाला में गांधी की एक अलग प्रतिमा गढ़ी जा रही है. वरना क्या कारण है कि हज़ारों निर्दोष नागरिकों की हत्या कराने वाले नरेंद्र मोदी के प्रशंसक अन्ना हजारे को गांधीवादी कहा और लिखा जा रहा है और गांधीवादी चुप ही नहीं, समर्थन में हैं. अग्निवेश ने भी अपने भाषण में गांधी का हवाला दिया कि वह उन्हीं का काम आगे बढ़ा रहे हैं. इन महानुभावों की नज़र में वही लोकशक्ति है, जो इनके आह्वान पर जंतर-मंतर और रामलीला मैदान पहुंचती है, कपिल सिब्बल के चुनाव क्षेत्र में जनमत संग्रह कराती है और टीवी-अख़बारों में जन लोकपाल विधेयक के पक्ष में ताल ठोकती है. नव उदारवाद की प्रयोगशाला में लोकशक्ति का आधार और मायने बदल गए हैं. जिन्हें नव उदारवादी सुरक्षा कवच प्राप्त है, वे ही लोकशक्ति हैं. उन्हें रेहड़ी नहीं लगानी पड़ती, कचरा नहीं बीनना पड़ता, उनके बच्चे ढाबों पर बर्तन नहीं मांजते, उनकी औरतें कई-कई घरों में झाड़ू-पोंछा-बर्तन नहीं करतीं, उन्हें मलमूत्र सफ़ाई, कमरतोड़ फुटकर मज़दूरी, कारीगरी और किसानी नहीं करनी पड़ती. अग्निवेश ने अपने भाषण में इसी 28-29 मई को हैदराबाद में बनी सोशलिस्ट पार्टी का ज़िक्र किया, यह बताने के लिए कि भ्रष्ट राजनीति का मुक़ाबला राजनीतिक पार्टियां बनाकर नहीं किया जा सकता. उनके मुताबिक़, कोई भी नवगठित राजनीतिक पार्टी राजनीतिक होने के नाते भ्रष्ट ही होगी. मंच पर उपस्थित जस्टिस राजेंद्र सच्चर ने उनसे कहा कि वह भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष को वास्तविक और व्यापक बनाने के लिए सोशलिस्ट पार्टी में शामिल होने की बाबत सोचें. अग्निवेश ने जवाब दिया कि राजनीतिक पार्टी बनाना या उनमें शामिल होना भटके हुए लोगों का काम है. कुछ भटके हुए लोगों के नाम भी उन्होंने उछाले कि ऐसे लोग चाहें तो सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हो सकते हैं.

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एवं समाजवादी चिंतक हैं)

feedback@chauthiduniya.com

मैं ख़ुद भी डर गया. मैंने पुलिस को बुलाया. पुलिस आने के बाद कर्मचारी मुर्दाघर में एक साथ घुसे. कर्मचारियों ने जब इस व्यक्ति को निकाला तो वह पीला पड़ा हुआ था.

सूचना का अधिकार
जानने का अधिकार जीने का अधिकार
चौथी दुनिया की पहल

आप भी भ्रष्टाचार से लड़ सकते हैं

भ्रष्टाचार देश को घुन की तरह खा रहा है. अफ़सर से लेकर नेता तक हर कोई लूट के खेल में लगा हुआ है. विधायकों एवं सांसदों का वेतन–भत्ता सुरसा के मुंह की तरह बढ़ता जा रहा है. रातोंरात बनते इनके महल और करोड़ों–अरबों की संपत्ति देखकर तो यही लगता है. जिस जनता के वोटों से ये चुने जाते हैं, वही इनसे यह नहीं पूछ पाती कि आख़िर कुछ ही समय में इनके पास इतना पैसा कहां से आ गया. ज़ाहिर है, यह पैसा उसी जनता का होता है, लेकिन वह अपने ही पैसों की लूट के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाती. यही नहीं, जिस जनता के टैक्स से सरकारी अधिकारियों–कर्मचारियों को वेतन मिलता है, उसी जनता का काम अधिकारी–कर्मचारी बिना रिश्वत लिए नहीं करते. चाहे एक ग़रीब आदमी का राशनकार्ड बनना हो, इंदिरा आवास, पेंशन का मामला हो. हर काम के लिए रिश्वत की दर तय है और उसके बिना काम नहीं होता. रिश्वत देकर काम कराना ग़रीब आदमी की मजबूरी है, क्योंकि यह उसके जीने–मरने का सवाल होता है. लेकिन हद तो तब होती है, जब एक सुखी–संपन्न आदमी अपना काम कराने के लिए ख़ुशी–ख़ुशी रिश्वत देने को तैयार हो जाता है. उसे यह नहीं पता होता है कि इस घूसखोरी के ज़रिए वह भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा दे रहा है.

चौथी दुनिया इस कॉलम के माध्यम से अपने पाठकों को यह बताता रहा है कि भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है. इस अंक में भी हमने भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए जनता को और अधिक जागरूक बनाने की कोशिश की है.

भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ लड़ाई की शुरुआत आप सभी को करनी होगी, व्यवस्था को दोष देने भर से काम नहीं चलने वाला. सूचना अधिकार क़ानून के रूप में आपके पास एक ताक़तवर हथियार है. आप इसका इस्तेमाल करें और भ्रष्टाचारियों के ख़िलाफ़ हल्ला बोलें. आप सभी का एक–एक आवेदन भ्रष्ट व्यवस्था को साफ़ करने का काम करेगा. इस अंक में हम एक ऐसे आवेदन का प्रारूप प्रकाशित कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल आप भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ अपनी लड़ाई के लिए कर सकते हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया

एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन –201301
ई–मेल : rti@chauthiduniya.com

आवेदन का प्रारूप

(भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों की स्थिति)

सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी
(विभाग का नाम)
(विभाग का पता)

विषय: सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन

महोदय,
कृपया निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराएं:

1. केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा दिनांक.....से.....के बीच प्राप्त की गई शिकायतों का संक्षिप्त विवरण, क्या शिकायत गुमनाम थी, शिकायत की तिथि, उन अधिकारियों या प्राधिकरणों का पूरा विवरण (नाम, पद एवं संपर्क का पता आदि), जिनके ख़िलाफ़ शिकायत की गई है.

2. उपर्युक्त में से कौन सी शिकायतें तुरंत ख़ारिज़ कर दी गईं और कौन सी आगे की जांच के लिए स्वीकार की गईं. मामले के अनुसार शुरुआती जांच की तिथि या ख़ारिज करने की वजह का संक्षिप्त विवरण भी दें.

3. आगे की जांच के लिए स्वीकार की गई शिकायतों में से कितने मामलों में जांच बंद हो चुकी है? प्रत्येक के बंद होने का संक्षिप्त विवरण दें.

4. विभिन्न क़ानून, नियम, निर्देश, प्रक्रिया, मैन्युअल आदि के अनुसार केंद्रीय सतर्कता आयोग में शिकायत दर्ज कराने के कितने समय बाद जांच पूरी हो जाती है. कृपया ऐसे दिशानिर्देशों की प्रति उपलब्ध कराएं, जिसमें शिकायत प्राप्ति से लेकर उस पर कार्रवाई और दंडारोपण तक के विभिन्न चरणों के लिए समय सीमा का वर्णन हो.

5. दिनांक.....से अब तक आयोग को कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं? उनमें से कितनी तत्काल ख़ारिज कर दी गईं और कौन सी आगे की जांच के लिए रखी गईं? उनमें से कितनी शिकायतों की छानबीन में उपरोक्त समय सीमा का पालन किया गया?

मैं आवेदन शुल्क के रूप में.....रुपये अलग से जमा कर रहा/रही हूं.
या
मैं बीपीएल कार्डधारक हूं, इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूं. मेरा बीपीएल कार्ड नं.....है.

यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित न हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों की समयावधि के अंतर्गत हस्तांतरित करें. साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम एवं पता अवश्य बताएं.

भवदीय

नाम.....
पता.....
फोन नं.....

संलग्नक:
(यदि कुछ हो)

राशिफल

मेष 21 मार्च से 20 अप्रैल

आपको सभी प्रकार के छिटपुट कार्य निपटाने में अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए. यदि आप किसी नौकरी या आजीविका से जुड़े हैं तो अधिकारी वर्ग आपके कामकाज से संतुष्ट रहेगा. किसी नई तरक्क़ी का प्रस्ताव या स्थानांतरण की समीक्षा आपके हक़ में संभव है.

वृष 21 अप्रैल से 20 मई

रोज़गार और कारोबार से जुड़े कार्यों के लिए घर से बाहर निकलना होगा. कुछ लोगों को सरकारी मामले निपटाने में जद्दोजहद करनी पड़ सकती है. यदि आप इन सब अटके हुए मामले निपटाने में तल्लीन रहेंगे तो सप्ताह मध्य में आपकी स्थिति बहुत उत्साहपूर्ण और स्फूर्तिदायक रहेगी.

मिथुन 21 मई से 20 जून

प्रियजनों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहेंगे. किसी नए चिकित्सा स्थल या रोगोपचार करने वाले चिकित्सक की खोजबीन आप कर सकते हैं. यदि आपकी समस्या ज़्यादा गंभीर है तो इस मामले में दौड़धूप करने में भी पीछे नहीं रहेंगे.

कर्क 21 जून से 20 जुलाई

आपको दूसरों के लिए कुछ कर दिखाने का मौक़ा दे रहा है. यदि आप अपने वादे को पूरा करना चाहें तो उसके लिए भी अनुकूल समय है. आपकी पहुंच और प्रतिष्ठा किसी व्यक्ति के लिए रामबाण औषधि साबित हो सकती है. यही विचार आपको स्थायी साख और प्रसिद्धि देने में सहायक हो रहा है.

सिंह 21 जुलाई से 20 अगस्त

मान–मर्यादा और सामाजिक प्रतिष्ठा बचाने के लिए कोई गुप्त चिंता आपको परेशान करेगी. शत्रुओं के षड्यंत्र विफल करने के लिए आप साम–दाम–दंड–भेद का सहारा ले सकते हैं. यदि आप समय रहते इन मामलों को अपने तरीक़े से हल नहीं करेंगे तो आगे चलकर आपको खिन्नता झेलनी पड़ेगी.

कन्या 21 अगस्त से 20 सितंबर

आय की तुलना में व्यय बढ़ जाने से आपका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है. ऐसा ही समय इस सप्ताह भी आपको बेचैन रखेगा. कार्यक्षेत्र में धीमी प्रगति के कारण आपका हौसला टूट सकता है. जहां से भी आप राहत की उम्मीद रखते हैं, वहीं से नकारात्मक जवाब मिलने से और भी चिंताएं आपको घेर सकती हैं.

तुला 21 सितंबर से 20 अक्टूबर

इस सप्ताह यदि आप बातूनी और बड़बोले होकर काम करेंगे तो सहयोगी या वरिष्ठ अधिकारी की प्रताड़ना आपको झेलनी पड़ेगी. यदि आप अपने काम में मन लगाएं और कुछ देर ख़ामोश रहें तो आपके लिए लोगों का नज़रिया बदल सकता है.

वृश्चिक 21 अक्टूबर से 20 नवंबर

विश्वसनीय दोस्त या प्रेमी के व्यवहार से आपको कुछ खिन्नता हो सकती है. आपको ऐसा लगेगा कि अब आपकी उपेक्षा होने लगी है. हो सकता है कि आपने उसके मिज़ाज पर पूरी तरह ग़ौर न किया हो या फिर उसकी किसी उल्टी–सीधी बात का ग़लत मतलब लगा लिया हो.

धनु 21 नवंबर से 20 दिसंबर

आप अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए आंख बंद करके ख़र्च करते हैं. कुछ ऐसे ही सवालों और देनदारी का सामना इस सप्ताह करना पड़ सकता है, लेकिन छोटी–मोटी और झूठी वाहवाही के लिए अपनी जेब ख़ाली करना बुद्धिमानी नहीं है.

मकर 21 दिसंबर से 20 जनवरी

किसी गोष्ठी, मीटिंग या विचार–विमर्श के दौरान आपकी सलाह कार्यक्षेत्र में बहुमूल्य हो सकती है. किसी नई जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व का निर्वाह करने के लिए भी आपसे कहा जा सकता है. इन सब बातों का असर यह होगा कि आप औरों से बहुत आगे निकल जाएंगे.

कुंभ 21 जनवरी से 20 फरवरी

किसी कारण आपके मन में बहुत अशांति रहेगी. इसका कारण आर्थिक न होकर किसी प्रियजन या प्रेमी का व्यवहार भी हो सकता है. आपके अंदर यदि किसी मानसिक या शारीरिक कमज़ोरी का मामला बढ़ रहा है तो उसे दूर करने के लिए वैद्य या चिकित्सक की सलाह ज़रूरी है.

मीन 21 फरवरी से 20 मार्च

व्यवसायिक संबंधों के विस्तार के लिए यह सप्ताह बहुत अनुकूल है. यदि आपको अपने पार्टनर या सहयोगियों पर पूरा भरोसा हो तो आप अपना काम उनके हवाले करके निश्चिंत हो सकते हैं. हो सकता है, आपकी दौड़भाग का कोई अच्छा नतीजा निकल आए.

पंडित सुदर्शन
feedback@chauthiduniya.com

ज़रा हट के

मैं ज़िंदा हूं!

कभी–कभी ऐसा होता है कि जिसे हम मुर्दा समझते हैं, वह असल में जीवित होता है. एक दक्षिण अफ़्रीकी व्यक्ति की जब नींद खुली तो उसने ख़ुद को मुर्दाघर के फ़्रीजर में पाया. क़रीब एक दिन पहले उसके परिवारवालों ने सोच लिया था कि वह मर गया है. स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता शिज्वे कुपेलो ने बताया कि यह व्यक्ति अचानक उठ बैठा. 21 घंटे पहले उसके परिवारवालों ने एक सहायक को बुलाकर इस व्यक्ति को दमे के दौरे के बाद मुर्दाघर भेज दिया. मुर्दाघर के मालिक आयंदा माकोलो ने बताया कि परिवारवालों ने जैसे ही मौत की सूचना दी, उन्होंने अपने ड्राइवर को शव लाने के लिए भेज दिया. माकोलो ने बताया कि उन्होंने सोचा था कि यह कोई 80 साल का व्यक्ति होगा. जब ड्राइवर वहां पहुंचा तो शव का परीक्षण किया गया. उसकी नब्ज़, दिल की धड़कन सुनने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ नहीं बचा था. शव को मुर्दाघर के फ़्रीजर में रखने के एक दिन बाद कर्मचारियों ने भीतर से मदद के लिए किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी. उन्होंने सोचा कि यह कोई भूत है. माकोलो ने बताया, मुझे इस पर यक़ीन ही नहीं हुआ.

मैं ख़ुद भी डर गया. मैंने पुलिस को बुलाया. पुलिस आने के बाद कर्मचारी मुर्दाघर में एक साथ घुसे. कर्मचारियों ने जब इस व्यक्ति को निकाला तो वह पीला पड़ा हुआ था. उसने हम लोगों से पूछा, मैं यहां कैसे आया. स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि इसके बाद इस व्यक्ति को नज़दीक स्थित एक अस्पताल में जांच के लिए ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बाद में उसे छुट्टी दे दी.

वजूद पर ख़तरा

ज़्यादातर वन्यजीव–जंतु प्रजातियां तो विलुप्ति की कगार पर हैं ही, अब मेंढक और सांप भी ख़तरे में हैं. वैज्ञानिकों ने एक ताज़ा शोध में पाया है कि दुनिया में पाए जाने वाले जीवों में से एक तिहाई लुप्त होने की कगार पर हैं और यह ख़तरा हर दिन बढ़ता जा रहा है. पशु–पक्षियों के संरक्षण के लिए काम करने वाली संस्था आईयूसीएन ने 47,677 जीवों की एक रेड लिस्ट जारी की है, जिनमें से 17,291 जीवों की प्रजातियां गंभीर ख़तरे में हैं. इनमें 21 प्रतिशत स्तनधारी जीव हैं, 30 प्रतिशत मेंढकों की प्रजातियां हैं, 70 प्रतिशत पौधे हैं और 35 प्रतिशत बिना रीढ़ की हड्डी वाले यानी सांप जैसे जीव हैं. वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके लिए ज़िम्मेदार ख़तरों को, ख़ासकर वह जगह जहां इस तरह के जीव रहते हैं, पनपते हैं, कम करने के लिए उचित क़दम नहीं उठाए जा रहे हैं. आईयूसीएन की निदेशक जेन स्मार्ट का कहना है कि इस बात के सबूत मिल रहे हैं कि इस तरह के जीवों पर ख़तरा बढ़ता जा रहा है. उनका कहना है, हाल के विश्लेषणों से स्पष्ट है कि 2010 का जो लक्ष्य था, वह पूरा नहीं हो पाएगा. उनका कहना है कि सरकारों को फ़ौरन गंभीर क़दम उठाने होंगे, क्योंकि समय बेहद तेज़ी से ख़त्म हो रहा है. संस्था की तरफ़ से जारी रेड लिस्ट दुनिया भर में फैले हज़ारों वैज्ञानिकों की रिपोर्ट के आधार पर बनती है और इसे जैव विविधता पर सबसे विश्वसनीय रिपोर्ट माना जाता है. इस रिपोर्ट में मेंढकों की प्रजातियों का ख़ास तौर पर ज़िक्र है और कहा गया है कि इनकी 6,285 प्रजातियों में से 1,895 विलुप्त होने की कगार पर हैं. उदाहरण के तौर पर किहांसी स्प्रे टोड एक ऐसा मेंढक है, जो पहले ख़तरे में था और अब विलुप्त हो चुकी प्रजातियों की श्रेणी में आ गया है. तनज़ानिया में पाया जाने वाला यह मेंढक इसलिए लुप्त हुआ, क्योंकि जहां इसका बसेरा होता था, वहां नदी के ऊपरी हिस्से पर बांध बना दिया गया और पानी के बहाव में 90 प्रतिशत की कमी आ गई.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

ऐसा नहीं है कि चीन में पहली बार ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट ने कोई हिंसक कार्रवाई की है और उसके तार पाकिस्तान से जोड़े गए हैं.

ड्रैगन के निशाने पर पाक

राजीव कुमार

भारत सालों से पाकिस्तान में आतंकी अड्डे और आतंकियों की शरणस्थली होने की बात कहता आ रहा है, लेकिन अमेरिका सहित दुनिया को इस बात में तब दम नज़र आया जब ओसामा बिन लादेन के ठिकाने के बारे में पता चला. अब चीन के जिनजियांग प्रांत में आतंकी हमले हुए तो वह भी पाकिस्तान पर आरोप लगा रहा है. चीन के जिनजियांग प्रांत में हिंसक घटनाओं में 20 लोगों की मृत्यु हो गई. मरने वालों में एक पुलिस अधिकारी भी शामिल था. 30 जुलाई की रात को पाक अधिकृत कश्मीर के पास स्थित चीन के एक शहर काशगर में एक ट्रक ड्राइवर की हत्या कर वाहन पर क़ब्ज़ा कर लिया गया और लोगों को रौंद डाला गया, जिसमें सात लोगों की मौत हो गई. इसके अगले दिन ही इसी शहर में एक बम विस्फोट में 7 और लोगों की मौत हो गई. यह विस्फोट एक रेस्तरां में किया गया. इस विस्फोट को अंजाम देने वाले 5 लोगों को पुलिस ने मार गिराया. ये लोग ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के सदस्य बताए गए हैं. काशगर प्राधिकरण का कहना है कि इन 5 लोगों में एक व्यक्ति को पाकिस्तान के एक शिविर में बम बनाने का प्रशिक्षण दिया गया था.

इससे पहले भी जिनजियांग प्रांत में साल 2009 में भीषण दंगे हुए थे, जिसमें 200 लोग मारे गए थे. इस घटना के बाद चीन ने उइगर मुस्लिम अलगाववादियों के ख़िलाफ़ अभियान शुरू कर दिया था. इसी साल 18 जुलाई को प्रांत के होतान शहर में 14 दंगाई उस समय मारे गए, जब उन्होंने एक पुलिस थाने को निशाना बनाने की कोशिश की थी. लेकिन यह पहली बार है जब चीन ने चरमपंथी शिविरों के मामले में अपने सहयोगी पाकिस्तान पर उंगली उठाई हो. चीन का काशगार प्रांत पाकिस्तान कश्मीर से सटा हुआ है और दोनों देशों के बीच व्यापार इसी सीमा से होता है. इसी के साथ ही चीन की ओर से पाकिस्तान पर आतंकवादियों को संरक्षण देने की बात कही गई. इसके साथ ही ऐसा लगने लगा कि पाकिस्तान और चीन के बीच रिश्तों में खटास आ जाएगी. इस बीच पाकिस्तान की तरफ़ से भी बयान आने लगे कि वह चीन के जिनजियांग प्रांत में सक्रिय आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाई में वह चीन के साथ है. पाकिस्तान ने चीन की ओर से लगे आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और कहा है कि आतंकवाद की सभी घटनाएं निंदनीय हैं और कहा कि पाकिस्तान ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के ख़िलाफ़ चीन की सरकार का समर्थन और सहयोग करता रहेगा. यही नहीं पाकिस्तान ने चीन के साथ कूटनीतिक रिश्ते सुधारने के लिए अपनी ख़ुफ़िया एजेंसी आईएसआई के प्रमुख ले. जे. शुजा पाशा को चीन के दौरे पर भेज दिया. यह गोपनीय दौरा है, जिसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है और शायद इसी का नतीजा है कि जिनजियांग में सक्रिय चरमपंथियों के पाकिस्तान से आने की बात करने के कुछ ही दिन बाद चीन ने चरमपंथ के ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तान को अपना साथी बताते हुए पाकिस्तान की सराहना की है. चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान चरमपंथ के ख़िलाफ़ कार्रवाई में चीन का एक मज़बूत साथी है. चीनी विदेश विभाग से जारी इस वक्तव्य में उस बयान का कोई ज़िक्र नहीं है, जिसमें चीन के काशगर क्षेत्र के अधिकारियों ने चीन में सक्रिय चरमपंथियों के पाकिस्तान में प्रशिक्षण पाने की बात कही थी.

ऐसा नहीं है कि चीन में पहली बार ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट ने कोई हिंसक कार्रवाई की है और उसके तार पाकिस्तान से जोड़े गए हैं. पहले भी चीन ने पाकिस्तान को उइगर विद्रोहियों की मदद न करने और अपने यहां के प्रशिक्षण शिविरों में उन्हें प्रशिक्षण लेने से रोकने के लिए कार्रवाई करने की मांग की है. चीन ने पाकिस्तान के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास भी किया था और इसके पीछे उसका जो हित था वह यही था कि बाद में दोनों देश की साझा कार्रवाई द्वारा ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट का ख़ात्मा किया जा सकेगा. लेकिन अभी तक न तो पाकिस्तान ने इस पर कोई विशेष ध्यान दिया और न ही चीन ने पाकिस्तान का साथ छोड़ा. चीन को भी पता है कि वह पाकिस्तान को सहयोग देना नहीं छोड़ सकता, क्योंकि पाकिस्तान के साथ संबंध वह इस कारण नहीं रखता कि इस देश से उसे कोई विशेष लगाव है बल्कि उसे भारत के विरुद्ध एक हथियार के रूप में देखता है. जब तक चीन भारत के विरुद्ध अपना वैमनस्य जारी रखेगा तब तक उसे पाकिस्तान के सहयोग की आवश्यकता रहेगी और वह पाकिस्तान के विरुद्ध कोई कड़ी कार्रवाई नहीं कर सकता. लेकिन अंतरराष्ट्रीय राजनीति की यह मांग है कि चीन पाकिस्तान को ऐसा कहे और चूंकि अभी पाकिस्तान पर अमेरिका ने भी कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं, इसी कारण पाकिस्तान भी चीन के इस आरोप को गंभीरता से ले रहा है.

पहले भी चीन ने पाकिस्तान को उइगर विद्रोहियों की मदद न करने और अपने यहां के प्रशिक्षण शिविरों में उन्हें प्रशिक्षण लेने से रोकने के लिए कार्रवाई करने की मांग की है. चीन ने पाकिस्तान के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास भी किया था और इसके पीछे उसका जो उसका हित था वह यही था कि बाद में दोनों देशों की साझा कार्रवाई द्वारा ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट का ख़ात्मा किया जा सकेगा, लेकिन अभी तक न तो पाकिस्तान ने इस पर कोई विशेष ध्यान दिया और न ही चीन ने पाकिस्तान का साथ छोड़ा.

feedback@chauthiduniya.com

चीन में अल्पसंख्यकों की स्थिति

सूचना तकनीक के युग में भी यह जान पाना आसान नहीं है कि चीन में अल्पसंख्यकों की स्थिति क्या है? वजह, चीन का सूचना प्रवाह पर कड़ी नज़र का होना है. चीन के अल्पसंख्यकों के बारे में बाहरी दुनिया को कम ही पता चल पाता है. चीन इस मामले में भी साज़िश करने से पीछे नहीं रहता. चीनी सरकार कई बार तस्वीरों के ज़रिए यह साबित करती रही है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग पारंपरिक वेशभूषा में कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होते हैं. लेकिन वास्तविक विश्वविद्यालय में पूर्वी एशिया मामलों के जानकार पीटर फर्डीनेंड का कहना है कि चीन की आर्थिक प्रगति ने पिछले कुछ वर्षों में नस्लीय संबंधों की परिभाषा बदल डाली है. सुधारों के कारण लोगों के आने जाने पर लगे कई प्रतिबंध हटे हैं और अब अल्पसंख्यक लोग शहरों तक आ रहे हैं तथा अपनी बात रख रहे हैं. अब चीन की संसद में भी अल्पसंख्यक लोग जा रहे हैं और सरकार की कई नीतियों का उन्होंने विरोध भी किया है. कई प्रांतों में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को नौकरियों में आरक्षण मिल रहा है और जन्म संबंधी कठोर नीतियां उन पर लागू नहीं हैं. अल्पसंख्यकों को इस तरह के फ़ायदे देने से बहुसंख्यक हान समुदाय काफ़ी नाराज़ भी है. हान समुदाय बाक़ी अन्य समुदायों को असभ्य मानते हैं और उन्हें चीन के लिए बड़ा ख़तरा भी समझते हैं. एक और समस्या यह हुई है कि हान लोगों के पूरे चीन में तेज़ी से फैलने के कारण अल्पसंख्यक लोगों की स्थिति ख़राब हो रही है. ख़ास कर तिब्बत और जिनजियांग प्रांत में जहां धार्मिक और नस्ली तनाव सबसे अधिक है. सराकर को डर है कि इस तरह के तनाव से चीन की भौगोलिक एकता को ख़तरा हो सकता है. वर्तमान समय में चीन के लिए पूरी एकता और अखंडता बनाए रखना और भी ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अब चीन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी शक्ति के रूप में ख़ुद को तक़रीबन स्थापित कर चुका है.

देश का पहला इंटरनेट टीवी
हर दिन 50,000 से ज़्यादा दर्शक
दो टूक-संतोष भारतीय के साथ
ब्लैक एंड व्हाइट रोज़ाना 1 बजे
पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया
स्पेशल रिपोर्ट
नायाब हैं हम-उर्दू के मशहूर शायरों, गीतकारों के साथ मुलाक़ात
साई की महिमा

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301 www.chauthiduniya.tv

बाबा के स्वभाव से भलीभांति परिचित अंतरंग भक्त भला इन अपशब्दों का कब बुरा मानने वाले थे. बाबा के इन शब्दों-वाक्यों को उन्होंने आर्शीवाद समझा.

बाबा का समभाव

बाबा तो अंतर्यामी थे. उन्हें तो सब ज्ञान था कि वाड़े में क्या-क्या हो रहा है. बाबा ने महाजनी से प्रश्न किया कि वहां क्या चल रहा था. इस आकस्मिक प्रश्न से महाजनी घबरा गए. भीष्म ने रामनवमी उत्सव मनाने का विचार बाबा के समक्ष प्रस्तुत किया और स्वीकृति देने की प्रार्थना की. बाबा ने भी सहर्ष अनुमति दे दी. सभी भक्त हर्षित हुए और रामजन्मोत्सव मनाने की तैयारियां करने लगे. दूसरे दिन रंग-बिरंगी झंडियों से मस्जिद सज़ा दी गई.

वर्ष 1911 में एक भक्त कृष्णराव जोगेश्वर भीष्म (श्री साई सगुणोपासना के लेखक) अमरावती के दादा साहेब खापर्डे के साथ मेले के एक दिन पूर्व शिरडी के दीक्षित वाड़े में ठहरे. जब वह दालान में लेटे हुए विश्राम कर रहे थे, तब उन्हें एक कल्पना सूझी. उसी समय लक्ष्मणराव उर्फ काका महाजनी पूजन सामग्री लेकर मस्जिद की ओर जा रहे थे. उन दोनों में विचार विनिमय होने लगा और उन्होंने सोचा कि शिरडी में उर्स एवं मेला ठीक रामनवमी के दिन होता है, इसमें अवश्य ही कोई गूढ़ रहस्य निहित है. रामनवमी का दिन हिंदुओं को बहुत ही प्रिय है. कितना अच्छा हो, यदि रामनवमी उत्सव (अर्थात श्रीराम का जन्म दिवस) का भी श्रीगणेश कर दिया जाए. काका महाजनी को यह विचार रुचिकर प्रतीत हुआ. अब मुख्य कठिनाई हरिदास के मिलने की थी, जो इस शुभ अवसर पर कीर्तन एवं ईश्वर गुणानुवाद कर सके, परंतु भीष्म ने इस समस्या को हल कर दिया. उन्होंने कहा कि मेरा स्वरचित राम आख्यान, जिसमें राम जन्म का वर्णन है, तैयार हो चुका है. मैं उसका ही कीर्तन करूंगा और तुम हारमोनियम पर साथ करना तथा राधाकृष्ण माई सुंठवड़ा (सोंठ का शक्कर मिश्रित चूर्ण) तैयार कर देंगी. दोनों तुरंत बाबा की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु मस्जिद की तरफ़ चल दिए.

बाबा तो अंतर्यामी थे. उन्हें तो सब ज्ञान था कि वाड़े में क्या-क्या हो रहा है. बाबा ने महाजनी से प्रश्न किया कि वहां क्या चल रहा था. इस आकस्मिक प्रश्न से महाजनी घबरा गए. भीष्म ने रामनवमी उत्सव मनाने का विचार बाबा के समक्ष प्रस्तुत किया और स्वीकृति देने की प्रार्थना की. बाबा ने भी सहर्ष अनुमति दे दी. सभी भक्त हर्षित हुए और रामजन्मोत्सव मनाने की तैयारियां करने लगे. दूसरे दिन रंग-बिरंगी झंडियों से मस्जिद सजा दी गई. राधाकृष्ण माई ने एक पालना लाकर बाबा के आसन के समक्ष रख दिया और फिर उत्सव प्रारंभ हो गया. भीष्म कीर्तन करने को खड़े हो गए और महाजनी हारमोनियम पर उनका साथ करने लगे. तभी बाबा ने महाजनी को बुलावा भेजा. यहां महाजनी शंकित थे कि बाबा उत्सव मनाने की आज्ञा देंगे भी या नहीं, परंतु जब वह बाबा के समीप पहुंचे तो बाबा ने उनसे प्रश्न किया, यह सब क्या है, यह पालना क्यों रखा गया है? महाजनी ने बताया कि रामनवमी का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया और इसी कारण यह पालना यहां रखा गया. बाबा ने निंबर पर से दो हार उठाए. उनमें से एक हार तो उन्होंने काका जी के गले में डाल दिया और दूसरा भीष्म के लिए भेज दिया. अब कीर्तन प्रारंभ हो गया था. कीर्तन समाप्त हुआ, तब श्री राजाराम की उच्च स्वर से जय-जयकार हुई. कीर्तन स्थल पर गुलाल की वर्षा की गई. जब हर कोई प्रसन्नता से झूम रहा था, अचानक एक गरजती हुई ध्वनि उनके कानों में पड़ी. जिस समय गुलाल की वर्षा हो रही थी तो उसमें से कुछ कण अनायास ही बाबा की आंख में चले गए. तब बाबा एकदम क्रुद्ध होकर उच्च स्वर में अपशब्द कहने और कोसने लगे. यह दृश्य देखकर सब लोग भयभीत होकर सिटपिटाने लगे. बाबा के स्वभाव से भलीभांति परिचित अंतरंग भक्त भला इन अपशब्दों का कब बुरा मानने वाले थे. बाबा के इन शब्दों-वाक्यों को उन्होंने आर्शीवाद समझा.

उन्होंने सोचा कि आज राम का जन्मदिन है, अत: रावण का नाश, अहंकार एवं दुष्ट प्रवृत्ति रूपी राक्षसों का संहार करने के लिए बाबा को क्रोध उत्पन्न होना सर्वथा उचित है. इसके साथ-साथ उन्हें यह विदित था कि जब कभी भी शिरडी में कोई नवीन कार्यक्रम रचा जाता था, तब बाबा इसी प्रकार कुपित हो जाते थे. इधर राधाकृष्ण माई भयभीत थीं कि कहीं बाबा पालना न तोड़-फोड़ डालें, इसलिए उन्होंने काका महाजनी से पालना हटाने के लिए कहा, परंतु बाबा ने ऐसा करने से उन्हें रोका. कुछ समय पश्चात बाबा शांत हो गए और उस दिन की महापूजा और आरती का कार्यक्रम विधिवत संपन्न हो गया. इसके बाद काका महाजनी ने बाबा से पालना उतारने की अनुमति मांगी, परंतु बाबा ने कहा कि अभी उत्सव संपूर्ण नहीं हुआ है. अगले दिन गोपाल काला उत्सव मनाया गया, उसके बाद बाबा ने पालना उतारने की आज्ञा दे दी. उत्सव में दही मिश्रित पौहा एक मिट्टी के बर्तन में लटका दिया जाता है और कीर्तन समाप्त होने पर वह बर्तन फोड़ दिया जाता है तथा प्रसाद के रूप में वह पौहा सबको वितरित कर दिया जाता है, जिस प्रकार श्रीकृष्ण ने ग्वालों के साथ किया था. राम नवमी उत्सव इसी तरह दिन भर चलता रहा. दिन के समय दो ध्वजों वाला और रात्रि के समय चंदन का जुलूस बड़ी धूमधाम के साथ निकाला गया. इसके साथ ही उर्स का उत्सव राम नवमी के उत्सव में परिवर्तित हो गया. अगले वर्ष (1912) से राम नवमी के कार्यक्रमों की सूची में वृद्धि होने लगी. राधाकृष्ण माई ने चैत्र की प्रतिपदा से नाम सप्ताह प्रारंभ कर दिया. (लगातार दिन-रात 7 दिनों तक भगवत नाम लेना नाम सप्ताह कहलाता है) सभी भक्त इसमें बारी-बारी से भाग लेते थे. वह भी प्रात:काल सम्मिलित हो जाती थीं. देश के सभी भागों में राम नवमी का उत्सव मनाया जाता है. इसलिए अगले वर्ष हरिदास के मिलने की कठिनाई पुन: उपस्थित हुई, परंतु उत्सव के पूर्व ही यह समस्या हल हो गई. पांच-छह दिन पहले महाजनी की बाला बुवा साहेब से अकस्मात भेंट हो गई.

बुवा साहेब आधुनिक तुकाराम के नाम से प्रसिद्ध थे और इस वर्ष कीर्तन का कार्य उन्हें ही सौंपा गया. अगले वर्ष 1913 में श्री हरिदास (सातारा ज़िले के बाला बुवा सातारकर) बृहदिसद्ध कवटे ग्राम में प्लेग का प्रकोप होने के कारण अपने गांव में हरिदास का कार्य नहीं कर सकते थे. इस वर्ष वह शिरडी में आए. काका साहेब दीक्षित ने उनके कीर्तन के लिए बाबा से अनुमति प्राप्त की. बाबा ने भी उन्हें यथेष्ट पुरस्कार दिया. 1914 से हरिदास की कठिनाई बाबा ने सदैव के लिए हल कर दी. उन्होंने यह कार्य स्थायी रूप से दासगणू महाराज को सौंप दिया. तबसे वह इस कार्य को उत्तम रीति से सफलता और विद्वतापूर्वक निभाते रहे. 1912 से उत्सव के अवसर पर लोगों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी. चैत्र शुक्ल अष्टमी से द्वादशी तक शिरडी में लोगों की संख्या में इतनी अधिक वृद्धि हो जाती थी, मानो मधुमक्खी का छत्ता लगा हो. दुकानों की संख्या में बढ़ोत्तरी हो गई. प्रसिद्ध पहलवानों की कुश्तियां होने लगीं. गरीबों को बड़े पैमाने पर भोजन कराया जाने लगा. राधाकृष्ण माई के घोर परिश्रम के फलस्वरूप शिरडी को संस्थान का रूप मिला, संपत्ति भी दिन-प्रतिदिन बढ़ने लगी. एक सुंदर घोड़ा, पालकी, रथ, चांदी के बर्तन और शीशे आदि भक्तों ने उपहार में दिए. उत्सव के अवसर पर हाथी भी बुलाया जाता था. यद्यपि संपत्ति बहुत बढ़ी, परंतु बाबा सदा साधारण वेशभूषा धारण करते थे. यह ध्यान देने योग्य है कि जुलूस एवं उत्सव में हिंदू और मुसलमान दोनों ही साथ-साथ कार्य करते थे, परंतु न उनमें कोई विवाद हुआ और न कोई मतभेद. शुरुआत में लोगों की संख्या 5000-7000 के लगभग होती थी, परंतु किसी-किसी वर्ष यह संख्या 75,000 तक पहुंच जाती थी. फिर भी न कभी कोई बीमारी फैली और न कोई दंगा हुआ.

श्री सद्गुरु साई बाबा के ग्यारह वचन

1. जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
2. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर.
3. त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4. मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5. मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो.
6. मेरी शरण आ ख़ाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7. जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8. भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9. आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर.
10. मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11. धन्य-धन्य व भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

श्री साई महिमा

श्री साई राम परम सत्य, प्रकाश रूप, परम पावन शिरडी निवासी, परम ज्ञान आनंद स्वरूप, प्रज्ञा प्रदाता, सच्चिदानंद स्वरूप, परम पुरुष योगीराज, दयालु देवाधिदेव हैं, उनको बार-बार नमस्कार.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

भूचाल अपने शीर्षक और कथानक दोनों ही मायनों में बहुअर्थी कहानी है. आम आदमी समाज के साधन संपन्न लोगों द्वारा किस तरह निरीह बना दिया जाता है, उसकी ज़बरदस्त प्रस्तुति हम यहां पाते हैं.

अनंत विजय

...किसी से हो नहीं सकता

हर साल 31 जुलाई हिंदी साहित्य के लिए एक बेहद ख़ास दिन होता है. इस दिन हिंदी के महान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद का जन्मदिन होता है, लेकिन हिंदी पट्टी में अपने इस गौरव को लेकर कोई उत्साह देखने को मिलता हो, यह ज्ञात नहीं है. प्रेमचंद के गांव लमही में कुछ सरकारी किस्म के कार्यक्रम हो जाते हैं, जिनमें मंत्री वग़ैरह भाषण देकर रस्म अदायगी कर लेते हैं. इस बार भी वहां कुछ वैसा ही हुआ. लेकिन तक़रीबन पिछले पच्चीस सालों से हंस पत्रिका प्रेमचंद के जन्मदिन पर दिल्ली में एक विचार गोष्ठी का आयोजन करती रही है. इस बार भी उसने किया. राजेंद्र यादव के संपादन में निकलते हुए इस पत्रिका के पच्चीस साल हो गए हैं, लिहाज़ा मौक़ा ख़ास था. हंस की रजत जयंती वर्ष और प्रेमचंद की जयंती. दिल्ली के ऐवान-ए-ग़ालिब के हॉल में हंस और साहित्यिक पत्रकारिता पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया था. हर साल की तरह इस वर्ष भी साहित्यिक जमात का ठीकठाक जमावड़ा लगा था. हर तबके के लेखक वहां मौजूद थे. दो- तीन पीढ़ियों

के लेखक तो थे ही. मैं जब पहुंचा तो उसके कुछ देर बाद बांग्लादेश की विवादास्पद लेखिका तस्लीमा नसरीन भी वहां आईं. तसलीमा के साथ एक सुरक्षाकर्मी भी था. लेकिन मैं यह देखकर हैरान रह गया कि तसलीमा को काफी देर तक खड़ा रहकर इधर-उधर देखना पड़ा. उनको लेकर वहां मौजूद लोगों में कोई उत्साह नहीं दिखा. कुछ देर जब वह अकेली खड़ी रहीं तो फिर किसी ने उन्हें हॉल का रास्ता दिखाया. यह वही तसलीमा थीं, जो तक़रीबन दस साल पहले वाणी प्रकाशन के एक कार्यक्रम में दिल्ली आई थीं तो लगा था कि राजधानी में कोई घटना घटी हो. दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के हॉल में तिल रखने की जगह नहीं थी. देशी-विदेशी मीडिया के दर्जनों कैमरे और पत्रकार तो वहां मौजूद थे ही, हिंदी का बड़ा से बड़ा लेखक भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने को बेताब था. तस्लीमा की एक झलक पाने के लिए लोग उतावले हो रहे थे, तस्लीमा के साथ फोटो खिंचवाने के लिए लोग सिफारिश कर रहे थे हमारे मित्र अरुण महेश्वरी से, लेकिन उस वक़्त अपने आयोजन की सफलता से गदगद अरुण जी ने लोगों को छोड़ दिया और तसलीमा के साथ अशोक वाजपेयी और कुंवर नारायण को लेकर लंच के लिए चले गए. जब तक तसलीमा वहां रहीं, कैमरे का फ्लैश बंद होने का नाम नहीं ले रहा था. जींस और टी शर्ट पहने छरहरी काया की तस्लीमा अपने स्वागत से भावविभोर थीं, लेकिन सिर्फ़ दस साल में माहौल कितना बदल गया. तस्लीमा दिल्ली की उसी साहित्यिक जमात के बीच खड़ी थीं, लेकिन उनका कोई नोटिस नहीं ले रहा था. वजह चाहे जो भी हो. ख़ैर, यह एक अलग बात है, जो प्रसंगवश मैं कह गया. हम बात कर रहे थे हंस के 25 साल पूरे होने की. राजेंद्र यादव ने कार्यक्रम की शुरुआत की और हंस के शुरुआती दिनों के अपने दोस्तों-लालानी जी और गौतम नवलखा आदि को शिद्दत से याद किया. छोटा सा भाषण भी दिया और टॉलस्टॉय की एक कहानी भी सुनाई. मैं लंबे समय से राजेंद्र जी को सुनता आ रहा हूं. उस दिन पहली बार लगा कि पाइप और सिगरेट के कश ने उनको काफी कमज़ोर कर दिया है. हिंदी साहित्य का अस्सी साल का यह जवान शारीरिक रूप से भले ही कमज़ोर लग रहा हो, लेकिन हौसले अब भी बुलंद नज़र आ रहे थे. राजेंद्र यादव ने अपना भाषण समाप्त कर हिंदी के दलित लेखक अजय नावरिया को मंच संचालन के लिए बुला लिया. यहीं से समारोह की गरिमा ख़त्म होने की शुरुआत हो गई. अजय नावरिया ने बेहद मसखरेपन के साथ मंच संचालन शुरू किया. मंच संचालन इतना ख़राब था कि उसकी चर्चा करना समय बर्बाद करना है, लेकिन जिस अपमानजनक तरीक़े की टिप्पणी अजय ने अपने मंच संचालन के दौरान की, उसके लिए उसे कम से कम दुर्गा से तो माफी मांगनी ही चाहिए. दुर्गा प्रसाद राजेंद्र जी के पुराने सहयोगी हैं. उन्हें भी इस मौक़े पर सम्मानित किया गया. स्मृति चिन्ह के साथ एक लिफाफा दिया गया. गिफ्ट देते वक़्त अजय ने कहा कि दुर्गा जी को दो पैंट-शर्ट का कपड़ा दिया जा रहा है, जो उनके लिए उपयोगी है. वह इतने पर ही नहीं रुका, उसने सार्वजनिक रूप से दुर्गा की खुराक के बारे में टिप्पणी कर डाली. काफी देर तक साहित्यिक जमात ने अजय को झेला, लेकिन जब लोगों का धैर्य जवाब दे गया तो कुछ उत्साही लोगों ने उसे हूट कर बैठा दिया. भीड़ जब तक इंसाफ कर पाती, तब तक अजय नावरिया ने साहित्यिक समारोह की गरिमा को समूल रूप से नष्ट कर दिया था. काफी देर तक चले मसखरेपन के बाद लालानी जी ने बोलना शुरू किया. उन्होंने राजेंद्र यादव के साथ अपने शुरुआती दिनों को याद किया. बोले तो गौतम नवलखा और अर्चना वर्मा भी. दोनों ने बेहद संक्षिप्त बोला और सिर्फ़ हंस की तारीफ़ों के पुल बांधे. अर्चना वर्मा ने हंस के साथ बिताए अपने दिनों के बारे में बताया कि किस तरह वह सिर्फ़ परख देखने के लिए हंस में आई थीं और किस तरह उनसे कहानी और फिर कम पड़ रहे लेख भी लिखवाए जाने लगे.

इसके बाद बारी थी हिंदी के हीरामन नामवर सिंह की. नामवर जी को हंस और साहित्यिक पत्रकारिता पर बोलना था, लेकिन बोले वह सिर्फ़ हंस पर. शुरुआत तो उन्होंने मेरे दुश्मन राजेंद्र यादव से की, लेकिन उसके बाद उन्होंने राजेंद्र यादव के हौसले की ज़बरदस्त तारीफ़ की. सार्वजनिक रूप से अपनी तारीफ़ सुनकर मंच पर बैठे यादव जी का चेहरा लाल-लाल हो रहा था. शरमा इस तरह रहे थे, जैसे कोई नई-नवेली दुल्हन शर्माती है, लेकिन नामवर जी तो अपनी रौ में थे. अपने विरोधियों को अपनी पत्रिका में जगह देने के लिए भी उन्होंने यादव जी की नामवरी अंदाज़ में सराहना की. उसी नामवरी अंदाज़ में अशोक वाजपेयी पर हमला भी बोला. नामवर जी ने कहा कि अशोक जब पूर्वाग्रह के संपादक थे तो अपने पूर्वाग्रहों के साथ उसका संपादन करते थे. उन्होंने कभी राजेंद्र यादव को पत्रिका में नहीं छापा, लेकिन राजेंद्र ने हंस के छब्बीसवें वर्ष के पहले अंक में अशोक वाजपेयी से ही लिखवाया. बोलते-बोलते नामवर सिंह ने अशोक वाजपेयी को कायर और यादव जी को बहादुर क़रार दे दिया. नाम तो रवींद्र कालिया और अखिलेश का भी आया. नामवर सिंह बहुत कम बोले. साहित्यिक पत्रकारिता पर भी प्रकाश डालते तो मौजूद श्रोताओं का ज्ञानवर्द्धन होता. उसके बाद कुछ सवाल-जवाब भी हुए, लेकिन नामवर सिंह ने एक जोरदार शेर के साथ अपनी बात ख़त्म की, जो हो सकता है इससे, वह किसी से हो नहीं सकता, मगर देखो तो जो हो सकता है, वह आदमी से हो नहीं सकता.

दिल्ली में हुए इस साहित्यिक जलसे से एक बात साफ हो गई कि राजेंद्र यादव हर उम्र के बीच खासे लोकप्रिय हैं. कार्यक्रम स्थल से बाहर निकलते हुए मैं एक बार फिर सोच रहा था कि अंग्रेजी में अगर किसी लिटरेरी मैगज़ीन के प्रकाशन के पच्चीस साल पूरे होते तो क्या इस तरह का ही समारोह मनाया जाता. जवाब मिला, नहीं. तो फिर हम हिंदी के लोग क्यों नहीं अपने गौरव का सम्मान कर पाते हैं, क्यों नहीं हमारा मीडिया इस तरह के समारोह को कवरेज देता है? इन सवालों से जूझता हुआ मैं घर लौट आया. सवाल अब भी मेरा पीछा कर रहे हैं.

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)

anant.ibn@gmail.com

निम्नवर्गीय जीवन संग्राम की कहानियां

मेरे मौला कथाकार डॉ. लालजी प्रसाद सिंह का 20वां कहानी संग्रह है. वैसे वह अब तक हिंदी की विभिन्न विधाओं में 35 किताबें लिख चुके हैं. इस पुस्तक में मेरे मौला, मौत का गीत, मर्सी किलिंग, जगिया और भूचाल आदि पांच कहानियां हैं. जद्दोज़हद इन सभी कहानियों का केंद्रीय भाव रहा है. चाहे मेरे मौला में बाढ़ में ज़िंदगी और मौत से जूझते वे चार बच्चे हों, जो पहले ही अपने माता-पिता को खो चुके हैं और भूख-प्यास झेलते पेड़-पौधों की पत्तियों के सहारे अपनी जीवन नैया खे रहे हैं या मौत का गीत की बासोमनी का पति, जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा में नेताओं को स्त्रियां उपलब्ध कराता है या मर्सी किलिंग का सुंदर, जो कोमा में पड़ी अपनी पत्नी की मर्सी किलिंग के लिए कोर्ट जाता है या जगिया की जगिया हो, जो लंबे वैधव्य के बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश करती है या फिर भूचाल की एतवरिया का बाप, मौत का गीत को छोड़कर सभी किरदार निम्नवर्गीय हैं. उनके जीवन में जद्दोजहद की खाई इतनी गहरी है, जिसे पाटने में यह पितृसत्तात्मक समाज और यह 63 वर्षों की जनतांत्रिक व्यवस्था अक्षम साबित हुई है. लालजी प्रसाद सिंह की कहानियां कभी-कभी यथार्थवाद की हदें पार कर जाती हैं. उनमें कहीं-कहीं अस्वाभाविकता परिलक्षित होने लगती है. संकलन की मौत का गीत इस दृष्टि से सबसे कमज़ोर कहानी है. नायक अपने राजनीतिक आकाओं को स्त्रियां मुहैया कराता है. बदले में वह ठेकेदारी पाता है. बाद में वह भी चुनाव लड़ने की सोचता है. अपनी बेटी के लिए जानबूझ कर मरने की स्थितियां पैदा करता है. इस कहानी पर लेखक की पकड़ बन नहीं पाई है. पुरुष की हिंसात्मक प्रवृत्ति, स्त्री विरोधी खलनायकत्व एवं बेटी की मौत के बाद उसके दांपत्य जीवन में पैदा हुई जद्दोज़हद को पर्याप्त उभार नहीं मिल पाया, कहानी बहुत सपाट बनकर रह गई.

भूचाल अपने शीर्षक और कथानक दोनों ही मायनों में बहुअर्थी कहानी है. आम आदमी समाज के साधन संपन्न लोगों द्वारा किस तरह निरीह बना दिया जाता है, उसकी जबर्दस्त प्रस्तुति हम यहां पाते हैं. एतवरिया

डॉ. लालजी प्रसाद सिंह

समीक्ष्य कृति- मेरे मौला
लेखक- डॉ. लालजी प्रसाद सिंह
प्रकाशक - लालजी साहित्य प्रकाशन, पटना, बिहार
मूल्य- पेपरबैक 75 रुपये/ साजिल्द 225 रुपये

का बाप भूखल स्कूल में नौकरी की प्रत्याशा में चपरासी के रूप में काम करता है. हेडमास्टर अपने निजी काम के निमित्त उसे झूठा आश्वासन देता है कि वह उसकी नौकरी पक्की कर देगा. नौकरी के सिलसिले में ही भूखल मंत्री के बंगले पर पहुंचता है और वहां वह उनकी गायों का गोबर तक साफ करता है. कहानी का नायक हर जगह ठगा जाता है. उसने अपनी बीमार बेटी के इलाज के लिए किसी से क़र्ज़ लिया. एक अजनबी व्यक्ति उसकी वह रकम यह विश्वास दिलाते हुए ले जाता है कि आज से ठीक आठवें रोज शहर में भूचाल आएगा. उस वक़्त मेरा आदमी तुमसे मिलेगा और तुम्हारा सारा काम ठीक कर देगा, लेकिन जब ऐसा होता नहीं दिखता है, तब वह अपनी गाय के पास बैठकर मंत्र पढ़ता है. उसका विश्वास है कि गाय माता ही उसे इस गड्डमड्ड हालत से मुक्ति का संकेत दे सकती हैं. इधर उसकी बेटी और पत्नी उसे इस तरह एकांत में बड़बड़ाते हुए देखकर सोचती हैं कि कहीं वह पागल तो नहीं हो गया.

जगिया कहानी समाज में एक विधवा स्त्री के त्रासद अनुभव को लक्ष्य करती है. कहानीकार ने विधवाओं की परंपरागत दुर्गति के कारणों को भी जहां-तहां सूत्रवाक्य में पिरोया है. हालांकि वैसे स्थलों पर कहानी कमजोर पड़ने लगती है. विधवा जगिया अपने से बहुत कम उम्र के कलुआ से सेक्स की भूख मिटाती है और गर्भवती हो उठती है और उससे शादी का निर्णय लेती है. इस निर्णय से उसकी संतानों समेत पूरा समाज विरोध में उठ खड़ा होता है. मर्सी किलिंग कहानी का नायक सुंदर अभाव का जीवन जी रहा है. गांव के ही संतानहीन विधुर बाढ़ दादा की पहल पर सुगनी से उसकी शादी होती है. उसकी पत्नी अपनी व्यवहारिकता से बाढ़ दादा का दिल जीत लेती है और वह अपने कुत्ते के साथ इस परिवार के अभिन्न अंग हो जाते हैं. लेकिन होली के मौक़े पर हंसी-ठिठोली में सुगनी का सिर दरवाजे की चौखट से टकराता है तो वह कोमा में चली जाती है. सुंदर की तीजिया नामक एक बेटी भी है. वह पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराता है. इलाज में उसकी जमीन भी बिक जाती है, लेकिन फिर भी पत्नी होश में नहीं आती. वह उसे घर ले आता है. जब अर्से तक वह होश में नहीं आती तो वह कोर्ट में उसकी मर्सी किलिंग के लिए याचिका दायर करता है. बाढ़ दादा उसकी इस हरकत से बहुत व्यथित होते हैं. इस बीच एक दिन सुंदर देखता है कि उसकी बेटी तीजिया दूध की तलाश में सुगनी के स्तनों को लहूलुहान कर देती है.

संग्रह की पहली और शीर्षक कहानी है, मेरे मौला. बाढ़ की विभीषिका में अपने अम्मी-अब्बू को गंवाए चार नन्हे मुस्लिम बच्चों की जिजीविषा को यह कहानी तार्किक और मार्मिक ढंग से आगे बढ़ाती है. चारों बच्चे टापू पर घिर चुके हैं, पर वे जूझना नहीं छोड़ते. वे प्रलय के बीच रोजा रखते हैं. इस संकट की घड़ी में कोई नौका या राहत की कोई चीज उन्हें नज़र आती है तो उसे वे अल्लाह की रहमत मानते हैं.

अरुण नारायण
feedback@chauthiduniya.com

किताब मिली

पुस्तक का नाम
स्वामी विवेकानन्द के सपनों का भारत

लेखक
हिमांशु शेखर

प्रकाशक
डायमंड बुक्स

मूल्य
125 रुपये

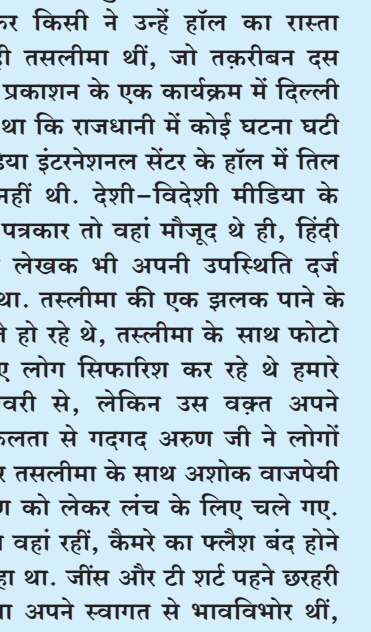

इस किताब में विभिन्न मुद्दों पर स्वामी विवेकानन्द के विचारों को पेश किया गया है.

सभी के लिए उपयोगी पुस्तकें

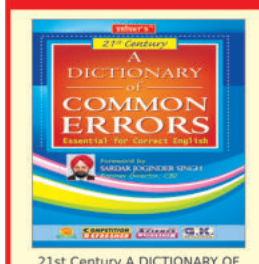

21st Century A DICTIONARY OF COMMON ERRORS ₹ 99

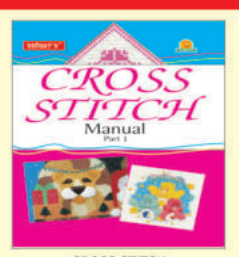

CROSS STITCH Manual Part - 1 ₹ 60

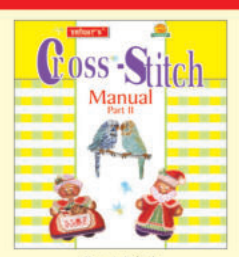

Cross-Stitch Manual Part - II ₹ 70

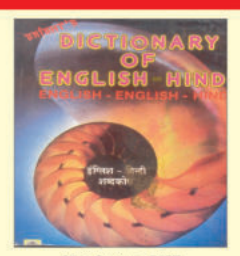

21st Century DICT ENGLISH - HINDI ₹ 75

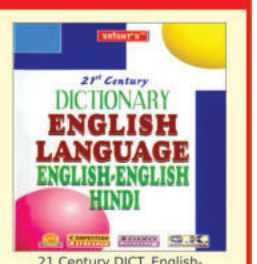

21 Century DICT. English-English-Hindi ₹ 125

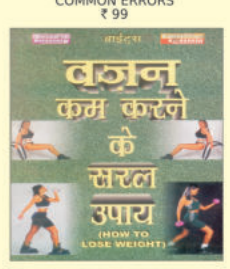

व्जन कम करने के सरल उपाय ₹ 50

इंगलिश सीखिए और बोलिए ₹ 199

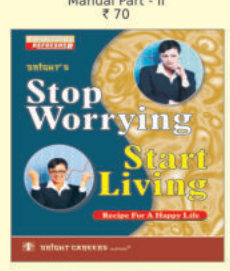

Stop Worrying Start Living ₹ 50

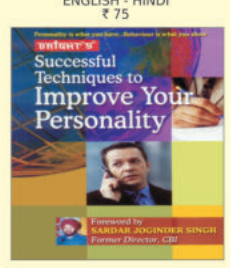

Successful Techniques to Improve Your Personality ₹ 99

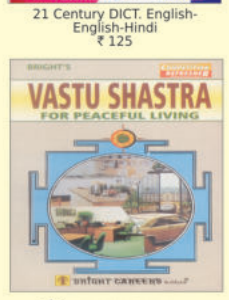

★ VASTU SHASTRA ₹ 70

WORD POWER ₹ 20

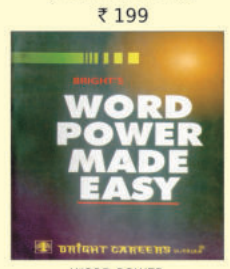

WORD POWER MADE EASY ₹ 80

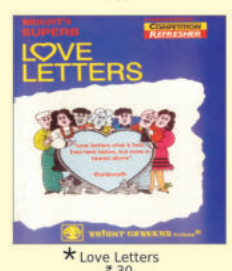

★ Love Letters ₹ 30

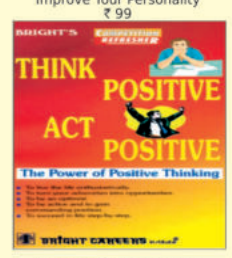

Think Positive Act Positive ₹ 70

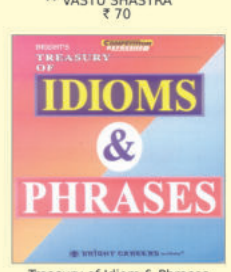

Treasury of Idiom & Phrases ₹ 75

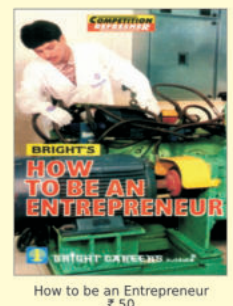

How to be an Entrepreneur ₹ 50

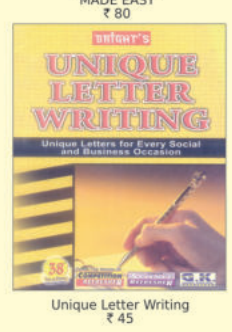

Unique Letter Writing ₹ 45

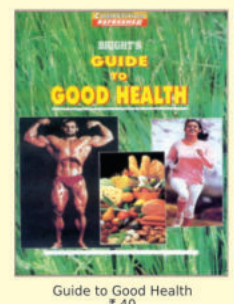

Guide to Good Health ₹ 40

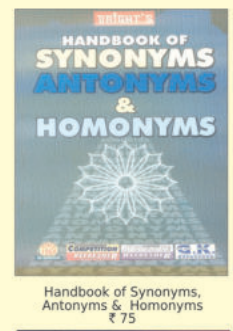

Handbook of Synonyms, Antonyms & Homonyms ₹ 75

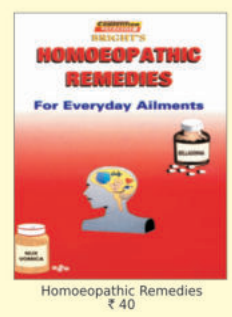

Homoeopathic Remedies ₹ 40

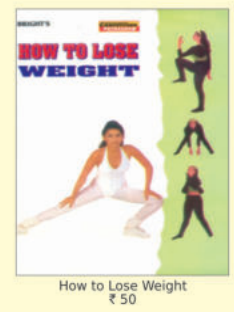

How to Lose Weight ₹ 50

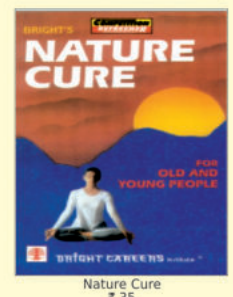

Nature Cure ₹ 35

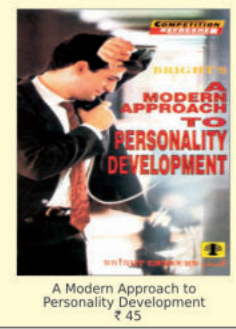

A Modern Approach to Personality Development ₹ 45

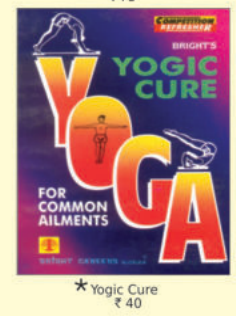

★ Yogic Cure ₹ 40

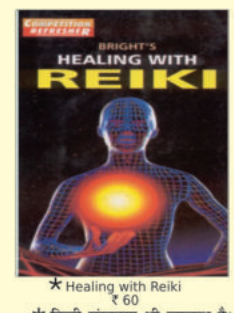

★ Healing with Reiki ₹ 60

★ हिन्दी संस्करण भी उपलब्ध है।

ब्राईट पब्लिकेशंस
भारत में सर्वाधिक बिकने वाली प्रतियोगिता पुस्तकों के प्रकाशक
2767, कूचा चैलान, दरियागंज, दिल्ली-110002 (भारत) (स्थापित : 1968)
फोन : 011-64632226, 23282226, 23283226 —— फैक्स : 011-23269227
ई-मेल: sales@brightpublications.com | वैब साइट: http://www.brightpublications.com

इस दो जीबी की मेमोरी को 32 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है. यह फोन वाई-फाई और जीपीएस सिस्टम को सपोर्ट करता है.

एचपी का पैवेलियन डीएम जेड-1

भारतीय बाज़ार में बेहद सस्ते मोबाइल हैंडसेट्स उतारने के बाद अब कंपनियां कम से कम क़ीमत पर टेबलेट कंप्यूटर उपलब्ध कराने की तैयारी में जुट गई हैं. कंप्यूटर निर्माण क्षेत्र की अग्रणी कंपनी एचपी ने पैवेलियन डीएम जेड-1 नेटबुक लांच की है. 11.7 इंच की इस नोटबुक में माइक्रो प्रोसेसर लगाया गया है. साथ ही 3 जीबी का डीडीआर-3 रैम और 320 जीबी की 7200 आरपीएम हार्ड्राइव भी लगाई गई है. इस नेटबुक में 7 सेल की लीथियम ऑयन की बैट्री लगाई गई है, जो 5 से 7 घंटे का बैकअप देती है. इससे बिजली चले जाने के बाद भी उपभोक्ता काफी समय तक इसका उपयोग कर सकते हैं. कंपनी का कहना है कि यह छात्रों और बिजनेस करने वाले लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है. कंपनी का कहना है कि इसमें और भी कई सुविधाएं दी गई हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

फोटो-सुनील मल्होत्रा

बीट का डीजल वेरिएंट

कारों की बिक्री में आ रही गिरावट को रोकने के लिए कार कंपनियां बड़े पैमाने पर शानदार कारें लांच कर रही हैं. भारतीय कार बाज़ार में कई और कारें पेश की जाएंगी. कंपनियों को उम्मीद है कि इससे कारों की बिक्री तेज होगी. इसी तर्ज पर जनरल मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी छोटी कार बीट का डीजल वेरिएंट बाज़ार में लांच कर दिया है. कंपनी ने इसकी शुरुआती क़ीमत 4.29 लाख रुपये रखी है. बीट का डीजल वेरिएंट 1.0 लीटर इंजन से लैस है, जो जीएम ने खासतौर पर भारतीय बाज़ार के लिए विकसित किया है. यह कार 24 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज ग्राहकों को देगी. कंपनी ने बीट डीजल को तीन श्रेणियों में लांच किया है, जिनकी क़ीमत 4.29-5.45 लाख रुपये के बीच है. बीट डीजल का मुक़ाबला मारुति स्विफ्ट, फोर्ड फिगो, मारुति रिट्ज और फिएट पुंटो के साथ होने की संभावना है. लांच के मौक़े पर जनरल मोटर्स इंडिया के प्रेसिडेंट एवं मैनेजिंग डायरेक्टर कार्ल स्लिम ने कहा कि वैश्विक स्तर पर जीएम की यह सबसे छोटे डीजल इंजन से लैस पैसेंजर कार है. उन्होंने कहा कि कंपनी का फ़िलहाल इस इंजन को दुनिया में कहीं भी निर्माण का इरादा नहीं है. कंपनी इसी इंजन में कुछ तब्दीली करके स्पार्क में भी डीजल वेरिएंट लांच करने पर विचार कर सकती है.

हार्ड्राइव स्टोरेज नो प्रॉब्लम

इस ड्राइव में 800 जीबी तक की स्टोरेज कैपेसिटी है, यह अपने आप डेटा एरर पकड़ती है और उसे सही कर लेती है. इस तरह यह सामान्य ड्राइव ऑपरेशन को आसान बताती है. कीमत और कामकाज के लिहाज़ से भी किफायती है. पल्सर एक्सटी-2 400 जीबी एसएसडी स्टोरेज परफॉर्मेंस काउंसिल या एसपीसी के कठिन मानदंडों पर पूरी तरह खरी उतरी है.

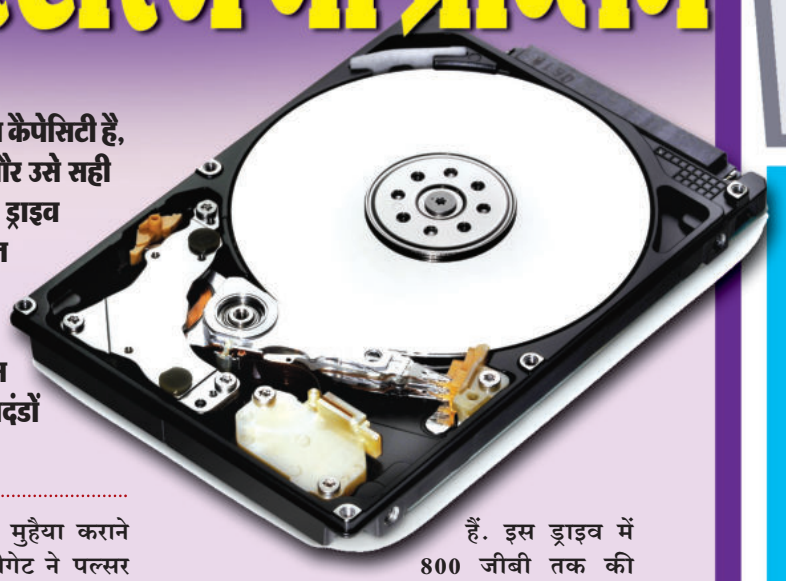

हार्ड्राइव स्टोरेज समाधान मुहैया कराने वाली अग्रणी कंपनी सीगेट ने पल्सर एक्सटी-2 सॉलिड स्ट्रेट ड्राइव (एसएसडी) को वितरण नेटवर्क तक पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है. यह ड्राइव कारोबारी माहौल की दो सबसे बड़ी मांग डेटा इंटीग्रेटी और ड्राइव के टिकाऊपन के लिहाज़ से बेजोड़ है. एंटरप्राइज हार्डड्राइव बनाने वाले की ओर से प्रस्तुत यह पहली मल्टी लेवल सेल और फ्लैश इनेबल्ड एसएसडी पल्सर-2 टीएम है.

पल्सर एक्सटी-2 एसएसडी सिंगल लेवल सेल एसएलसी फ्लैश, 6 जीबी/सेकेंड सीरियल अटैच्ड एससीएसआई एसएएस इंटरफेस से लैस है, जो इसे सीगेट पोर्टफोलियो के अंदर सबसे तेज ड्राइव बनाता है. 2.5 इंच एसएसडी और 400 जीबी तक की कैपेसिटी इसे कारोबारी माहौल के कामकाज, जैसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग या ओएलटीपी, डेटाबेस या वेब इंडेक्सिंग और ईमेल आदि के लिहाज़ से बेहतरीन बनाते हैं. पल्सर-2 एसएसडी ख़ास तौर पर डेटा सेंटर के लिए डिज़ाइन किए गए हैं. इस ड्राइव में 800 जीबी तक की स्टोरेज कैपेसिटी है, यह अपने आप डेटा एरर पकड़ती है और उसे सही कर लेती है. इस तरह यह सामान्य ड्राइव ऑपरेशन को आसान बताती है. क़ीमत और कामकाज के लिहाज़ से भी किफायती है. पल्सर एक्सटी-2 400 जीबी एसएसडी स्टोरेज परफॉर्मेंस काउंसिल या एसपीसी के कठिन मानदंडों पर पूरी तरह खरी उतरी है. एसपीसी वेंडरों का एक तटस्थ संगठन है, जो मानक स्टोरेज बेंचमार्क तयकर इसे बढ़ावा देता है और इससे जुड़ी पूरी निगरानी रखता है, ताकि लगातार बेहतरीन एवं भरोसेमंद एंटरप्राइज क्लास परफॉर्मेंस मिल सके. एसपीसी-1 सी का ताजा नतीजा बताता है कि पल्सर एक्सटी-2 एसएसडी हर पल एंटरप्राइज की ज़रूरतों के मुताबिक़, समग्र एवं बेहतरीन स्टोरेज डिवाइस परफॉर्मेंस मुहैया कराती है. इस पर न तो कार्यभार की जटिलताओं का असर पड़ता है और न सर्वर इनपुट-आउटपुट आईओ इंटेंसिटी लेवल का.

क्या है अबैकस

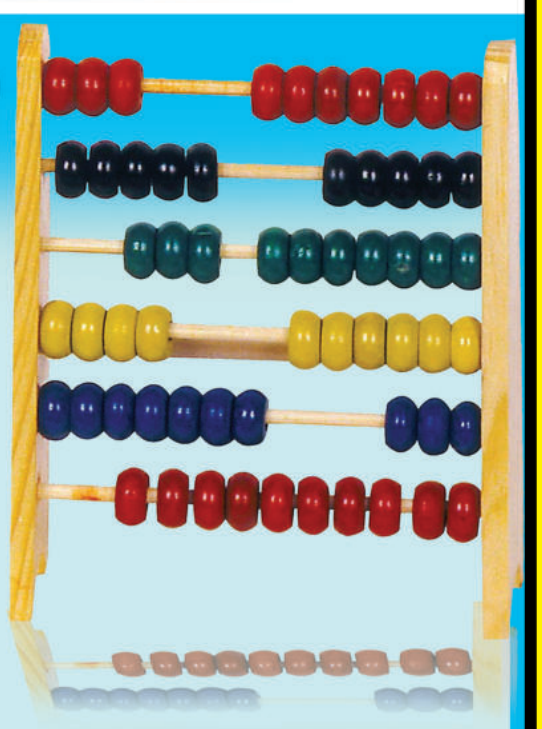

अबैकस, जिसे हिंदी में गिनतारा कहते हैं, लेकिन यह अबैकस या गिनतारा क्या है? अगर हम अपने बचपन को याद करें तो गिनतारा से हम लोग खेल चुके हैं. स्लेट के ऊपर कमानियों में फंसे ढेर सारे रंगबिरंगे प्लास्टिक के मोतियों को ही गिनतारा कहते हैं. गिनतारा से ही शुरू होता है कंप्यूटर का सफ़र. गिनतारा एक गणक उपकरण है, जिसका प्रयोग एशिया के विभिन्न भागों में अंकगणितीय समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता था. आज अबैकस अपने वर्तमान रूप में तारों पर बंधे मोतियों वाले एक बांस फ्रेम के रूप में दिखाई पड़ता है. गिनतारा का आविष्कार आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व हो चुका था. 2700-2300 ईस्वी पूर्व मेसोपोटामिया में सबसे पहले सुमेरियाई गिनतारा पाया गया था, जो सेक्साजेसिमल नंबर सिस्टम पर आधारित था. मेसोपोटामिया के अलावा मिस्र का गिनतारा, पारसी गिनतारा, यूनानी गिनतारा, रोम का गिनतारा, चीनी गिनतारा, जापानी गिनतारा, रूसी गिनतारा एवं कोरियाई गिनतारा का उल्लेख मिलता है.

भारत का भी अपना गिनतारा था. अभिधर्म कोश के अनुसार, व्यवसायी इसका उपयोग करते थे. भारतीय गिनतारा अन्य सभी गिनतारों से अलग और बहुत महत्वपूर्ण था. इसमें एक कमानी खली थी, जिसे शून्य कहा गया. जितने भी विदेशी यात्री भारत आए, वे भारत का गिनतारा देखकर दंग रह गए, क्योंकि भारतीय गिनतारा से सभी तरह की गणना संभव थी. यहीं से पूरे विश्व में शून्य का प्रसार हुआ. बाद में बाइनरी गिनतारा का आविष्कार हुआ. इसका उपयोग कंप्यूटर की कार्यप्रणाली समझने के लिए किया जाता है.

हीरो होंडा अब हीरो मोटोकॉर्प

भारत की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी हीरो होंडा मोटर्स को अब हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड के नाम से जाना जाएगा. हीरो होंडा ने जापान की होंडा कंपनी के साथ हीरो की साझेदारी समाप्त होने पर यह बदलाव करना ज़रूरी बताया. यही वजह है कि हीरो होंडा अब हीरो मोटोकॉर्प कहलाएगी. अपनी नई ग्लोबल ब्रांड पहचान को कंपनी ने लंदन में लांच करने का फ़ैसला किया. हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन बृजमोहन लाल के अनुसार, यह कंपनी के सिर्फ़ नाम का ही बदलाव नहीं है, बल्कि एक नए युग की शुरुआत है, जिसमें कंपनी अपनी क्षमताओं के बल पर नए मानक स्थापित करेगी. उन्होंने उम्मीद जताई कि कंपनी को डीलरों, वेंडरों एवं ग्राहकों का समर्थन पहले की तरह मिलता रहेगा. हीरो मोटोकॉर्प के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ पवन मुंजाल ने कहा कि यहां से उत्पादों एवं तकनीक के स्तर पर नई खोज का एक सिलसिला शुरू होगा. कंपनी के नए नाम की घोषणा करते हुए उन्होंने ग्राहकों को संदेश देते हुए कहा कि आगे भी बहुत कुछ बदलने वाला है. ओमनीकॉम ग्रुप की इकाई वोल्फ ओलिंस को नई ब्रांड पहचान तैयार करने के लिए अनुबंधित किया गया है.

एलजी का एंड्रॉयड ब्लैक स्मार्ट

आख़िरकार दुनिया की अग्रणी फोन निर्माता कंपनी एलजी इलेक्ट्रॉनिक ने भी अपना एंड्रॉयड फोन बाज़ार में उतार दिया. एलजी ऑप्टिमस ब्लैक पी-970 नामक इस एंड्रॉयड फोन में एक गीगाबाइट का माइक्रो प्रोसेसर लगाने के साथ ही दूसरी कई तकनीकों का प्रयोग किया गया है. इस फोन में 512 जीबी की रैम और दो जीबी की अतिरिक्त मेमोरी दी गई है. इस दो जीबी की मेमोरी को 32 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है. यह फोन वाई-फाई और जीपीएस सिस्टम को सपोर्ट करता है. इसका वजन केवल 109 ग्राम है. कंपनी का मानना है कि इतने कम वजन के कारण लोगों को इसे रखने में भी परेशानी नहीं होगी.

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने भारत से चैंपियंस ट्रॉफी और ओलंपिक क्वालीफाइंग टूर्नामेंट की मेज़बानी छीन ली है.

हॉकी सिर्फ़ नाम का राष्ट्रीय खेल

फोटो–प्रभात पाण्डेय

राजेश एस कुमार

कहते हैं जब कोई भी संस्थान या व्यक्ति अपने पतन के दौर से गुज़रता है तो एक दिन उसका उत्थान भी होता है, यानी उतार–चढ़ाव की स्थिति सब पर लागू होती है. अगर नहीं लागू होती है तो वह है हमारी भारतीय हॉकी टीम. जी हां, दुनिया में हर बदहाल संस्था और टीम के दिन बहुर सकते हैं, लेकिन भारतीय हॉकी टीम के बारे में यही कह सकते हैं कि यह फिर से कामयाबी का सवेरा शायद ही कभी देख सके. बात सिर्फ़ ख़िताबों के जीतने की ही नहीं, बल्कि हॉकी की संस्थात्मक सड़न से है. आज हॉकी के अंदर और बाहर का पूरा तंत्र इस क़दर सड़ चुका है कि जब भी हॉकी से जुड़ी ख़बर आती है तो कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर होता है जिससे हमारे राष्ट्रीय खेल की फ़ज़ीहत हो जाती है. अंतरराष्ट्रीय मुक़ाबलों में शर्मनाक हार झेलना तो बहुत पुरानी बात हो चुकी है. अब हम अपने देश में ही आपसी लड़ाई देख रहे हैं. कभी कोच के सेक्स स्कैंडल हॉकी को शर्मसार करते हैं तो कभी खिलाड़ी

ख़ुद के मेहनताने को लेकर सड़क पर विरोध प्रदर्शन के लिए उतर आते हैं. इतना ही नहीं टीम के खिलाड़ियों के आपसी संबंधों पर भी विवाद होते रहते हैं. फिर डोपिंग में फंसे खिलाड़ी बची खुची कसर पूरी कर देते हैं. कुल मिलाकर हॉकी आज अपने निम्नतम दौर से गुज़र रही है, लेकिन मुश्किलें हैं कि फिर भी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं. अभी ताज़ा मामला चैम्पियंस ट्रॉफी और ओलंपिक क्वालीफाइंग टूर्नामेंट की मेज़बानी को लेकर उठ रहा है. इस बात से तो सभी वाक़िफ़ हैं कि पिछले कुछ दिनों से अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ (एफआईएच), हॉकी इंडिया (एचआई) और भारतीय हॉकी महासंघ (आईएचएफ) के बीच हुए आपसी समझौते से नाराज़ चल रहा था. इस बात का अंदेशा लगाया जा रहा था कि अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ (एफआईएच) ज़रूर कोई न कोई ठोस क़दम उठाएगा, ऐसा ही हुआ. हॉकी इंडिया (एचआई) और भारतीय हॉकी महासंघ (आईएचएफ) के बीच हुए आपसी समझौते से नाराज़ अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ (एफआईएच) ने भारत से चैंपियंस ट्रॉफी और ओलंपिक क्वालीफाइंग टूर्नामेंट की मेज़बानी छीन ली है. उसके इस क़दम ने न सिर्फ़ हॉकी संघ की फ़ज़ीहत की है, बल्कि इससे देश की भी फ़ज़ीहत होती है.

ग़ौरतलब है कि एफआईएच इस बात को लेकर नाराज़ था कि एचआई ने उससे सलाह के बग़ैर आईएचएफ के साथ साझा तौर पर काम करने संबंधी समझौता किया. एफआईएच के मुताबिक़ एचआई और आईएचएफ के बीच हुआ समझौता ओलंपिक और उसके चार्टर के ख़िलाफ़ है और यही कारण है कि वह भारत से चैंपियंस ट्रॉफी और ओलंपिक क्वालीफाइंग टूर्नामेंट की मेज़बानी छीन रहा है. ग़ौरतलब है कि दोनों आयोजन नई दिल्ली में इस वर्ष के अंत में और 2012 की शुरुआत में होने थे. ऐसा नहीं है कि यह अचानक हो गया हो. दरअसल एफआईएच ने अपने बयान में कहा था कि एफआईएच भारतीय खेल मंत्रालय द्वारा एचआई और आईएचएफ के बीच कराए गए समझौते को लेकर बेहद चिंतित है. इसके लिए एफआईएच से सलाह लेने की भी ज़रूरत नहीं समझी गई. एचआई, आईएचएफ और खेल मंत्रालय के बीच हुए समझौते के मुताबिक़ दोनों संगठनों ने आपसी मतभेदों को भुलाकर भारतीय हॉकी के विकास के लिए साथ मिलकर काम करने फ़ैसला किया था. हालांकि घरेलू स्तर पर दोनों संगठन अलग–अलग काम करेंगे. घरेलू स्तर पर दोनों के लिए बराबर ज़िम्मेदारियां तय करने के लिए एक संयुक्त कार्यकारिणी और कार्यकारी समिति का गठन किया जाएगा. नए संगठन को राष्ट्रीय टीम के चयन, उसकी तैयारी, विदेशी आयोजनों के लिए टीमों को भेजने और राष्ट्रीय कैंप आयोजित करने का काम सौंपा जाएगा. फ़िलहाल यह व्यवस्था 2012 तक के लिए की गई है. इसके बाद इन संगठनों की ज़िम्मेदारियों पर फिर से विचार किया जाएगा. ज़ाहिर सी बात है कि इस फ़ैसले से एफआईएच ख़ुश नहीं था. उसने साफ़ कहा है कि भारत के दो हॉकी संगठनों के बीच हुआ यह समझौता उसे मंज़ूर नहीं है. एफआईएच अध्यक्ष लेनार्दो नेगरे ने खेल मंत्री अजय माकन को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने इस बात का ज़िक्र किया कि इस मामले की गंभीरता को समझते हुए एचआई और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्षों के बीच एक बैठक कराई जाए, जिसमें एफआईएच की चिंताओं को लेकर चर्चा होनी चाहिए. एफआईएच ने कहा कि उसके मुताबिक़ एचआई ही भारत में हॉकी का संचालन करने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था है और इस नाते उसे ही भारतीय टीम के चयन और अंतरराष्ट्रीय आयोजनों की मेज़बानी का अधिकार मिलना चाहिए. एफआईएच किसी भी हाल में आईएचएफ को मान्यता नहीं दे सकता. एफआईएच ने वर्ष 2000 में आईएचएफ की मान्यता रद्द कर दी थी. अब हो सकता है कि इस मामले पर फिर कई बैठकें हों, पर इतना तो तय है कि हॉकी की जो फ़ज़ीहत होनी थी, वह तो हो ही गई. समझने वाली बात यह है कि यहां पर हॉकी से ज़्यादा फ़ज़ीहत भारत की हुई है. किसी भी देश के लिए एन वक़्त पर मेज़बानी का छिनना बहुत ही शर्मिंदगी भरा होता है. ख़ैर, जो होना था वह तो हो ही गया. लेकिन दिक्क़त तो इस बात को लेकर और बढ़ जाती है कि ऐसे मौक़े पर जहां देश की अस्मिता के लिए टीम और प्रबंधन को एकजुट होकर देश को संदेश देना चाहिए था, उल्टा वे आपस में ही उलझे हुए हैं.

पिछले दिनों कुछ खिलाड़ियों के अभ्यास शिविर छोड़कर विश्व श्रृंखला हॉकी के लिए भारतीय हॉकी महासंघ और नियो स्पोर्ट्स के मुंबई में हुए संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में शामिल होने की वजह से पनपा विवाद भी थमने का नाम नहीं ले रहा है. पूर्व भारतीय कप्तान धनराज पिल्लै ने हॉकी इंडिया से कारण बताओ नोटिस पाने वाले पांच वरिष्ठ खिलाड़ियों को सलाह दी है कि वे भारतीय हॉकी टीम में खेलने के लिए इस संस्था के अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाए नहीं. इस बात से तो सभी वाक़िफ़ है कि हॉकी इंडिया ने कुछ दिनों पहले ही पांच वरिष्ठ खिलाड़ियों अर्जुन हलप्पा, संदीप सिंह, एड्रियन डिसूजा, सरदारा सिंह और प्रभजोत सिंह को बेंगलुरु में चल रहा अभ्यास शिविर छोड़कर विश्व श्रृंखला हॉकी के लिए भारतीय हॉकी महासंघ और नियो स्पोर्ट्स के मुंबई में हुए संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में शामिल होने की वजह से कारण बताओ नोटिस जारी किया था. हॉकी इंडिया की अनुशासन समिति के अध्यक्ष परगट सिंह ने इन पांचों खिलाड़ियों को नोटिस जारी किया था. बस विवाद यहीं से शुरू हो गया. इस विवाद को सुलझाने के बजाय धनराज इस मामले को एक तरह से तूल देते हुए यह बयान देते हैं कि इन खिलाड़ियों को अपने देश के लिए खेलने के लिए हॉकी इंडिया के अधिकारियों के सामने नाक नहीं रगड़नी चाहिए. हालांकि धनराज ने इसके अलावा जो सवाल उठाए हैं, वे कई मायनों में तार्किक हैं, मसलन पूर्व कप्तान ने इस निर्णय और हॉकी इंडिया में बड़ा पद ले चुके अपने पूर्व टीम साथी परगट पर टिप्पणी करते हुए कहा कि एक समय परगट भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी को माफ़िया कहा करते थे, लेकिन जब उन्हीं के बनाए हॉकी इंडिया में जब उनके सामने अच्छे पद की पेशकश की गई तो वह सबकुछ भूलकर पद की तरफ़ लपक पड़े. धनराज ने विश्व श्रृंखला हॉकी की तरफ़दारी करते हुए कहा कि यह भारतीय हॉकी खिलाड़ियों के हक़ और हित में है और इसीलिए मैं इसमें शामिल हूं. अब इन हालात में कैसे कोई उम्मीद कर सकता है कि पहले से क़ब्र में पैर लटकाए हुए इस राष्ट्रीय खेल का भला कैसे होगा. एक बात तो बिल्कुल समझ में नहीं आती है कि किसी भी देश के लिए राष्ट्रीय खेल को परिभाषित करने के लिए क्या मापदंड होते हैं. इस बात को भी दरकिनार कर दिया जाए तो यह सवाल उठता है कि क्या राष्ट्रीय खेल की इस बदहाली का ज़िम्मेदार खेल मंत्रालय और प्रशासन नहीं है. अगर इस खेल की बदहाली यूं ही जारी रही तो बहुत दुख के साथ कहना पड़ सकता कि हॉकी सिर्फ़ नाम का ही राष्ट्रीय खेल रह जाएगा.

rajeshy@chauthiduniya.com

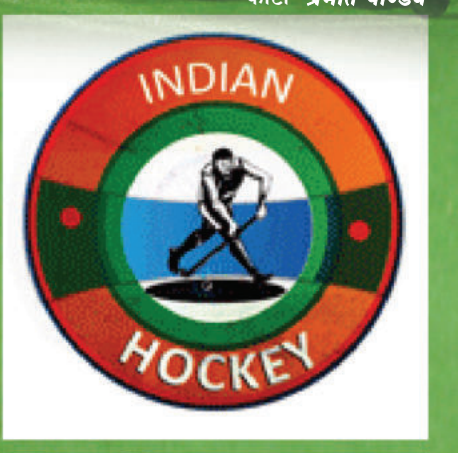

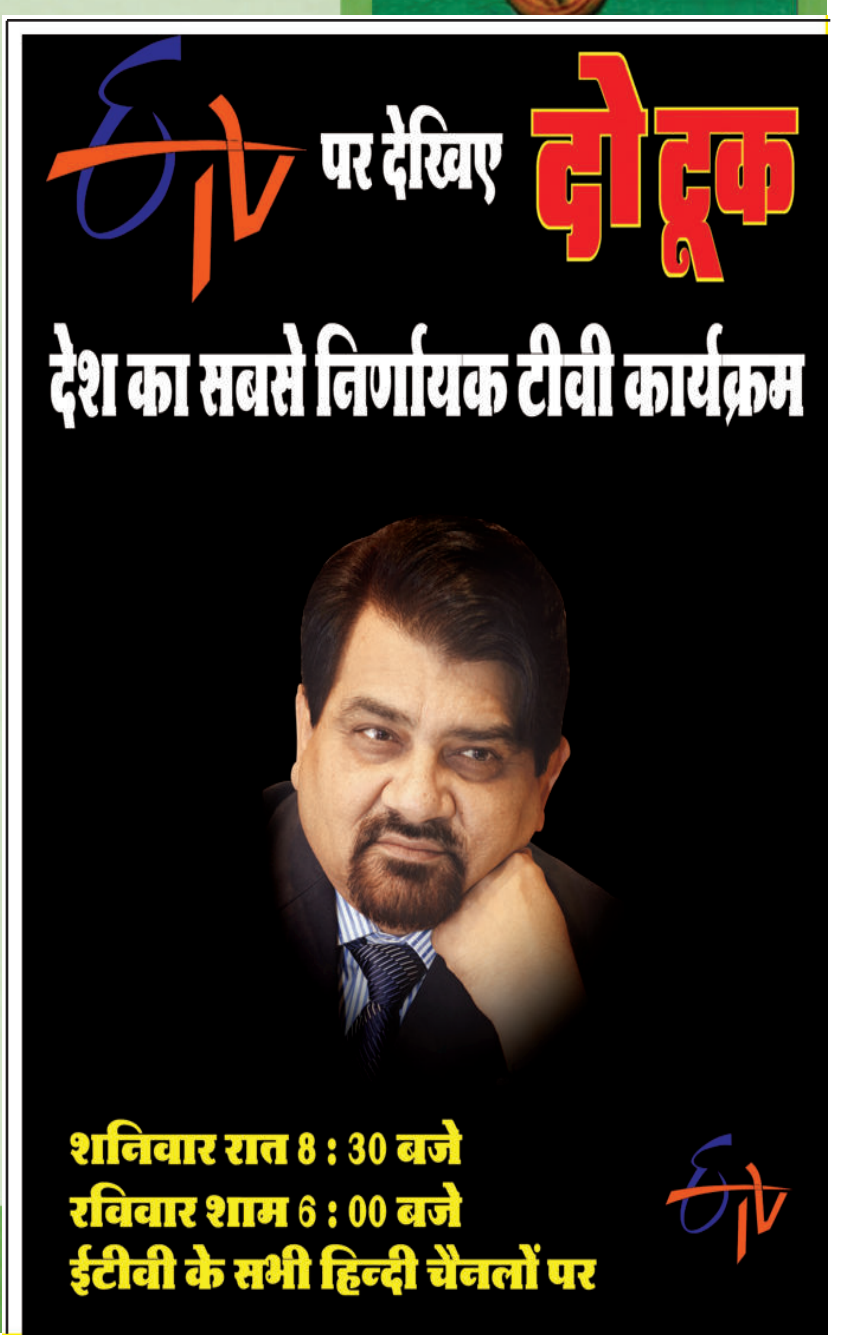

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. DELHIN/2009/30467

करिश्मा को आइटम नंबर का यह ऑफर साजिद नाडियावाला की फिल्म हाउसफुल-2 के लिए हुआ है, जिसे पहले रानी मुखर्जी करने वाली थीं.

बॉलीवुड में बारबरा

हॉलीवुड और स्पेनिश फिल्म इंडस्ट्री में कामयाबी के झंडे गाड़ चुकीं बारबरा मोरी अब बॉलीवुड में भी अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराना चाहती हैं. फिल्म काइट्स में रितिक रोशन की प्रेमिका की भूमिका निभा चुकीं मेक्सिकन ब्यूटी बारबरा मोरी जल्द ही फिल्म फीवर में राजीव खंडेलवाल के साथ नज़र आएंगी. फिल्म में अपने रोल के लिए उन्होंने 1.3 करोड़ रुपये लिए हैं. यह बॉलीवुड में उनकी दूसरी फिल्म होगी. राजीव झवेरी के निर्देशन में बनने जा रही इस फिल्म का निर्माण रवि अग्रवाल कर रहे हैं. फिल्म में बारबरा एक भाषाविद् के रूप में नज़र आएंगी. फीवर की ज़्यादातर शूटिंग ब्रिटेन के कॉर्नवॉल में तय की गई है. इस फिल्म में उनके साथ बॉलीवुड की एक और अदाकारा नज़र आएंगी, लेकिन इससे बारबरा को कोई कांप्लेक्स नहीं हो रहा, जैसा कि बॉलीवुड की अभिनेत्रियों में अक्सर देखा जाता है. दरअसल, बारबरा जितनी ख़ूबसूरत हैं, उनके विचार भी उतने ही खुले हैं. सिर्फ़ काम के प्रति नहीं, बल्कि ज़िंदगी जीने के प्रति भी. बारबरा मोरी शादी में यकीन नहीं रखती. 19 साल की उम्र में बारबरा की मुलाक़ात अभिनेता सरजियो मेयर से हुई. दोनों में प्यार हुआ और फिर बारबरा बिन शादी सरजियो के बच्चे की मां भी बनीं, लेकिन कुछ दिनों बाद बारबरा और सरजियो की राहें अलग-अलग हो गईं और बारबरा ने अपने दम पर बेटे की परवरिश की. वह कहती हैं, मुझे रीति-रिवाजों के ज़रिए लोगों को यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं किसी इंसान से कितना प्यार करती हूं. प्यार और शादी पर बेहद अलग राय रखने वाली 32 वर्षीय बारबरा आज अकेली हैं और ख़ुश हैं. उन्हें अपनी ज़िंदगी में कोई कमी महसूस नहीं होती.

टीवी शो से परहेज

एक बार जिसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करने का चस्का लग जाता है, फिर उसके पर निकल आते हैं. कुछ ऐसा ही हो रहा है वीना मलिक के साथ. बत्तीस वर्षीय पाकिस्तानी मॉडल एवं अभिनेत्री वीना मलिक जितनी लोकप्रिय पाकिस्तान में नहीं हुईं, उससे कहीं ज़्यादा भारत में हो चुकी हैं. पाकिस्तान की राखी सावंत कही जाने वाली वीना को जिस छोटे टेलीविजन से काम करने का मौक़ा मिला, अब वह उसी में काम करने से इंकार कर रही हैं. रियलिटी शो बिग बॉस में काम कर चुकीं वीना ने फ़िलहाल किसी भी टीवी शो में काम करने से इंकार कर दिया है. वीना के अनुसार फ़िलहाल वह बॉलीवुड की दो फिल्मों दाल में कुछ काला है और टुडे पर ही फोकस कर रही हैं. इसलिए टीवी के दर्शकों को उनका थोड़ा इंतज़ार करना होगा. हालांकि हाल ही में उन्हें इमेजिन चैनल ने रियलिटी शो स्वयंवर के लिए अप्रोच किया है. पिछले दिनों ही इस शो का तीसरा सीजन ख़त्म हुआ है, अब इसके चौथे सीजन के लिए वीना का नाम चर्चा में है. स्वयंवर के इस ऑफर को वीना स्वीकार करती हैं या नहीं, यह तो वक़्त बताएगा, लेकिन पाकिस्तान की इस पहली टॉपलेस अभिनेत्री ने रियलिटी शो बिग बॉस के ज़रिए करोड़ों दर्शकों को रिझाकर फ़ायदा उठा लिया है. शायद वह जानती हैं कि हर बदनामी में नाम छुपा है और हर तरह का नाम दाम दिलाता है. इसलिए दस साल पहले फोटो शूट से चर्चित हुईं वीना मलिक अब तक उर्दू, पंजाबी और पश्तो की सत्रह फिल्में कर चुकी हैं. ऐसा नहीं है कि केवल देह दर्शन से ही वह मशहूर हो गईं, अभिनय प्रतिभा भी उनमें है. वह हास्य धारावाहिक भी कर चुकी हैं और शानदार कॉमेडी करती हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

आइटम गर्ल बनेंगी करिश्मा

जबसे करिश्मा कपूर ने यह घोषणा की है कि वह फिर से फिल्मों में वापसी कर रही हैं, उन्हें लेकर फिल्म बनाने वाले लोगों में वृद्धि होती नज़र आ रही है. इसकी ख़ास वजह यह भी है कि उन्होंने अपना वजन बहुत कम किया है और अब वह सुडौल नज़र आ रही हैं. करिश्मा ने विक्रम भट्ट के निर्देशन में बनने जा रही फिल्म डेंजरस इश्क के ज़रिए बॉलीवुड में वापसी की घोषणा क्या कर दी, अब उनके पास आइटम नंबर के भी ऑफर आ रहे हैं. हो सकता है कि करिश्मा इसे करने के लिए तैयार भी हो जाएं. करिश्मा को आइटम नंबर का यह ऑफर साजिद नाडियावाला की फिल्म हाउसफुल-2 के लिए हुआ है, जिसे पहले रानी मुखर्जी करने वाली थीं. किसी कारणवश रानी यह आइटम नंबर नहीं कर पा रही हैं, इसलिए अब करिश्मा को अप्रोच किया गया है. हालांकि करिश्मा ने इस बारे में हामी नहीं भरी है. करिश्मा साजिद की अच्छी दोस्तों में से एक हैं. वह उनकी जीत और जुड़वा जैसी फिल्मों में काम कर चुकी हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि करिश्मा के लिए साजिद को इंकार करना मुश्किल होगा. अब देखना तो यह है कि इस आइटम नंबर को लेकर करिश्मा क्या निर्णय लेती हैं.

इनर ब्यूटी बेहद ज़रूरी

मासूम ख़ूबसूरती के लिए पहचानी जाने वाली दीया अब प्रोडक्शन में हाथ आजमा रही हैं. लंबे समय से उनकी कोई फिल्म नहीं आई है, लेकिन जल्द ही उनकी एक फिल्म लव, ब्रेकअप, ज़िंदगी रिलीज होने वाली है. यह होम प्रोडक्शन के तहत बनने वाली उनकी पहली फिल्म है. दरअसल बात यह है कि जबसे उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला है, तबसे दूसरी फिल्मों में काम करना बंद कर दिया है. अब वह पूरी तरह इसके तहत बनने वाली फिल्मों पर ही ध्यान देती हैं. उनकी आने वाली फिल्म एक रोमांटिक कॉमेडी है. इसमें वैल्यूज के साथ रोमांस, कॉमेडी, लव वग़ैरह सभी कुछ देखने को मिलेगा. यानी यह फुल एंटरटेनमेंट वाली फिल्म होगी. दीया बताती हैं कि जब भी उन्हें खाली वक़्त मिलता है तो उसे सोशल वर्क में बिताती हैं. आंध्र प्रदेश सरकार के साथ मिलकर उन्होंने एचआईवी के प्रति लोगों को जागरूक करने, भ्रूण हत्या रोकने के लिए काफी काम किया. इसके अलावा वह हरित क्रांति के साथ-साथ कैंसर पेशंट्स एंड एसोसिएशन और स्पास्टिक्स सोसायटी ऑफ इंडिया से भी जुड़ी हैं. वह अन्य अभिनेत्रियों की तरह जिम एक्सरसाइज को ब्यूटी एंड हेल्थ सीक्रेट नहीं मानती, बल्कि कहती हैं कि दिल साफ हो और किसी के लिए कड़वाहट न हो तो ख़ूबसूरती को बनाए रखना आसान हो जाता है. उनके अनुसार, इनर ब्यूटी बेहद ज़रूरी है. इसके अलावा हेल्दी लाइफ स्टाइल भी अट्रैक्टिव बनाए रखने में ख़ासा मदद करता है. सोशल साइट्स ट्विटर और फेसबुक पर भी काफी एक्टिव हैं दीया, क्योंकि वह मानती हैं कि अपने फैंस से जुड़ने का सबसे आसान तरीक़ा ट्विटर है. फेसबुक को वह अपने स्कूल एवं फैमिली फ्रेंड्स के साथ टच में रहने के लिए इस्तेमाल करती हैं. यह भी कोशिश करती हैं कि इसे लगातार अपडेट करती रहें.

फिल्म प्रीव्यू

चतुर सिंह टू स्टार

संजय दत्त की वर्षों से अटकी फिल्म चतुर सिंह टू स्टार एक कॉमेडी फिल्म है. इसमें संजय दत्त ने एक ऐसे बेवकूफ पुलिस अधिकारी का किरदार निभाया है, जो अपने सारे मामले अपनी बेवकूफी की वजह से ख़राब कर देता है. मुंबई पुलिस डिपार्टमेंट में काम करने वाले चतुर सिंह टू स्टार (संजय दत्त) को लगता है कि वह सब कुछ जानता है, जबकि हक़ीक़त यह होती है कि वह आला दर्जे का बेवकूफ है. जब भी कोई केस सुलझाने के लिए उसे दिया गया, अपनी मूर्खता के कारण उसने और उलझा दिया तथा हंसी का पात्र बना. अपनी टीम को कई बार अपमानित करने के बावजूद उसे डिपार्टमेंट का सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा मामला सौंपा जाता है. चतुर सिंह के सामने अपने आपको काबिल अधिकारी साबित करने का हसीन मौक़ा मिलता है. वह सीक्रेट मिशन के लिए दक्षिण अफ्रीका रवाना जाता है और कई लोगों की मुसीबतों का कारण बनता है. उसकी हरकतें दूसरों के लिए ख़तरनाक साबित होती हैं, फिर भी सोनिया (अमीषा पटेल) की मदद से वह सही दिशा में आगे बढ़ता है. चतुर सिंह का मसखरापन और सुपर इंटेलिजेंस कई हास्यास्पद घटनाओं को जन्म देता है, गड़बड़ियां होती हैं, ग़लतफ़हमियां होती हैं. मामले को और मसालेदार बनाने के लिए पप्पू पेंथर (सुरेश मेनन) भी मौजूद है. वह चतुर सिंह की पूजा करता है और उससे भी बड़ा बेवकूफ है. फिल्म में संजय दत्त ने एक गाना भी गाया है. फिल्म पेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और लोटस पिक्चर्स के बैनर तले बनी है. इसके निर्माता हैं मोहम्मद असलम. फिल्म के निर्देशन की बागडोर संभाली है निर्देशक अजय चंडोक ने और संगीत दिया है साजिद-वाजिद ने. मुख्य कलाकार हैं संजय दत्त, अमीषा पटेल, सुरेश मेनन, अनुपम खेर, सतीश कौशिक एवं गुलशन ग्रोवर.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

दिल्ली, 15 अगस्त-21 अगस्त 2011

www.chauthiduniya.com

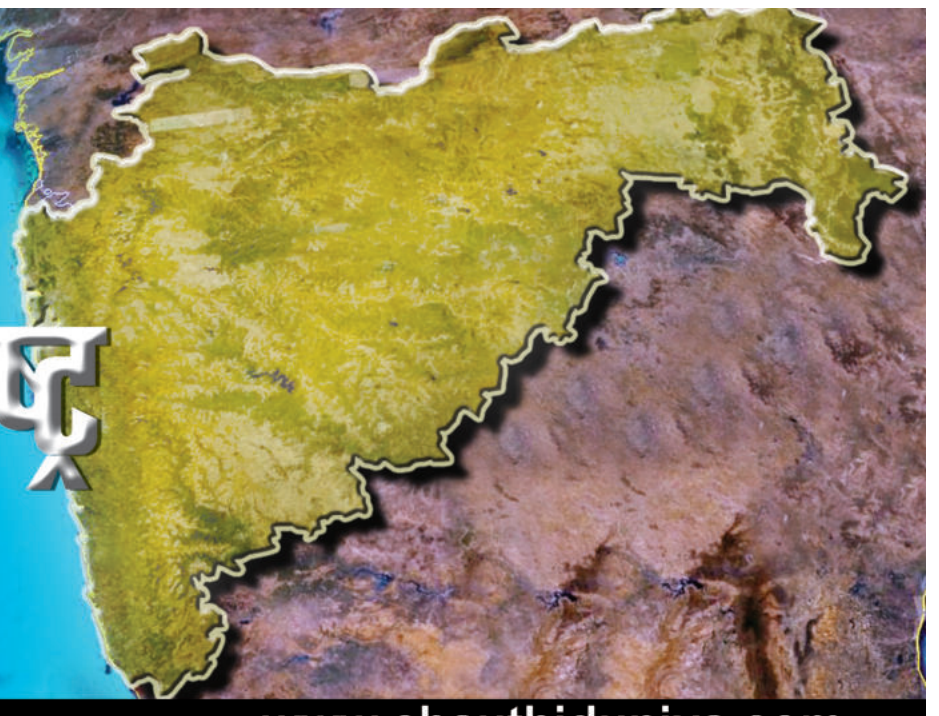

ख़तरे में बांध

विदर्भ के बड़े बांध

तोतलाडोह, नागपुर
कामठीखैरी, नागपुर
रामटेक, नागपुर
लोवर- नांद वणा, नागपुर
वइगांव- नांद वणा, नागपुर
इटियाडोह, गोंदिया
सिरपुर, गोंदिया
पुजारी टोला गोंदिया
कालीसरार, गोंदिया
असोलामेंढा, चंद्रपुर
दिना, गड़चिरोली
बोर, वर्धा
धाम, वर्धा
पोथरा, वर्धा
लोअर वर्धा टप्पा-1, वर्धा
गोसीखुर्द टप्पा-1 भंडारा
अपर वर्धा , अमरावती
पुस प्रकल्प, यवतमाल
अरुणावती, यवतमाल
बंबला, यवतमाल
काटेपूर्णा, अकोला
वान, अकोला
नळगंगा , बुलढाणा
पेनटाकली, बुलढाणा
खड़कपूर्णा, बुलढाणा

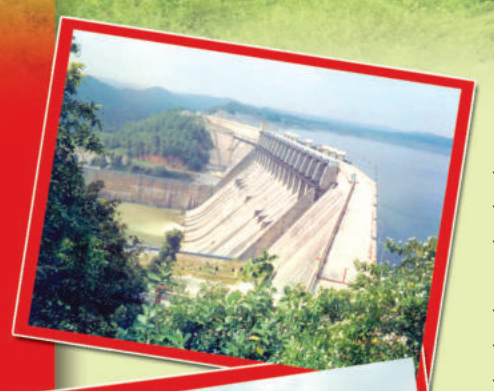

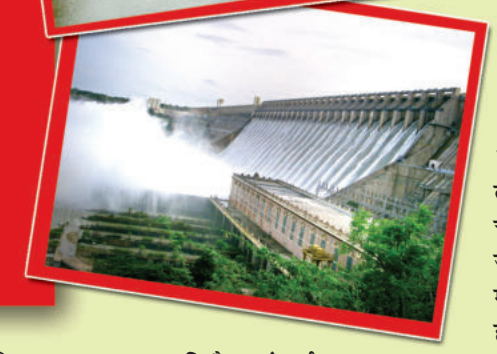

प्रवीण महाजन

विदर्भ सहित राज्य में स्थित बांध क्या सुरक्षित हैं? यह सवाल इसलिए उठ रहा है, क्योंकि पिछले दिनों देश की ख़ुफ़िया एजेंसियों ने एक रिपोर्ट में आतंकवादियों द्वारा बड़े जलाशयों व बांधों को निशाना बनाए जाने की चेतावनी केंद्र व राज्य सरकारों को दी है. हालांकि ख़ुफ़िया एजेंसियों की रिपोर्ट में महाराष्ट्र के किसी बांध का उल्लेख नहीं किया गया है, पर आतंकवादी किस पर, कब, कहां हमला करेंगे यह भी तो निश्चित नहीं होता है. लेकिन जिस तरह से राज्य में आतंकवादी अपना नेटवर्क बढ़ा रहे हैं उससे हमले की आशंकाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है. विशेषकर तब जब मुंबई, पुणे, नागपुर, अकोला हमेशा आतंकवादियों के निशाने पर रहते हैं और इस दृष्टि से इन शहरों को अतिसंवेदलशील माना जाता है. इसके पहले आतंकवादी और नक्सली कई राज्यों में बांधों, बिजली घरों को निशाना बनाने की धमकी दे चुके हैं और उड़ीसा में तो एक बांध को उड़ाने का प्रयास भी किया, पर पुलिस की सर्तकता से उसे विफल कर दिया गया.

राज्य में आतंकवादियों ने बड़े शहरों के साथ ही अब मध्यम शहरों में भी अपना नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया है. पिछले तीन-चार माह के दौरान मुंबई, पुणे, ठाणे में कई आतंकवादियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है. इसके अलावा आतंकवादियों व नक्सलियों ने शहरों से पढ़े-लिखे युवाओं को भी अपने साथ जोड़ने का प्रयास शुरू कर दिया है. इसका साफ़ मतलब है कि नक्सली धीरे-धीरे दुर्गम क्षेत्रों से बाहर निकल कर अपनी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश में जुटे हैं. इसी के तहत दो वर्ष पूर्व नागपुर में होने वाले विधानमंडल के शीतसत्र के दौरान विधानसभा में नक्सलियों द्वारा हमला किए जाने की सूचनाएं सामने आई थीं. तब से विधानसभा के नागपुर में होने वाले शीतकालीन सत्र के दरम्यान अभूतपूर्व पुलिस बंदोबस्त किया जाता है. उसी बीच नागपुर के गिट्टीखदान एरिया में नक्सलियों द्वारा भारी मात्रा में एकत्रित विस्फोटक व हथियार भी पुलिस ने बरामद किए थे, परंतु अब ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि आतंकवादियों की तर्ज़ पर महाराष्ट्र के नक्सली भी किसी बड़ी योजना को अंजाम देने का मनसूबा बना रहे हैं. वे ऐसे संस्थानों और जगहों की टोह ले रहे हैं जिनकी ओर सुरक्षा के लिहाज़ से सरकार का ध्यान नहीं है. इस लिहाज़ से राज्य के बांधों को निशाना बनाना उनके लिए आसान लक्ष्य हो सकता है, क्योंकि सरकार व पुलिस प्रशासन का बांधों की सुरक्षा की ओर बिलकुल भी ध्यान नहीं है. यह अलग बात है कि नक्सलियों ने अब तक राज्य के किसी बांध को निशाना नहीं बनाया है, लेकिन आशंकाओं को कभी ख़ारिज नहीं किया जा सकता है. भविष्य में उनका रुख़ कब बदल जाए, कहना मुश्किल है. ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार के ध्यान में बांधों की सुरक्षा का मुद्दा न हो, पर अब तक इसे गंभीरता से नहीं लिया गया है. राज्य के जलसंपदा विभाग के उपसचिव चं.रा. तेजाले हस्ताक्षरित शासन परिपत्रक क्र. धसुव्यं 2008/(535/2008)/ सिं.व्य. (कामे) परिपत्रक 8 अगस्त, 2008 को जारी कर सभी कार्यकारी संचालक, पाटबंधारे विकास महामंडल, जनसंपदा विभाग, सभी मुख्य अभियंता, सभी अधीक्षक अभियंता और सभी कार्यकारी अभियंताओं को बांधों की सुरक्षा को लेकर सर्तक किया था. पत्र के पहले पैराग्राफ में स्पष्ट रूप से बांधों पर आतंकी हमलों की आशंका व्यक्त करते हुए अधिकारियों को सर्तक रहने की हिदायत दी गई है. पत्र में लिखा है कि सिंचाई व पानी से बिजली निर्माण के लिए राज्य में बड़े पैमाने पर बांधों/जलाशयों का उपयोग किया जाता है. बांधों से जुड़े जलाशयों की सुरक्षा की दृष्टि से इन्हें अबाधित रखना विभाग की ज़िम्मेदारी है. चूंकि पूरे देश में आतंकी हमले बढ़ने से बड़े बांधों-जलाशयों की सुरक्षा के मद्देनज़र अधिकारियों का सतर्क रहना आवश्यक है. अपने क्षेत्रों में स्थित बांधों की सुरक्षा निश्चित करने के लिहाज़ से हर वर्ष सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करें. अब जलसंपदा विभाग के अधिकारीगण बांधों की सुरक्षा के प्रति कितना सर्तक हैं, यह इससे ही पता चलता है कि राज्य की सीमा पर स्थित अंतर्राज्यीय प्रकल्प तोतलाडोह (पेंच प्रकल्प) की सुरक्षा व्यवस्था पुलिस विभाग के हवाले है. सुरक्षा की दृष्टि से वायरलेस की व्यवस्था है, पर दुर्भाग्य यह है कि यदि वायरलेस पर वहां नियुक्त पुलिस व जलसंपदा विभाग के कर्मचारियों से संपर्क करना हो तो सीधी बात नहीं हो पाती है. पहले रिपीटर से बात करनी पड़ती है, फिर बड़ी मुश्किल से वहां के वायरलेस कर्मचारी से बात हो पाती है. लेकिन रिपीटर अपनी ही बात सामने वाले को रिपीट कर बताता है. इसके साथ ही वहां पुलिस सुरक्षा नाममात्र की है. वहां कई बार जाने पर एक भी पुलिस विभाग का कर्मचारी ड्यूटी करता दिखाई नहीं देता. तोतलाडोह जैसी वायरलेस व्यवस्था विदर्भ के महत्वाकांक्षी प्रकल्प गोसीखुर्द की भी है. यहां पर भी रिपीटर से ही बात करनी पड़ती है. विदर्भ सहित महाराष्ट्र के किसी भी धरण पर पुलिस बंदोबस्त, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए दिखाई नहीं देते. यह सुरक्षा की दृष्टि से बड़ी चूक है. ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्ष 22 दिसंबर, 2010 को राज्य के गृहमंत्री आर.आर. पाटिल की अध्यक्षता में बांधों की सुरक्षा को लेकर बैठक हुई, जिसमें जलसंपदा मंत्री और गृह राज्यमंत्री विक्रमसिंह पाटणकर उपस्थित थे. इस बैठक में कोयना बांध सहित राज्य के अन्य बांधों की सुरक्षा पर विचार-विमर्श किया गया था. बैठक में जो निर्णय लिए गए, वे इस प्रकार हैं- (1) राज्य का जलसंपदा विभाग राज्य के सभी सीमेंट-कांक्रीट निर्मित बांधों की सूची पुलिस महानिरीक्षक (सुरक्षा) महाराष्ट्र राज्य को उपलब्ध कराएगा. (2) पुलिस महानिरीक्षक (सुरक्षा) राज्य के सभी बड़े बांधों की सिक्युरिटी ऑडिट करेगा. सिक्युरिटी ऑडिट होने के बाद वर्तमान में की गई सुरक्षा व्यवस्था व उसकी ख़ामियां और ख़ामियों को दूर करने की उपाय योजना की रिपोर्ट सचिव, जलसंपदा विभाग को उपलब्ध कराएगा. (3) सचिव, जलसंपदा विभाग संबंधित ज़िले के पुलिस अधीक्षक से चर्चा कर संबंधित बांध की सुरक्षा करने की दृष्टि से तत्काल उपाय योजना पर अमल करेगा. (4) कोयना राज्य का सबसे बड़ा बांध है. इस बांध से बड़ी मात्रा में बिजली उत्पादन किया जाता है, इसलिए इसकी सुरक्षा पर अधिक सतर्कता बरतने की ज़रूरत है. बैठक में तय किया गया कि इस बांध की सुरक्षा व्यवस्था केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल (सेंटल इंडस्ट्रियल सिक्युरिटी फोर्स) के सुपुर्द करना उचित रहेगा. इस संदर्भ में होने वाला ख़र्च जलसंपदा विभाग करेगा. इस संबंध में समन्वय की कार्रवाई पुलिस महासंचालक करेगा. इसी तरह भविष्य में इसकी सुरक्षा की जवाबदेही महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडल को सौंपने पर विचार किया जाएगा. (5) कोयना बांध में पेट्रोलिंग के लिए दो बोटों की आवश्यकता है. इन बोटों के लिए स्पेसीफिकेशन पुलिस महानिरीक्षक (सुरक्षा) से जलसंपदा विभाग प्राप्त करे. उसके बाद उक्त स्पेसीफिकेशन के अनुसार बोटों की ख़रीद की कार्यवाही जलसंपदा विभाग द्वारा तत्काल की जाए. (6) कोयना बांध के समीप बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं. पर्यटकों के लिए यहां बोटिंग की सुविधा उपलब्ध है. बोटिंग संचालित करने वाले लोगों को पुलिस के मार्फत परिचय पत्र देने की व्यवस्था होनी चाहिए. इसी तरह बोट के मालिक व चालक संबंधित संपूर्ण जानकारी पुलिस के पास रहनी चाहिए. (7) बांध के नीचे बग़ल में व भोवताल की सीमित जगह में पर्यटकों को जाने की अनुमति होनी चाहिए. मात्र संवेदनशील भाग में पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए. (8) सभी बांध वेबसाइट या गूगल में देखे जा सकते हैं. इससे उनकी लोकेशन में समाजविरोधी तत्व, आतंकवादी सहज ही पहुंच सकते हैं. पुलिस महानिरीक्षक को इन सभी बड़े बांधों की फोटो गूगल से हटाने के लिए संबंधित व्यक्ति से पत्र व्यवहार करना चाहिए. (9) जलसंपदा विभाग के बांधों के ठिकाने पर निवास व्यवस्था है. इन आवासों को वहां सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मचारियों को उपलब्ध कराना चाहिए. इन निवास स्थानों का नवीनीकरण जलसंपदा विभाग कराए. (10) पुणे ज़िले में बड़ी संख्या में बांध हैं. इन बांधों को होने वाली किसी तरह की क्षति का परिणाम पूरे पुणे पर होता है. इसलिए इन सभी बांधों की सुरक्षा व्यवस्था सख्त की जानी चाहिए. (11) मुंबई महानगर को जलापूर्ति करने वाले बांधों की सुरक्षा व्यवस्था मज़बूत करने बाबत बृहंमुंबई महानगर पालिका को अवगत कराना चाहिए. बैठक में

शेष पृष्ठ संख्या - 18 पर

बांधों से जुड़े जलाशयों की सुरक्षा की दृष्टि से इन्हें अबाधित रखना विभाग की ज़िम्मेदारी है. चूंकि पूरे देश में आतंकी हमले बढ़ने से बड़े बांधों-जलाशयों की सुरक्षा के मद्देनज़र अधिकारियों का सतर्क रहना आवश्यक है. अपने क्षेत्रों में स्थित बांधों की सुरक्षा निश्चित करने के लिहाज़ से हर वर्ष सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करें. अब जलसंपदा विभाग के अधिकारीगण बांधों की सुरक्षा के प्रति कितना सर्तक हैं, यह इससे ही पता चलता है कि राज्य की सीमा पर स्थित अंतर्राज्यीय प्रकल्प तोतलाडोह (पेंच प्रकल्प) की सुरक्षा व्यवस्था पुलिस विभाग के हवाले है.

मुख्य अभियंता निकुंम गंभीर नहीं

मुख्य अभियंता आर.डब्ल्यू. निकुम गोसीखुर्द प्रकल्प, जलसंपदा विभाग नागपुर यहां पर कार्यरत हैं. इनके पास मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग पद का अतिरिक्त प्रभार है. इनसे जब डैम सुरक्षा के संबंध में जानकारी मांगी गई तो इनका कहना था कि मैं मीटिंग में हूं. एक-दो दिन बाद इस पर बात करेंगे या एस.ई. चव्हाण हैं, उनसे बात कर लीजिए. जब हमारे प्रतिनिधि ने याद दिलाया कि आप दोनों जगह पर मुख्य अभियंता हो और आपके अंडर में आने वाले दोनों प्रकल्प में से एक अंतर्राज्यीय व दूसरा राष्टीय प्रकल्प है. इसके बाद में उन्होंने इस मुद्दे का महत्व नहीं समझा और अपनी टिप्पणी देने से पहले ही फोन काट दिया. उसके बाद पुनः मिलने के लिए समय मांगा गया था और उन्होंने शाम को 5.30 बजे मिलने का समय दिया था, परंतु निर्धारित समय पर प्रतिनिधि के जाने के बाद भी उन्होंने उसे काफ़ी देर तक इंतज़ार कराया. अंततः हमारे प्रतिनिधि को बिना उनसे मिले ही वापस आना पड़ा. इससे यह पता चलता है कि मुख्य अभियंता बांधों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ज़रा भी गंभीर नहीं हैं. मज़े की बात यह है कि निकुंम इसके पहले डैम सेफ्टी नासिक में एस.ई. पद पर थे, वहां से पदोन्नत होकर सी.ई. होकर नागपुर आए हैं.

निर्देशानुसार सुरक्षा : शर्मा

बांधों की सुरक्षा के संबंध में नागपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार शर्मा का कहना है कि हमारे अंडर में जो बांध आते हैं, हम उनकी शासन के निर्देशों के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था करते हैं. जैसे तोतलाडोह में हमारे हथियारबंद गार्ड तैनात किए गए हैं. इसके लिए अभी हमने रोटेशन सिस्टम से गार्डों की तैनाती शुरू की है. जहां तक सीसीटीवी कैमरे व अत्याधुनिक हथियारों की बात है तो जैसे-जैसे शासन से संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं, उसके हिसाब से हम अपने गार्डों को अपडेट करते हैं. सीसीटीवी कैमरे तो पूरे महाराष्ट्र में अभी तक किसी बांध की सुरक्षा की दृष्टि से नहीं लगाए गए हैं. अभी जो अलर्ट होने की सूचनाएं मिली हैं, उसके मद्देनज़र सुरक्षा व्यवस्था में परिवर्तन किया जा रहा है. वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों के लिहाज़ से हम पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं

जल संपदा को प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए: डॉ. आरती सिंह

भंडारा पुलिस अधीक्षक डॉ. आरती सिंह ने बताया कि बांधों की सिक्युरिटी व्यवस्था के लिए जलसंपदा विभाग को प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है. हम उनको ख़ुफ़िया एजेंसियों से प्राप्त सूचनाओं के विषय में अपगत कराते रहते हैं. इनकी सुरक्षा मुख्य रूप से केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को दी जानी चाहिए, जिसकी प्रक्रिया जलसंपदा विभाग को ही पूरी करनी होगी. हमने गोसीखुर्द और बाबनथड़ी प्रकल्पों की सुरक्षा के संबंध में जलसंपदा विभाग को पत्र लिखा था जिसका अब तक जवाब नहीं मिला है. सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करना हमारी ज़िम्मेदारी है, जो समय-समय पर करके हम जलसंपदा विभाग को अपने सुझाव देते रहते हैं.

राजपत्र के जारी हो जाने के पश्चात यह व्यवस्था राज्य की सभी 28 हज़ार से अधिक ग्राम पंचायतों पर लागू हो गई है.

बंधुओं हमारे लिए यह गर्व और सौभाग्य का विषय है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र के नागरिक हैं. लोकतंत्र अर्थात जनता का तंत्र, यानी जनता ही सर्वोपरि.

ख़तरे में बांध

पृष्ठ 17 का शेष

हुए उक्त सभी निर्णयों पर राज्य शासन व राज्य के जलसंपदा विभाग ने कितना ध्यान दिया, यह शोध का विषय हो सकता है. परंतु गूगल में आज भी कोयना सहित सभी बांधों के फोटो और मैप उपलब्ध हैं. इससे ही पता चल जाता है कि बैठक में लिए गए निर्णयों को गंभीरत से नहीं लिया गया. बांधों की सुरक्षा अभी भी राज्य सरकार की सूची में गौण है. विशेष यह है कि इस बैठक में लिए गए निर्णयों की प्रति प्रधान सचिव, जलसंपदा विभाग मुंबई, पुलिस महासंचालक, मुंबई, आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई, पुलिस महानिरीक्षक, कोल्हापुर, ज़िला दंडाधिकारी, सतारा, पुलिस अधीक्षक, सतारा/रत्नागिरी, कार्यकारी संचालक मंडल, कृष्णा खोरे महामंडल, मुख्य अभियंता, कोयना प्रकल्प, सातारा को भेजी गई. इस बैठक में विदर्भ में स्थित बांधों की सुरक्षा पर कोई चर्चा नहीं हुई और लिए गए निर्णय की प्रति मंत्रालय ने भेजी नहीं.

ग़ौरतलब है कि पिछले माह में भारत के गुप्तचर ब्यूरो (आईबी) ने देश की विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों को एक रिपोर्ट भेज कर आगाह किया है कि आतंकवादी देश के बड़े बांधों को विनाशकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए निशाना बना सकते हैं. इसी तरह पिछले साल गुजरात के गुहमंत्री और पुलिस को पत्र भेजकर नक्सलियों ने काकरापार परमाणु केंद्र, उकाई बांध को उड़ाने की चेतावनी दी थी. तब वहां पुलिस निगरानी बढ़ा दी गई थी. नक्सलियों ने छत्तीसगढ़–उड़ीसा की सीमा में स्थित हीराकुंड बांध को उड़ाने की तैयारी भी कर ली थी, पर एयरफोर्स द्वारा दी गई एक रिपोर्ट पर सरकार सतर्क हुई और नक्सलियों के नापाक इरादे नाकाम हो गए. अब एक बार फिर गुप्तचर ब्यूरो ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क करते हुए बांधों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए आगाह किया है. इसलिए महाराष्ट्र हो या पंजाब सभी जगह स्थित बांधों की सुरक्षा करना सरकार की ज़िम्मेदारी बनती है. यहां हमें यह भी ध्यान देना होगा कि भारत में सक्रिय माओवादी (नक्सली) के सूत्र पाक समर्थित आतंकवादियों से जुड़े होने के संकेत हमें समय–समय पर मिलते रहे हैं और नक्सलियों का रेड कॉरीडोर में महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र मुख्य पड़ाव माना जाता है. इस दृष्टि से विदर्भ में स्थित बड़े बांध भी नक्सलियों व आतंकवादियों के निशाने पर होने से इंकार नहीं किया जा सकता है. महाराष्ट्र का कोयना नदी पर बना बांध राज्य का सबसे बड़ा बांध है. यदि कोयना डैम पर आतंकवादी या विदर्भ के निर्माणाधीन गोसीखुर्द बांध पर नक्सली हमला हो जाए और बांध टूट जाए या क्षतिग्रस्त हो जाए तो जानमाल का कितना नुक़सान होगा, इसका अनुमान लगा पाना भी आज असंभव है. विदर्भ में गोसीखुर्द सहित अपर वर्धा, धापेवाड़ा, निमपेढ़ी, खड़कपूर्णा, पेंच प्रकल्प सहित अन्य छोटे बड़े 287 बांध हैं. इसी तरह पूरे राज्य 763 बांध हैं, जिनकी सुरक्षा पर सरकार ने अब तक कोई विशेष ध्यान नहीं दिया है. यहां आतंकवादी और नक्सली आसानी से पहुंच सकते हैं. विदर्भ में भंडारा ज़िले में स्थित गोसीखुर्द बांध फ़िलहाल निर्माणाधीन है, पर ख़तरे से परे नहीं है. इसे राष्ट्रीय परियोजना भी घोषित किया गया है. इस महत्वाकांक्षी सिंचाई परियोजना के तीन–चान सालों में पूरा होने की संभावना है. किसान गोसीखुर्द बांध के पूरा होने पर विदर्भ में सिंचाई से वंचित खेतों को भरपूर पानी मिलने की आस लगाए बैठे हैं. मगर आतंकी और नक्सली इस पर कभी भी ग्रहण लगा सकते हैं. इसकी वजह है गडचिरोली, चंद्रपुर, गोंदिया सहित भंडारा ज़िले के कुछ भागों में नक्सलियों ने अपने पैर पहले ही पसार लिए हैं. उनकी इस बांध तक आवाजाही आसानी से हो सकती है. यह भी आशंका है कि वे यहां आना–जाना करते हों. इस बांध के कभी भी नक्सली हमले के निशाने पर आने की आशंका है.

इन सारे तथ्यों को मद्देनज़र रखते हुए सरकार को अब सुरक्षा बंदोबस्त को लेकर नए सिरे से सोचना होगा. विशेषकर उन संस्थानों व परियोजनाओं की ओर जहां पर किसी तरह का हमला होने पर जानमाल को भारी नुक़सान पहुंचाया जा सकता है. बांधों/जलाशयों पर आतंकवादियों द्वारा जैविक हमला भी किया जा सकता है. यदि बांधों/जलाशयों के पानी में विषैले पदार्थ और ज़हरीले जंतु देश के दुश्मनों द्वारा छोड़ने की आशंका को नजरअंदाज़ नहीं किया जा सकता है. बांधों व ऐसे सभी उपक्रमों की सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से जगह–जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए. बांधों में जिस स्थल से गाड़ियां प्रवेश और बाहर निकलती हैं, वहां पर सीसीटीवी कैमरे के साथ ही उनके नंबर और चालक–मालिक के नामों को रजिस्टर पर दर्ज किए जाने की व्यवस्था होनी चाहिए. ओर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आतंकवादी हों या नक्सली उनका मुख्य उद्देश्य भारत को अधिक से अधिक आर्थिक व मानवीय क्षति पहुंचाना है. यदि हमें इस नुक़सान को नहीं होने देना है तो मुंबई व गड़चिरोली में होने वाले आतंकी–नक्सली हमलों से सबक़ लेते हुए पहले से ही सतर्क रहना होगा.

feedback@chauthiduniya.com

महाराष्ट्र हलचल

गिरणी मिल कामगारों के एक शिष्टमंडल से अपने निवासस्थल वर्षा में मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण गृहनिर्माण राज्यमंत्री सचिन अहिर, मुख्य सचिव रत्नाकार गायकवाड़ के साथ चर्चा करते हुए.

उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के जन्मदिन के अवसर पर प्रकाशित पुस्तक स्टेट फारवर्ड का विमोचन करते राकांपा प्रदेशाध्यक्ष मधुकरराव पिचड़, विधान सभा अध्यक्ष दिलीप वलसे पाटील, मंत्री बबनराव पाचपुते, महासचिव प्रमोद हिंदूराव, संपादक गणेश अंबिलवाड़े, पत्रकार नंदकुमार सुनार व अन्य.

पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री व सांसद गुरुदास कामदत अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान मुंबई अंधेरी निर्वाचन क्षेत्र की जनता की समस्याओं व शिकायतों को सुनते हुए. साथ में क्षेत्र के नगरसेवक भी उपस्थित हैं.

गिरणी कामगारों के घरों के प्रश्न पर शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे दादर स्थित शिवसेना भवन में पत्रकारों से चर्चा करते हुए, उनके साथ भाजपा के माहसचिव गोपीनाथ मुंडे और रिपब्लिकन नेता रामदास आठवले भी उपस्थित हैं.

बहुराष्ट्रीय कंपनियों को खुदरा व्यापार करने की सरकार द्वारा अनुमति दिए जाने का विरोध करते हुए नागपुर के खुदरा व्यापारी.

कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव बनकर नागपुर आगमन पर सांसद विलास मुत्तेमवार का हवाई अड्डे पर स्वागत करते पार्टी कार्यकर्ता.

विजय दिवस पर नागपुर में परेड करते एन.सी.सी. कैडेट्स.

महिलाओं के हाथ पंचायत राज

राजेश नामदेव

महाराष्ट्र की राजनीति में महिलाओं का दबदबा राजनीति में बढ़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं. इसकी वजह है राज्य की ग्राम पंचायत निर्वाचन में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण विधेयक का लागू हो जाना. इस क़ानून के लागू होने के बाद अब बारी है इसके क्रियान्वयन की. अब भविष्य में होने वाले ग्राम पंचायत चुनावों में आधी जनप्रतिनिधि आसपड़ोस की महिलाएं ही होंगी, जिसका राजनीति में असर पड़ना स्वाभाविक है. इस तरह राज्य की कुल ग्राम पंचायतों में 14 हज़ार 105 की बागडोर महिला सरपंचों के हाथ में होगी. यह भविष्य की राजनीति में महिलाओं के बढ़ते क़दम को रेखांकित करेगा. इसके साथ ही राज्य की आधी आबादी को मिलेगा राज सम्मान.

ज्ञात रहे की देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद में राजनीति में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने पर भले सहमति न बन सकी हो. महिलाओं को आरक्षण देने के मामले में नेताओं द्वारा राजनीतिक दांवपेंच चले जा रहे हों, पर महाराष्ट्र की विधानसभा ने राज्य के स्थानीय निकाय के चुनावों में 50 प्रतिशत स्थान महिलाओं को आरक्षण देने संबंधी विधेयक पहले ही पारित कर दिया है. अब आगे होने वाले चुनावों में इस पर अमल होते ही राज्य की आधी आबादी यानी महिलाओं की एक नई खेप राजनीति में सक्रिय हो जाएगी. राज्य सरकार ने महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण संबंधी अपने निर्णय को 23 जुलाई को जारी राजपत्र में प्रकाशित किया है. मुंबई ग्राम पंचायत निर्वाचन अधिनियम 1964 में नियम 2–अ उपबंध (1) व (2) में अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और खुले प्रवर्ग के लिए आरक्षित सरपंच पदों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था की है. राजपत्र के जारी हो जाने के पश्चात यह व्यवस्था राज्य की सभी 28 हज़ार से अधिक ग्राम पंचायतों पर लागू हो गई है. इस व्यवस्था के लागू होने के बाद होने वाले ग्राम पंचायत चुनावों के बाद 14105 ग्राम पंचायत के मुखिया (सरपंच) की ज़िम्मेदारी महिलाएं संभालेंगी और बाक़ी 14 हज़ार की सरपंची पुरुष संभालेंगे. इस आदेश में राजपत्र में राज्य के 33 ज़िलों की 28 हज़ार 211 ग्राम पंचायतों का ज़िलावार उल्लेख किया गया है. एक हज़ार से अधिक ग्राम पंचायतों वाले ज़िले पुणे (1320), सोलापुर (1028), कोल्हापुर (1028), जलगांव (1124), अहमदनगर (1215), नांदेड (1168), बीड (1019), यवतमाल (1052) में पाच सौ से अधिक महिलाओं को सरपंच पद मिलेगा. इसका राजनीति में दूरगामी परिणाम होने की संभावना राज्य के राजनीतिक विश्लेषक व्यक्त कर रहे हैं. इसी तरह विदर्भ की 7655 में से भी आधी ग्राम पंचायतों पर महिलाओं का वर्चस्व होगा.

महिला आरक्षण की इस व्यवस्था के बाद अब राजनीतिक दलों पर ग्राम पंचायत स्तर पर महिला उम्मीदवारों की तलाश अभी से शुरू हो गई है. सभी राजनीतिक दलों के महिला संगठनों में भागदौड़ मच गई है. योग्य महिलाओं–युवतियों की सूची बनाई जाने लगी है, ताकि समय आने पर उन्हें ग्रामपंचायत चुनाव में उतारा जा सके. संभावना यह भी व्यक्त की जा रही है कि इससे सत्ता का विकेंद्रीकरण और भी निचले स्तर तक हो सकेगा. साथ ही इसका अनुमान भी लगाया जा रहा है कि स्थानीय संस्थाओं

के रूप में सत्ता का जो विकेंद्रीकरण हुआ है, उस पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ने का क्या असर पड़ेगा? मगर इसका उचित जवाब तो भविष्य मे तभी मिलेगा जब ज़मीनी स्तर पर महिलाओं का राजनीति पर दख़ल बढ़ेगा. इतना अवश्य निश्चित है कि भविष्य में सत्ता महिलाओं के हाथ में होगी, परंतु कुछ शंकाएं भी व्यक्त की जा रही हैं कि महिलाओं को आगे करके राजनीति का असली खेल तो पुरुष ही खेलेगा. कुछ महिलाएं की राजनीति में अपनी छाप छोड़ पाएंगी. इसकी वजह यह है कि भारतीय समाज पुरुष प्रधान व्यवस्था का अभ्यस्त है. बहरहाल इन शंकाओं का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आज की नारी हर क्षेत्र में छाप छोड़ रही है. वर्तमान में यदि देश की राजनीति और सत्ता पर नज़र डालें तो ऊपर से लेकर नीचे तक महिलाओं की सक्रियता दिखाई देती है. देश की राष्ट्रपति महिला है. सत्तारूढ़ दल की मुखिया, मुख्य विपक्षी दल का लोकसभा में नेता, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री महिलाएं हैं. राज्य व केंद्रीय मंत्रिमंडल में अनेक महिलाएं कई मंत्रालयों का कामकाज सफलतापूर्वक संभाल रही हैं. राज्य में ही मुंबई व नागपुर जैसी नगरपालिकाओं में महापौर पद की शोभा महिलाएं ही बढ़ा रही हैं. ग्रामपंचायतों पर महिलाओं की सक्रियता पहले से और कई जगह महिला सरपंच हैं उसी को और विस्तार 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था को करके दिया गया है. आज की महिलाएं खुलकर राजनीति में हिस्सा ले रही हैं और सांसद, विधायक से लेकर ज़िला परिषद, महानगर पालिका, पंचायत समिति व ग्रामपंचायत में जनप्रतिनिधित्व कर रही हैं. यह स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेश सरकार का राज्य की महिलाओं के लिए एक तोहफ़ा है.

feedback@chauthiduniya.com

शिक्षा पर ग़रीब बच्चों का हक़

आलोक मिश्रा

[illegible]

संचालकों का यह भी कहना है कि ग़रीबों के बच्चों को स्कूल में लेने पर परीक्षा परिणाम भी प्रभावित होंगे जो जिससे स्कूल की छवि पर असर पड़ेगा. उनका यह भी कहना है कि एक ओर सरकार निजी स्कूलों के ख़िलाफ़ शुल्क नियंत्रण क़ानून बना रही है. दूसरी ओर ग़रीबों के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत जगह आरक्षित करने पर ज़ोर दे रही है. ग़रीब लोग तो सहज में ही फीस बढ़ाने का विरोध करेंगे. ऐसे में तो स्कूल चलाना मुश्किल हो जाएगा. निजी स्कूल संचालकों की इन बातों का उल्लेख करते हुए कई मंत्रियों ने मंत्रिमंडल की बैठक में विरोध जताया.

feedback@chauthiduniya.com

प्रावधान के तहत जिन ग़रीब बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश दिया जाएगा, उनकी फीस व अन्य ख़र्च का भुगतान सरकार द्वारा स्कूलों को किया जाएगा. मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार शिक्षा के अधिकार अधिनियम में ग़रीबों के बच्चों को निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत अनिवार्य रूप से प्रवेश दिए जाने को लेकर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है. इस वजह से इसे लागू नहीं किया जा सकता है. यह अचंभे की बात है कि उक्त क़ानून का क्रियान्वयन अभी तक नहीं हुआ है..

मनपा-भाजपा में असंतोष

विचारहीन राजनीति में कोई किसी का अहसानमंद नहीं होता है. सभी अवसर की ताक में रहते हैं. मौक़े का फ़ायदा उठाना चाहते हैं. बस तलाश रहती है एक अवसर, एक मौक़े की. इस वैचारिक संकट से आज भाजपा भी गुज़र रही है. इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी के गृहनगर में पूछा जा रहा है कि क्या भाजपा मनपा की सत्ता में पुनः वापसी करेगी? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अगले वर्ष नागपुर महानगर पालिका के चुनाव हैं. इसके बावजूद नगर का भाजपा नेतृत्व निष्क्रिय है. पार्टी में असंतोष तेज़ी से पनप रहा है. बढ़ते असंतोष को रोकने का प्रयास फ़िलहाल न पार्टी का महानगर पालिका का नेतृत्व कर रहा है और न प्रदेश नेतृत्व. इसी का नतीजा है कि मनपा में पार्टी के वरिष्ठ पार्षद बाय–बाय टाटा कर कांग्रेस का दामन थाम लिया. मनपा चुनाव के पहले दो वरिष्ठ पार्षदों का छोड़कर जाना पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं है. इसके अलावा भाजपा के मनपा अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगातार बढ़ते जा रहे हैं.

इस बार भाजपा में असंतोष के नायक बने हैं मनोनीत सदस्य रमन पैगवार और पूर्व महापौर मजीद शोला. यह भी कहा जा रहा है कि भाजपा के अनेक मनपा सदस्य अपनी उपेक्षा से दुःखी हैं और वे भी बग़ावत की राह पर कभी भी निकल सकते हैं. इससे भाजपा की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं. इन दोनों वरिष्ठ पार्षदों की बग़ावत से भाजपा सकते में है और संभवतः आत्ममंथन में लग गई है. इस पर विचार किया जा रहा है कि क्या कारण है कि पार्टी से सबकुछ मिलने के बाद भी वे पार्टी छोड़ने को मजबूर हुए? हालांकि मनपा में सत्तापक्ष के नेता प्रवीण दटके यह मानने को तैयार नहीं है कि पैगवार और मजीद शोला के कांग्रेस में जाने से भाजपा को किसी तरह का नुक़सान होगा. वे यह भी कहते हैं कि दोनों पार्षदों को लेने से कांग्रेस को भी लाभ नहीं होने वाला है. विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि रमन पैगवार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गडकरी के क़रीबी माने जाते हैं. उनको गडकरी ही भाजपा में लाए थे. उनके कारण ही पैगवार को मनपा का मनोनीत सदस्य बनाया गया था. इसके बाद भी उनका पार्टी छोड़कर जाना किसी की समझ में नहीं आ रहा है. वहीं मजीद शोला पार्टी की ओर से उपमहापौर, स्थायी समिति का तीन बार सदस्य बनाए जाने के बाद भी भाजपा में असुरक्षा की भावना से ग्रस्त थे. यह असुरक्षा की भावना अधिक रहस्यात्मक लग रही है. इसकी वजह यह है कि कांग्रेस में इनको क्या मिलने वाला है. वैसे भी कांग्रेस में पहले से ही महापौर पद के दावेदारों की कमी नहीं है. फिर कांग्रेस ने दोनों को ऐसा क्या लालच दिया कि भाजपा से बग़ावत करके अपनी मनपा सदस्यता के ख़तरे में पड़ने की परवाह भी नहीं की. दोनों के नज़दीकी लोगों की बात मानी जाए तो बात कुछ और है. दोनों की महत्वाकांक्षाएं बड़ी हैं. मजीद शोला अब नगर से उठकर राज्य की राजनीति में आना चाहते हैं और पैगवार को भाजपा के नेता उनके रवैये के कारण पचा नहीं पा रहे थे. अब वजह चाहे जो भी हो पर ख़ामियाज़ा तो भाजपा को भुगतना पड़ रहा है. सुनने को तो यह मिल रहा है कि गडकरी इस ख़बर से नाखुश हैं और आगवन पर नागपुर के नेताओं की क्लास लेने वाले हैं.

अब भाजपा का हाल खिसियानी बिल्ली–सा है. खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे की कहावत को चरितार्थ करते हुए भाजपा के नेता कह रहे हैं कि दोनों की मनपा सदस्यता रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इस संबंध में विभागीय आयुक्त, मनपा आयुक्त और महापौर को पत्र लिखकर पैगवार और शोला की सदस्यता रद्द करने की सिफ़ारिश की गई है, क्योंकि अब तक दोनों ने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफ़ा नहीं दिया है. इन दोनों के इस्तीफ़े के बाद मनपा की 27 जुलाई को आयोजित विशेष सभा को भी विपक्ष व सत्तापक्ष के सदस्यों के हंगामे के बीच घंटे भर में समेट लिया गया. उसके बाद ज़ुबानी जमा ख़र्च कर आरोप–प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ. जहां मनपा सत्तापक्ष के नेता दटके दोनों पाला बदल कर कांग्रेस में गए पार्षदों की सदस्यता रद्द कराने की बात कर रहे हैं, वहीं बाग़ी पैगवार का कहना है कि भाजपा नेता अनुभवहीन हैं. उन्हें नियम–क़ायदे का ज्ञान नहीं है. पैगवार कहते हैं कि उनकी नियुक्ति राज्यपाल ने महाराष्ट्र शासन की अनुशंसा और मनपा सभागृह में लिए गए निर्णय के आधार पर की है. इसलिए भाजपा नेताओं को पहले क़ानूनी जानकारी ले लेनी चाहिए उसके बाद सदस्यता रद्द करने की बात करें. इस तरह खिसियाने से कुछ हासिल नहीं होगा.

दूसरी ओर मनपा प्रशासन से भी उपराजधानी की जनता ख़ुश नहीं है. मकान टैक्स, पानी टैक्स सहित मनपा में कामकाज को लेकर व्याप्त फ़ीताशाही से आक्रोश बढ़ता जा रहा है. महापौर अर्चना डेहनकर के महापौरी कार्यकाल में एक भी कार्य ऐसा नहीं हुआ कि उसे भाजपा की सत्ता की उपलब्धि माना जाए. जब से संदीप जोशी स्थायी समिति के अध्यक्ष बने हैं तब से घोषणाओं के अलावा कुछ नहीं हुआ. इसीलिए उन्हें विपक्षी नेता घोषणाबाज़ अध्यक्ष बतलाते हैं. सत्तारूढ़ भाजपा पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप बढ़ते जा रहे हैं जिससे विपक्ष को आक्रमण करने का मौक़ा मिल गया है. विपक्ष के सदस्यों के अलावा सत्तारूढ़ दल के कुछ सदस्य भी कई मुद्दों पर भ्रष्टाचार की आशंका जता चुके हैं. कांग्रेस नेता व पूर्व महापौर विकास ठाकरे का आरोप है कि सत्तारूढ़ दल के पदाधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं. यही कारण है कि नागार्जुन, सड़क, कचरा, पानी, पथदीप, कारटेल व स्टार बस जैसे जनहित से जुड़े मुद्दों पर वे चर्चा करने को तैयार नहीं हैं. होर्डिंग के मामले में उच्च न्यायालय ने कारटेल से पांच करोड़ रुपये वसूलने के निर्देश दिए हैं. मनपा ने 100 करोड़ रुपये की लागत से सड़क निर्माण करने का प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन नगर के कई इलाक़ों में पक्की सड़कें नहीं हैं. सड़कों की हालत ख़स्ता है. 27 जुलाई की सभा में इन मुद्दों पर चर्चा के उपरांत हस्तांतरण व आरक्षण रद्द करने के मुद्दे पर पूरा विपक्ष चर्चा करने को तैयार था. इसके बावजूद महापौर ने पहले विषय पत्रिका के विषयों पर चर्चा शुरू की, जबकि विषय पत्रिका के मुद्दों पर चर्चा के पश्चात सभा ख़त्म हो जाती है. महापौर के इस क़दम से सभा उस दिन नहीं हो सकी. ठाकरे के इन आरोपों का भाजपा के पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं है. ऊपर से पार्टी में फूट रहे असंतोष के स्वर चिंता का कारण हैं. भाजपा पार्षद अपने महापौर और पदाधिकारियों से दुःखी हैं. सिर पर मनपा चुनाव है और भाजपा सत्ता की ख़ुमारी में खोई हुई है. उसे ऐसा लगता है कि अगली बार भी उसी की सत्ता रहेगी, परंतु यहां के राजनीतिक विश्लेषकों की राय भाजपा नेताओं से जुदा है. सभी का मानना है कि भाजपा की यदि मनपा सत्ता की ख़ुमारी समय रहते नहीं उतरी तो उसके पुनः वापसी की कोई संभावना नहीं है. साथ ही पार्टी को ज़मीनी हक़ीक़त का आंकलन करके अभी से चुनावी तैयारी में जुटना होगा. वैसे इतना होने के बाद भी भाजपा यदि अपनी साख बचा ले तो चमत्कार से कम नहीं होगा. गडकरी को ही अपना घर दुरुस्त करना पड़ेगा.

उल्लेखनीय बात यह है कि रमन पैगवार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गडकरी के क़रीबी माने जाते हैं. उनको गडकरी ही भाजपा में लाये थे. उनके कारण ही पैगवार को मनपा का मनोनीत सदस्य बनाया गया था. इसके बाद भी उनका पार्टी छोड़कर जाना किसी की समझ में नहीं आ रहा है. वहीं मजीद शोला पार्टी की ओर से उपमहापौर, स्थायी समिति का तीन बार सदस्य बनाए जाने के बाद भी भाजपा में असुरक्षा की भावना से ग्रस्त थे. यह असुरक्षा की भावना अधिक रहस्यात्मक लग रही है.

अब्दुल मजीद शेख़ इब्राहिम

रमण ईश्वरसिंग पैगवार

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

ये क्या हो रहा है...

कालवा का बलवा

कहीं नहर फूटने से किसानों की फ़सल बर्बाद हो रही है. कहीं फ़सलों को पानी ही नहीं मिल रहा है. माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है. किसान परेशान हैं. एक ओर भ्रष्टाचार की दीमक जहां कालवा (नहर) को खा गई और वह फूट गई. पानी आस–पास के खेतों में घुस गया, जिससे फ़सल चौपट हो गई. वहीं दूसरी ओर खेत सूखने तक की नौबत आ गई है. वे बार–बार संबंधित अधिकारियों से लिखित–मौखिक मांग, अनुनय–विनय करके थक गए. अंततः उनका आक्रोश बढ़ा और फूट पड़ा. किसानों–खेतों को उनके हक़ का पानी नहीं मिल रहा है. दोनों ही घटनाएं नागपुर ज़िले की आसपड़ोस की तहसीलों में घटित हुईं यानी पारशिवनी और रामटेक. जब जनता की कोई सुनवाई नहीं हो तो सरकार और जलसंपदा विभाग के रहने का क्या मतलब. ऐसा लगता है कि जलसंपदा विभाग के आला अधिकारी से लेकर नीचे तक सब सोए हुए हैं. क्यों राज्य के चव्हाण साहब? साहब आप तो एसी कमरे में काम कर रहे हैं और बेचारे किसान आपके मातहत कार्यकारी अभियंता काले की मनमर्ज़ी के कारण मुसीबत में हैं. आख़िर ये क्या हो रहा है? आख़िर हर साल नहरों की दुरुस्ती के नाम पर ख़र्च होने वाले लाखों–करोड़ों रुपये जाते कहां हैं? पारशिवनी में गुंडरी पंडे पर जहां पिछले दिनों नहर फूटी थी उसी जगह पिछले साल भी फूटी थी. मगर जिस ठेकेदार ने दुरुस्ती का काम किया था, उसने वहीं का पड़ा मटेरियल उपयोग कर जैसे–तैसे काम पूरा कर, दिखाकर, लाखों रुपये अपनी तिजोरी में डाल लिए. मतलब साफ़ है कि उस नहर को भ्रष्टाचार की दीमक लग गई है. यही कारण है कि वह हर साल फूटती है और संबंधित अधिकारी व ठेकेदार की जोड़ी मिल–बांटकर अपनी तिजोरी नोटों से भरते हैं. नुक़सान किसान का होता है. वह बेचारा साल दर साल क़र्ज़ के बोझ से दबा जाता है. अधिकारी–ठेकेदारों की ज़मीन–जायदाद, बैंक बैलेंस दिन–दूनी, रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ते जाते हैं. आपको पता है चव्हाण साहब, आपके आने से पहले 192 कार्य बिना टेंडर मंगा दिए. इन कार्यों के लिए करोड़ों का भुगतान हुआ. अब कितना काम हुआ और कितना काम नहीं हुआ इसका पता आप लगाइए. या दक्षता पथक को सौंप दिया जाए. हां, इतना सुनने को ज़रूर मिला कि इन कार्यों के लिए ठेकेदारों को समय पर भुगतान कर दिया गया, बिना निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच–परख किए. वैसे भी कहा जाता है कि बिना टेंडर के काम जो होते हैं वे अपनों को उपकृत करने के लिए होते हैं. काम हो या न हो इससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता है. अब दूसरा मुद्दा पानी पर किसानों के हक़ का है. आपके मंत्री महोदय कहते हैं कि पानी पर पहला हक़ किसानों–खेतों का है, परंतु आपके क्रिया–कलाप देख कर ऐसा नहीं लगता है. ऐसा लगता है कि सबसे पहले पानी आपके अधिकारियों का है. उसके बाद पानी उसका है जिसका परिचित अधिकारी बैठा है. दूसरे किसानों को मिले, न मिले, इससे आपके अधिकारियों को कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता है. रामटेक–काचुरवाही क्षेत्र में बारिश कम हुई है. इस तथ्य से सभी परिचित हैं. मौसम ख़रीफ़ फ़सल का है. किसान पहले शाखा अभियंता मेश्राम और फिर कार्यकारी अभियंता काले से बार–बार गुज़ारिश की कि साहब पानी छोड़ दो, नहीं तो हमारी फ़सलें चौपट हो जाएंगी. मगर काले साहब को किसानों पर रहम नहीं आया. दिल नहीं पसीजा. अरे, जब डैम में पानी पर्याप्त था. चार दिन बाद छोड़ा जाना था. फिर क्यों नहीं किसानों की ज़रूरत को देखते हुए पानी नहर में छोड़ा गया? सरकार व प्रशासन किसकी सुविधा के लिए बनाया गया है? यदि जलसंपदा विभाग जिन किसानों व खेतों को पानी देने के लिए बनाया गया है यदि उनके काम नहीं आ सकता तो ऐसे विभाग के रहने का क्या फ़ायदा? आप जैसे अधिकारियों को वेतन–भत्ते के नाम पर दी जाने वाली मोटी रक़म देने का क्या मतलब? चार दिन पहले पानी छोड़ने से न पेंच प्रकल्प सूख जाता और न काले साहब की सेहत पर कोई असर पड़ता. इसका तो यही अर्थ होता है कि जलसंपदा विभाग अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर रहा है. आपके अधिकारी कुंडली मारकर नागोबा की तरह बैठे हैं और किसी पीड़ित किसान के आने पर फुंफकारने लगते हैं. यही कारण है कि जब किसानों का आक्रोश फूटता है तो वे भी तोड़फोड़ मचा देते हैं. अब आपको सोचना है कि आपके राज में ये क्या हो रहा है.....

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

स्वाधीनता दिवस (15 अगस्त) पर विशेष

जनता को जगाने के लिए स्वावलंबन की अलख जगाओ

भय्यूजी महाराज

भारतभूमि के समस्त बंधु–बांधवों, माताओं–बहनों अगस्त का महीना राष्ट्रवासियों के लिए प्रतिवर्ष एक नया संदेशा, नया पैग़ाम लेकर आता है. इस महीने की 15 तारीख़ को हम सभी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, पर हमें सोचना पड़ेगा, गहराई से चिंतन करना पड़ेगा, स्वतंत्रता या स्वाधीनता का तात्पर्य क्या है? 15 अगस्त को हम राष्ट्र की स्वतंत्रता की 58वीं वर्ष मनाएंगे. फिर वही सिलसिला चलेगा एक–दो दिन देशभक्ति के तराने गूंजेंगे, ध्वजारोहण किया जाएगा, समारोह होंगे, गोष्ठियां होंगी, जलसे होंगे, महान महापुरुषों और भारत मां के वीर सपूतों की शहादत को हम नमन करेंगे. 15 के 16 अगस्त, 17 अगस्त आएगी और हम फिर अपने काम–धाम, चौके–चूल्हे, घर–गृहस्थी, नौकरी–पानी के काम में जुट जाएंगे. 57 वर्षों से यही तो होता आ रहा है. हर साल अगस्त महीना आते ही हमें 15 अगस्त की याद आ जाती है. चंद आयोजनों के बाद और राष्ट्रध्वज को एक दिन फहराकर हम अपने कर्तव्यों की, दायित्वों की इतिश्री समझ लेते हैं.

किंतु हमने आज तक यह समझने की चेष्टा नहीं कि आज़ादी क्या होती है, कर्तव्य क्या होता है, दायित्व क्या होते हैं? और सबसे अहम तो यह कि राष्ट्र क्या होता है. राष्ट्र का अस्तित्व और इसकी शक्तियां कहां निहित है, कौन इसका खेवनहार है?

बंधुओं हमारे लिए यह गर्व और सौभाग्य का विषय है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र के नागरिक हैं. लोकतंत्र अर्थात जनता का तंत्र, यानी जनता ही सर्वोपरि, किंतु यह बड़े खेद का विषय है कि हम आज तक जनता को अपने कर्तव्यों, अधिकारों का बोध नहीं करा सके. यदि हम सच्चाई से बात करें और यथार्थ के धरातल पर आएं तो वास्तविकता यही सामने आएगी कि जनता के कर्तव्यों, अधिकारों राष्ट्र के प्रति इसके दायित्वों को समझाने में हम अभी तक नाकाम ही हुए हैं. यह ज़िम्मेदारी किसकी है? यह ज़िम्मेदारी हम सबकी है. हमें जनता की जागृति के लिए, स्वावलंबन के लिए अपने हृदय को टटोलना होगा. यह तथ्य विचारणीय है कि जब तक जनता स्वावलंबी नहीं होगी तब तक राष्ट्र भी स्वावलंबी नहीं होगा. मौजूदा हालत में हम राष्ट्र की तस्वीर देखें तो हृदय पसीज उठता है, ख़ून खौलने लगता है. समाज के प्रत्येक क्षेत्र में नैतिकता और इसके मूल्यों के लगातार हुए पतन में राष्ट्र की अस्मिता को झकझोर कर रख दिया है. अत्याचार, अनाचार, उत्पीड़न, शोषण, आडंबर, ढोंग–दिखावे, लड़ाई–झगड़ों, आतंकवाद, अलगाववाद, स्वार्थपरता ने देश को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से जितनी जल्दी उबर सकें इतना ही बेहतर है. बंधुओं इतिहास और यहां तक कि दुनिया का भूगोल भी इस बात का साक्षी रहे है कि दुनिया में जो भी राष्ट्र ऊपर उठे हैं वे स्वावलंबी बनकर ही आगे बढ़े हैं. आपदाओं, विपदाओं से जूझकर, हालात से लड़कर ये राष्ट्र आगे बढ़े हैं. दुनिया में जहां कहीं भी किसी देश ने तरक़्क़ी की है वह जनता के बलबूते ही की है. इन देशों की जनता ने अपने दायित्वों, कर्तव्यों और अधिकारों को भलीभांति समझा. इस जनता को यह समझाने वालों ने भी सच्चे मन से सशक्त नेतृत्व दिया, तभी वे देश स्वावलंबी बन सके. बंधुओं यह हमारा परम सौभाग्य है कि हम इस महान वैदिक सनातन संस्कृति को अंगीकार करने वाली पावन भूमि पर रहते हैं, जिस भूमि से महान संतों, धर्माचार्यों, ऋषि–मुनियों, महापुरुषों और वीर सपूतों ने समूची दुनिया को सुसंस्कृत, नैतिक आचरण, समभाव, सहिष्णुता, शालीनता का सबक़ सिखाया. आश्चर्य तो यह कि दुनिया के तमाम मुल्कों ने हमारे धर्म, अध्यात्म और संस्कृति को आत्मसात करके अपने आपका कल्याण कर लिया, परंतु हमने धर्म, अध्यात्म और संस्कृति को समझने में भारी ग़लतियां की. मैं यहां यह स्पष्ट कहना चाहूंगा कि कई धर्माचार्यों, भगवाधारियों ने जनता को न तो धर्म और अध्यात्म की वास्तविक परिभाषा बताई और न ही जनता को धर्म के मर्म को समझने का मौक़ा दिया. पाखंड, आडंबर का ताना–बाना बुनकर इन पाखंडियों ने जनता को भ्रमित कर दिया, जिसका नतीजा यह निकला कि आज भी जनता धर्म और अध्यात्म का सही अर्थ नहीं समझती. ज़्यादातर लोग सिर्फ़ माला जपने, मंदिर जाने, तिलक लगाने को ही धर्म समझ बैठे हैं. जब तक हम यह नहीं समझ लेते कि वास्तव में धर्म क्या है? इसका मर्म क्या है? तब तक हम स्वावलंबी नहीं बन सकते, अपने दायित्वों का बोध हमें ज्ञात नहीं होता, तब तक हम सर्वांगीण विकास की बात नहीं कर सकते. जब तक हम जनता के दिलों में राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव का जज्बा नहीं पैदा कर सकते, तब तक हम तरक़्क़ी का सपना भी नहीं देख सकते. उन्नति के शिखर पर पहुंचने के लिए हमें जनता को जाग्रत कर इसे स्वावलंबी बनने के लिए प्रेरित करना होगा, इसमें दायित्वबोध, कर्तव्यबोध का भाव जागृत करना होगा. यही सच्चा धर्म है. भारत की आत्मा गांवों में बसती है, हम जब तक गावों को उन्नत शहरों की मानिंद सर्वसुविधा संपन्न नहीं बनाते, इस गांव की जनता को स्वावलंबी नहीं बनाते, तब तक हमें चैन की नींद सोने का अधिकार नहीं है. हमें इन दो दिनों 15 अगस्त और 26 जनवरी के अलावा प्रत्येक दिन जनता के पास जाना होगा, इसे राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को लेकर जागृत करना पड़ेगा तभी राष्ट्र के स्वावलंबन के लिए हम सपना संजोने के अधिकारी हो सकते हैं.

दुनियां में जहां कहीं भी किसी देश ने तरक्की की है वह जनता के बाजुओं के बलबूते से ही की है. इन देशों की जनता ने अपने दायित्वों, कर्तव्यों और अधिकारों को भली-भांति समझा. इस जनता को यह समझाने वालों ने भी सच्चे मन से सशक्त नेतृत्व दिया, तभी वे देश स्वावलंबी बन सके.

(लेखक जाने–माने संत हैं)

feedback@chauthiduniya.com

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. DELHIN/2009/30467

भारत-बांग्लादेश और भारत-नेपाल सीमा से घुसपैठ के मामले निरंतर बढ़ रहे हैं. आईएसआई कश्मीर केमुस्लिम युवाओं को भी भारत विरोधी मुहिम में इस्तेमाल कर रहा है.

मुंबई धमाके

भारत को लहूलुहान करने की साज़िश

बिग्रेडियर हेमंत महाजन

भारत में आतंकी गतिविधियों के चलते वर्ष 2009 में 1019 आम नागरिक, 372 सुरक्षा कर्मी और 1220 आंतकवादी, ऐसे कुल 2611 लोग मारे गए. 2010 में भी कमोबेश यही स्थिति रही. 976 नागरिक, 459 सुरक्षाकर्मी, 707 आतंकी, कुल मिलाकर 2132 लोग मारे गए. गंभीर रूप से घायलों की संख्या 10000 से अधिक है. इन आंकडों से हमारे पड़ोसी (दुश्मन) पाकिस्तान और उसकी कुख्यात ख़ुफ़िया एजेंसी आईएसआई की आंतक फैलाने की विलक्षण क्षमता का पता चलता है. भारत में प्रति वर्ष औसतन 2500 लोग आतंकी घटनाओं का शिकार होते हैं. न ही मेरे पास और न ही और किसी के पास हाल में हुए मुंबई धमाकों से जुड़े कुछ सवालों के जवाब हैं. चाहे वह सरकार के आला अफ़सर हों या समाचार एजेंसियों से जुड़े, हर कोई कुछ अनसुलझे सवालों के जवाब चाहता है. जैसे ही राहत और बचाव अभियान ख़त्म हो जाता है, घटनाओं की जांच और कड़ियों को जोड़ने का कार्य पूरा हो जाता है. आने वाले कुछ हफ्तों में इन सवालों के जवाब पूरी ईमानदारी से दिए जाने चाहिए.

- इन धमाको के पीछे कौन है?
- क्या इन धमाकों को रोका जा सकता था? क्या यह ख़ुफ़िया एजेंसियों की असफलता है?
- घटना के बाद पुलिस, फायर ब्रिगेड, अस्पतालों और अन्य आकस्मिक प्रतिक्रिया दलों की कार्रवाई संतोषजनक थी? क्या 26/11 के मुंबई हमले से हमने कोई सबक़ लिया?
- भविष्य में हम ऐसे हमलों को कैसे रोक पाएंगे? क्या पिछली आतंकी घटनाओं के आधार पर कोई ठोस रणनीति बनाई गई है.
- विभिन्न हमलों के लिए ज़िम्मेदार आतंकियों के संबंध में जल्द से जल्द फ़ैसला करने की क्या योजना बनाई गई है?
- घटना के बाद मीडिया व्यवस्थापन कितना प्रभावी साबित हुआ. विशेष रूप से टीवी समाचार चैनलों द्वारा घटना का कवरेज क्या आम लोगों तक विश्वसनीय सूत्रों से भरोसेमंद जानकारी शीघ्र पहुंच सकी?

● **ख़ुफ़ियां एजेंसियों की असफलता –** क्या मुंबई हमला ख़ुफ़िया सूत्रों की असफलता का नतीजा है ? ऐसा ही प्रतीत होता है. विभिन्न आतंकी घटनाओं का विश्लेषण करें तो स्पष्ट है कि इसके पीछे हमारी सुरक्षा मशीनरी की नाकामी है. वस्तुतः ऐसा नही होना चाहिए. जिस तरह हम नहीं चाहते कि कभी कोई सड़क दुर्घटना हो, हम सदैव सच बोलें, सभी नागरिक मतदान करें आदि. उसी तरह हम सभी सही पूर्वानुमान, रोकथाम योजना चाहते हैं और उसकी मांग करते हैं. पर क्या यह बढ़ती आबादी का बोझ झेल पा रहे हैं. विभिन्न मुद्दों पर विभाजित भारत में सब संभव है, जहां वोट बैंक की राजनीति से शासन चलाया जाता है. एक बात सदैव याद रखनी चाहिए कि बुरे व्यक्ति को केवल एक बार सफल होना पड़ता है, जबकि अच्छे व्यक्ति को सदैव और बार-बार सफलता हासिल करनी पड़ती है. सवाल यह है की क्या हमले को उस ख़तरनाक आतंकी संगठन के पुनर्गठित प्रकोष्ठ ने अंजाम दिया जो 26/11 के हमले के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा-व्यवस्था के कारण लगभग निष्क्रिय पड़ा हुआ था या किसी नए आतंकी संगठन द्वारा? चाहे आतंकी संगठन नया हो या पुराना, उसके विषय में जानकारी हासिल करने में हमारी ख़ुफ़िया एजेंसियां नाकाम रही हैं. सतर्कता एजेंसियों की सफलता आतंकी संगठनों के भेद जानने में है. इसके लिए संपर्कों का नेटवर्क मज़बूत होना चाहिए. आतंकी घटनाओं के बाद आतंकी विचारधारा से जुड़े सूत्र पुलिस को जानकारी देने से कतराते हैं, क्योंकि उन्हें ही संदिग्ध हमालवार समझ लिया जाता है. हमलों को रोकने की हमारी सतर्कता एजेंसियों की क्षमता और उपायों की पुन:समीक्षा किए जाने की आयश्कता है.

● **क्या हुआ सीसीटीएनएस का? –** पुलिस थानों के बीच समय पर संपर्क न होने की समस्या को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क सिस्टम (सीसीटीएनएस) को क्रियान्वित करने का फ़ैसला किया है. इस योजना की संकल्पना मुंबई हमले से पहले 7 मई 2008 को रखी गई थी. योजना का उद्देश्य पुलिस थानों, राज्य मुख्यालयों और केंद्रीय पुलिस संगठनों के बीच आंकड़ों और जानकारी का प्रभावी एकत्रीकरण, संग्रहण, पुनः हासिल करना, विश्लेषण तथा आवश्यकता पड़ने पर आदान-प्रदान तथा उपलब्ध कराना था. इस योजना में क्या प्रगति हुई, इसकी कोई रिपोर्ट अब तक सामने नहीं आई है, क्यों? इसकी वजह यह है कि सरकार के बाएं हाथों को पता नहीं होता कि दाहिना हाथ क्या कर रहा है. हमारी ख़ुफ़िया संस्थानों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण समय पर कोई कार्रवाई कर पाना संभव नहीं होता.

● **एनसीटीसी कहा है?–** नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर (एनसीटीसी) की स्थापना देश तथा लोगों पर होने वाले आतंकी हमलों से सीधे निपटने के लिए की जानी थी, जैसा कि नाम है. इसका उद्देश्य आतंकी हमलों को रोकना तथा आतंकवादियों से कड़ाई से निपटना है. इस तरह एससीटीसी को आतंकी हमलों के संदर्भ में ख़ुफ़िया, जांच तथा हमलों के दौरान ऑपरेशन संचालित करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी. एनसीटीसी को सभी तरह के हिंसक समूहों की गतिविधियों से निपटने के लिए तैयार किया जाना था, जिनमें विभिन्न आंतकी संगठन, उत्तर पूर्व के उग्रवादी संगठन तथा माओवादियों से मुक़ाबला शामिल है. साथ ही एनसीटीसी को ऐसे धार्मिक तत्वों पर नकेल कसने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी, जो देश के भीतर या बाहर आंतकियों के साथ मिले हुए हैं. अमेरिका ने 11 सितंबर 2001 के हमले के मात्र 36 महीने के भीतर एनसीटीसी की स्थापना कर ली थी. भारत के तत्कालीन गृहमंत्री ने भरोसा दिलाया था कि हमारे यहां भी वर्ष 2010 के अंत तक यह काम पूरा हो जाएगा, लेकिन गृह सचिव अब कह रहे हैं कि एनसीटीसी अनिश्चितता के भंवर में है. सरकार ने अब तक इसके प्रस्ताव को ही स्वीकार नहीं किया है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि वर्तमान एजेंसियों और संस्थाओं को लगता है कि यदि एनसीटीसी का गठन हो गया तो उनका अस्तित्व ख़तरे में पड़ जाएगा और वर्षों से जमे-जमाए उनके अधिपत्य को क्षति पहुंचेगी. इसके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को ख़तरे में डालने से भी परहेज़ नहीं किया जा रहा है.

● **नेटग्रीड कहां है? –** नेटग्रीड विभिन्न जांच एजेंसियों का ऐसा समूह है जो किसी भी संदिग्ध आतंकवादी या क़ानून को तोड़ने वालों के विषय में जानकारी मांगे जाने पर तत्काल उपलब्ध कराता है. इसे भारत की सुरक्षा से जुड़ा मूलभूत संगठन समझा जाता है. नेटग्रीड के तहत डाटा बेस के 21 सेट को एक नेटवर्क के तहत स्थापित किया जाना था, ताकि किसी भी तरह की सूचना/जानकारी को तत्काल सुरक्षित रूप से ख़ुफ़िया संस्थाओं को उपलब्ध कराया जा सके. दिसंबर 2009 में गृहमंत्री ने आश्वासन दिया था कि यह परियोजना 18 से 24 महीने में पूरी हो जाएगी, लेकिन सच्चाई यह है कि पिछले महीने केंद्रीय मंत्रिमंडल ने योजना के प्रथम चरण को केवल सैद्धांतिक रूप से मंज़ूरी दी है. आख़िर इसकी वजह क्या है?

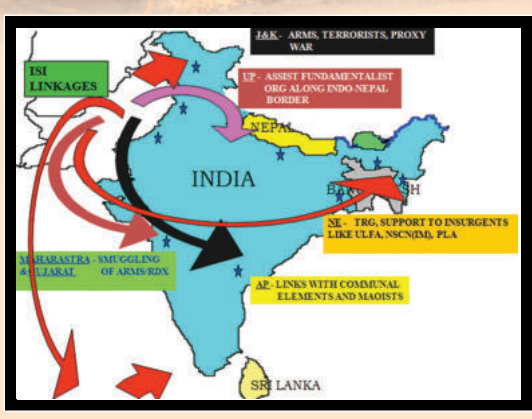

● **आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय –** आंतरिक मामलों का मंत्रालय (एमएचए) ऐसे अनेक कार्यों को अंजाम दे रहा है जिसका देश की आंतरिक सुरक्षा से कोई ताल्लुक़ नहीं है. उदाहरण के लिए इस मंत्रालय का एक विभाग स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़े मुद्दों पर काम कर रहा है, लेकिन फोरेंसिक साइंस (विज्ञान) के मामलों के निपटारे के लिए मंत्रालय में कोई विभाग नहीं है. केंद्र-राज्य संबंध, राज्य विधान मंडलों, मानवाधिकार, केंद्र शासित प्रदेश, आपदा प्रबंधन, जनगणना जैसे मुद्दों पर भी यह मंत्रालय ध्यान देता है, लेकिन इन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों पर यह ख़ामोश है. वरिष्ठ सुरक्षा विशेषज्ञ तथा कारगिल समीक्षा कमेटी रिपोर्ट के लेखक के. सुब्रमण्यम ने कैबिनेट मंत्री के नियंत्रण में एक ऐसे मंत्रालय की स्थापना का सुझाव दिया है जो पूरी तरह से आंतरिक सुरक्षा के प्रति समर्पित हो. उन्होंने कहा कि आंतरिक सुरक्षा को गृह मंत्रालय की ज़िम्मेदारियों का हिस्सा नहीं होना चाहिए. जिस तरह देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए रक्षा मंत्रालय है, उसी तरह आंतरिक सुरक्षा के लिए परिपूर्ण मंत्रालय की दरकार है. यद्यपि गृहमंत्री को अपना सारा समय और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों में लगाना चाहिए, लेकिन इस वादे को वह नहीं निभा पा रहे, क्यों?

● **सरकारें बदलती हैं, आईएसआई की रणनीति नहीं –** 1971 के युद्ध में भारत के हाथों मिली पराजय से बौखलाकर पाकिस्तान ने बदला लेने की रणनीति अपना रखी है. तत्कालीन जनरल ज़िया के सैन्य शासक ने कुख्यात ख़ुफ़िया एजेंसी आईएसआई के साथ मिलकर भारत को अस्थिर और खंडित करने की एक दीर्घ योजना बनाई थी. इस योजना को के प्लान नाम दिया गया था. यहां के का संबंध पाकिस्तान के सबसे उंचे पर्वत काराकोरम से है. इस षड़यंत्र का मक़सद भारत में नफ़रत के बीज बोना, देश के संवेदनशील क्षेत्रों में जातिवाद और सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देना था. बाद के वर्षों में आईएसआई ने इस षड़यंत्र का नाम बदल कर के-2 प्लान कर दिया. इसका लक्ष्य ख़ालिस्तान का निर्माण तथा कश्मीर में अलगाववादी आंदोलन को हवा देना था. तब से लेकर अब तक सभी स्तरों पर पड़ोसी मुल्क इस के-2 षड़यंत्र को सफल बनाने का पुरज़ोर प्रयास कर रहा है.

● **आईएसआई की योजना में परिवर्तन –** आज़ाद कश्मीर में आईएसआई 52 आंतकी प्रशिक्षण केंद्र चला रहा है. लगभग 2000-2500 आतंकी भारत में घुसपैठ की ताक में हैं. निजी धार्मिक संगठनों के माध्यम से आतंकवाद ने पाकिस्तान में निजी उद्योग का दर्जा हासिल कर लिया है. भारत के कई राज्यों में आईएसआई धार्मिक और जातिगत विभाजन का खेल खेल रही है. दंगा प्रभावित क्षेत्रों से बड़ी संख्या में मुस्लिम युवाओं को आंतक की इस घिनौनी मुहिम में शामिल कराने की कोशिशें की जा रही हैं. इन्हीं युवाओं के माध्यम से फ़र्ज़ी मुद्रा का जाल फैलाने की साज़िश रची गई है. भारत के विभिन्न हिस्सों में आईएसआई एजेंटों की टीम खड़ी की जा रही है. मुस्लिम बहुल इलाक़ों में नए नामों से संगठन बनाए जा रहे हैं. लोगों की संवेदनाओं को कुरेदकर सांप्रदायिकता बढ़ाने की मंशा आईएसआई ने पाल रखी है. जेल में बंद कुख्यात अपराधियों और आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे मुजरिमों को आंतक के इस खेल में शामिल करने की कोशिशें की जा रही हैं.

● **आईएसआई की नापाक कार्यप्रणाली –** आईएसआई भारत में अपना जाल फैलाने के लिए कई तरह के हथकंडे अपना रही है, जिनमें अपने एजेंटों को प्रमुख शहरों में स्थाई तौर पर बसाना, नौकरी दिलाना और भारतीयों के साथ विवाह करवाना प्रमुखता से शामिल है. आवश्यकता पड़ने पर यह एजेंट सक्रिय हो जाते हैं. गुजरात में भारत पाक सीमा पर कच्छ के रण केनिकट इन दहशतगर्दों को भारत में प्रवेश कराने का प्रबंध किया जाता है, क्योंकि गृह मंत्रालय के अधीन बीएसएफ यहां प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पा रही है. भारत से बड़ी संख्या में हज के लिए जाने वालों तथा खाड़ी देशों में काम कर रहे दक्षिण भारतीय लोगों को बरगला कर इस मुहिम में शामिल करवाया जाता है. मदरसों की स्थापना केलिए धन मुहैया कराया जाता है. भारत-बांग्लादेश और भारत-नेपाल सीमा से घुसपैठ के मामले निरंतर बढ़ रहे हैं. आईएसआई कश्मीर के मुस्लिम युवाओं को भी भारत विरोधी मुहिम में से इस्तेमाल कर रहा है. इतना ही नहीं उसने भारत में विस्फोटक बनाने या हासिल करने की क्षमता भी हासिल कर ली है. अब केम्रल बेहद ज़रूरी छोटे सैन्य उपकरणों को स्मगलिंग करके लाया जा रहा है. आईएसआई ने बड़ी चालाकी से अपने षड़यंत्र को अंडरवर्ल्ड और अलगाववादी मुहिम से जोड़ दिया है. जम्मू-कश्मीर सहित उत्तर पूर्व के विभिन्न राज्यों के स्थानीय प्रशासन में आईएसआई का हस्तक्षेप निरंतर बढ़ रहा है, ताकि वह जिहाद को यहां पाल-पोस सकें. आईएसआई तत्व यह दुष्प्रचार करने में लगे हुए हैं कि मुस्लिमों के लिए जिहाद ही सबकुछ है. जो शख्स जिहाद के नाम पर स्वयं को कुर्बान कर देता है, अल्लाह उसे जन्नत में जगह देता है.

● **भारत में आईएसआई के लिए अनुकूल माहौल –** भारतीय नेतृत्व कोई कार्रवाई करने की बजाय लंबे-चौड़े भाषण देने में यक़ीन करता है. हर हमले के बाद देश के नेता आंतकवाद को मुहतोड़ जवाब देने का बयान देते नज़र आते हैं. टीवी चैनलों पर होने वाली बहस के दौरान अक्सर हम यह नज़ारा देखते हैं. भारत को एक साफ्ट स्टेट माना जाता है, जिसकी विश्वसनीयता अधिक नहीं है. साथ ही हमारे नेता बेहद धैर्यवान हैं जिनके पास आईएसआई जैसी कुटिल एजेंसी के मंसूबों पर पानी फेरने केलिए कोई ऐसी रणनीति या उपाय योजना नहीं है. हम सभी के साथ घुलमिल कर रहने में यक़ीन करते हैं, भले ही कोई हमारा दुश्मन ही क्यों न हो. हम अपने शत्रुओं से भी कड़ाई से पेश नहीं आते. उत्तर-पूर्व भारत का बांग्लादेशीकरण इसका एक उदाहरण है. आईएसआई और पाकिस्तान को लेकर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए हमारे नेता अमेरिका की ओर देखते हैं. यही वजह है कि पाकिस्तान बार-बार भारत को संकट में डालता है. मुद्दा यह है कि आईएसआई रूपी दैत्य पर रोक लगाई जा सकती है? यह बिल्कुल संभव है यदि राजनीतिक इच्छाशक्ति से वोट बैंक की राजनीति को परे कर आतंकियों का मुक़ाबला करे तो आईएसआई से निपटना मुश्किल नहीं होगा. भारत के समक्ष सुरक्षा को लेकर अनेक ख़तरे विद्यमान हैं. हम तभी उनका सक्षमता से सामना कर सकते हैं जब हम पूरी तरह संगठित रहेंगे.

feedback@chauthiduniya.com

आईएसआई और पाकिस्तान को लेकर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए हमारे नेता अमेरिका की ओर देखते हैं. यही वजह है कि पाकिस्तान बार-बार भारत को संकट में डालता है. मुद्दा यह है कि आईएसआई रूपी दैत्य पर रोक लगाई जा सकती है? यह बिल्कुल संभव है यदि राजनीतिक इच्छाशक्ति से वोट बैंक की राजनीति को परे कर आतंकियों का मुक़ाबला करें तो आईएसआई से निपटना मुश्किल नहीं होगा. भारत केसमक्ष सुरक्षा को लेकर अनेक ख़तरे विद्यमान हैं.

चौथी दुनिया
महाराष्ट्र

सदस्यता फार्म (वार्षिक)

सदस्यता शुल्क- २५० /- रुपये

मैं "चौथी दुनिया" साप्ताहिक समाचार पत्र का सदस्य बनना चाहता/चाहती हूँ।

मेरा नाम श्री./ श्रीमती .....

मेरा पता .....

जिला.....राज्य .....पिन कोड.....

फोन (आ).....(का).....मोबाईल.....

ई -मेल.....

मैं रु. वार्षिक सदस्यता के लिए चेक क्रमांक.....

दिनांक .....बैंक.....शाखा..... द्वारा भेज रहा/ रही हूँ

नोट- यह सदस्यता शुल्क भारत में ही मान्य है तथा यह योजना सीमित अवधि के लिए है। समाचार पत्र केवल साधारण डाक द्वारा भेजा जाएगा।

सदस्यता शुल्क केवल चेक द्वारा आशीर्वाद पब्लिकेशन प्रा. लि. नागपुर के पक्ष में सदस्यता फार्म के साथ निम्नलिखित पते पर प्रषित करे या फिर हमारे प्रतिनिधि को फार्म कलेक्ट करने के लिए फोन पर सूचित करे.

कार्यालय
"चौथी दुनिया"- महाराष्ट्र,
आशीर्वाद पब्लिकेशन प्रा.लि.,
२७, पिसे कॉम्प्लेक्स, धंतोली पुलिया के पास, ग्रेट नाग रोड, नागपुर.
फोन - ०७१२-२७०७४१४/१५ फैक्स- ०७१२-२७५२०२५
Email: chauthiduniyaa@gmail.com

पाठक ध्यान दें
जिन पाठको कों चौथी दुनिया की वार्षिक सदस्यता चाहिए वे फार्म भरकर भेजें या कार्यालय में संपर्क करें.

चौथी दुनिया

बिहार झारखंड

दिल्ली, 15 अगस्त–21 अगस्त 2011

www.chauthiduniya.com

Website : sanjeevanibuildcon.in

"संजीवनी का है ऐलान, झारखण्ड-बिहार में हो सबका मकान"

AISHWARIYA RESIDENCY
Argora-Kathalmore Road, Ranchi
PLOT 6 LAC | DUPLEX 18 LAC

THE DYNASTY
Sidhu Kanhu Park, Kanke Road
PLOT 13 LAC | DUPLEX 25 LAC

SANJEEVANI HIGHWAY
Ranchi Patna Highway Road
PLOT 3 LAC | BUNGLOW 10 LAC

SANJEEVANI TOWNSHIP
4 Lane, Kanke Road, Ranchi
PLOT 3 LAC | BUNGLOW 10 LAC

SANJEEVANI STATION
BIT Pithoria, Road, Ranchi
PLOT 3 LAC | BUNGLOW 10 LAC

9661337777 / 9472722024

9472727767 / 9162779209

अब तो जंग होगी

फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

रामविलास पासवान ने नीतीश कुमार पर पलटवार की पूरी रणनीति अपनी देखरेख में तैयार की है. इसके तहत सरकार पर मुद्दों के आधार पर तीखा हमला किया जाएगा और सड़कों पर अपनी ताक़त का प्रदर्शन किया जाएगा. इसके अलावा अदालत में भी दो-दो हाथ की तैयारी है. बियाडा मामले में जिस तरह पासवान से बिना शर्त माफ़ी मांगने की मांग की गई है, उससे भी लोजपा प्रमुख ग़ुस्से में हैं. भरोसेमंद सूत्रों पर भरोसा करें तो पासवान नीतीश से जुड़े बहुत सारे पुराने मुद्दों को भी फिर ज़िंदा कर सकते हैं.

सरोज सिंह

राजनीति के मैदान में पिछले दिनों नीतीश कुमार ने लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान को गहरा झटका दिया. लोजपा के तीन विधान पार्षद जैसे ही नीतीश ख़ेमे में गए यह तय हो गया कि अब बारी विधायकों की आएगी. पटना से दिल्ली एक करने के बाद किसी तरह यह तोड़फोड़ बस टली भर है. मतलब नीतीश कुमार ने पासवान को एक तरह से कम से कम विधायकों के मामले में अकेला कर दिया, लेकिन अब बारी पलटवार की है. छेड़ा नीतीश कुमार ने है तो रामविलास पासवान ने भी तय कर लिया है कि अब छोड़ेंगे नहीं. इसलिए अगर आने वाले दिनों में लोजपा अपने अब तक के सबसे आक्रामक तेवर में नज़र आए तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी. रामविलास पासवान ने नीतीश कुमार पर पलटवार की पूरी रणनीति अपनी देखरेख में तैयार की है. इसके तहत सरकार पर मुद्दों के आधार पर तीखा हमला किया जाएगा और सड़कों पर अपनी ताक़त का प्रदर्शन किया जाएगा. इसके अलावा अदालत में भी दो–दो हाथ की तैयारी है. बियाडा मामले में जिस तरह पासवान से बिना शर्त माफ़ी मांगने की मांग की गई है, उससे भी लोजपा प्रमुख ग़ुस्से में हैं. भरोसेमंद सूत्रों पर भरोसा करें तो पासवान नीतीश से जुड़े बहुत सारे पुराने मुद्दों को भी फिर ज़िंदा कर सकते हैं. जैसे सीताराम सिंह हत्याकांड और चारा घोटाले में आर के दास का 164 के तहत दिया गया बयान और कोर्ट में इसकी गवाही. एसी डीसी बिल में सरकार की लापरवाही से संबंधित कोर्ट की टिप्पणी को भी उछालने की तैयारी है. पी के शाही की बेटी उर्वशी शाही के मैत्रीय एजुकेशनल ट्रस्ट को बियाडा की ज़मीन आवंटित करने में जितनी जल्दबाज़ी दिखलाई गई, उसे भी पासवान ज़ोर शोर से उठाने की तैयारी में हैं. पासवान मैत्रीय एजुकेशनल ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन के काग़ज़ को भी खंगाल रहे हैं. बताया जा रहा कि रजिस्ट्रेशन के समय इस ट्रस्ट की पूंजी मात्र 20 हज़ार थी, पर ज़मीन आवंटन के लिए तीस लाख से ज़्यादा का भुगतान ट्रस्ट ने किया. लोजपा का आरोप है कि चूंकि पी के शाही राज्य में शिक्षा मंत्री हैं इसलिए इस ट्रस्ट को शिक्षण संस्थानों के लिए जल्दबाज़ी में ज़मीन आवंटित की गई है. लोजपा के प्रधान महासचिव राघवेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि इस ट्रस्ट के पांच सदस्यों में से तीन पी के शाही से जुड़े हैं. इन्हीं सब बातों को लेकर पासवान नीतीश कुमार का इस्तीफ़ा मांगेंगे.

इन सबके अलावा ज़िला स्तर पर संगठन को मज़बूत कर यह संदेश देने की कोशिश होगी कि पार्षदों के चले जाने से लोजपा का मनोबल टूटा नहीं है, बल्कि पार्टी पूरी मज़बूती के साथ नीतीश सरकार के कारनामों का पर्दाफाश करेगी. ज़िला स्तर पर रैलियों के बाद पटना में एक बड़ी रैली कर नीतीश कुमार को करारा जवाब देने की तैयारी है.

feedback@chauthiduniya.com

बियाडा ज़मीन पर उद्योग और मॉल की जगह

कहीं खुली दुकान तो कहीं बसे घर

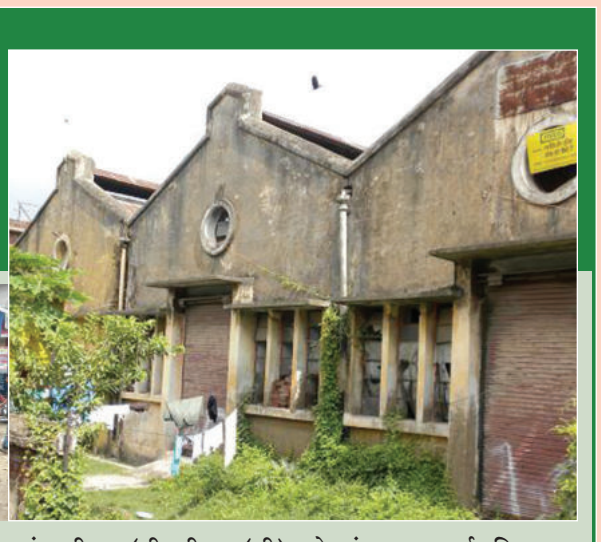

उद्योग लगाने एवं मॉल खोलने के लिए बियाडा द्वारा दी गई ज़मीन का इस्तेमाल बिहार शरीफ़ में निजी आवास, रेडिमेड दुकान, मार्बल शोरूम, महेंद्रा शोरूम, मारुति वर्क्स शॉप के लिए किया जा रहा है. जिस तरह ज़मीन का आवंटन किया गया, उस पर भी उंगली उठाई जा रही है. ग़ौरतलब है कि रामचंद्रपुर क्षेत्र के लघु उद्योग निगम पटना द्वारा वर्ष 1962 में 10 एकड़ भूमि पर औद्योगिक प्रांगण की स्थापना की गई थी. इस प्रांगण में लंबे समय तक खादी ग्रामोद्योग द्वारा हस्त उत्पादित काग़ज़ निर्माण, कपड़ा निर्माण, चर्म उद्योग, हैंडलूम एवं कृषि उद्योग विकास निगम के उद्योग लंबे समय तक लगभग वर्ष 1980–82 तक अच्छे ढंग से चला. दिन–प्रतिदिन ज़मीन की क़ीमत में भारी इज़ाफ़ा हुआ और लोगों की नज़र बियाडा ज़मीन पर पड़ी. वर्ष 1980–82 के बाद लघु उद्योग में शामिल ट्रेडों को छोड़कर अन्य वैसे ट्रेड को इस प्रांगण में बियाडा द्वारा जगह दी गई, जो लघु उद्योग की लिस्ट में शामिल नहीं है. अभी वर्तमान में ऐसी 49 यूनिटें बियाडा द्वारा चलाने का दावा किया जा रहा है, परंतु यह हक़ीक़त से कोसों दूर है.

वर्ष 2007–08 वर्ष में बियाडा की लगभग 24 हज़ार वर्ग फीट ज़मीन फिल्म निर्माता प्रकाश झा को होलिकाउ पिक्चर प्रा. लि. एंड मल्टीप्लेक्स मॉल के नाम से दी गई. इसके बाद प्रकाश झा ने बियाडा द्वारा दी गई ज़मीन की घेराबंदी कराकर मॉल का काम प्रारंभ कर दिया. चूंकि इतनी ज़मीन पर मॉल का निर्माण होना कठिन हो रहा था, इसलिए कंपनी ने ब्लॉक सी–1 से सी–3 के सटे 15 हज़ार वर्ग फीट ज़मीन जो मो. ताहिर के नाम से आवंटित थी और इस ज़मीन पर कोई कारोबार नहीं हो रहा था, क्योंकि मो. ताहिर की मृत्यु हो चुकी थी. मो. ताहिर के पुत्र मो. आरिफ़ रज़ा से ज़मीन का स्थानांतरण कर देने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, पर बियाडा के पूर्व प्रबंध निदेशक के.के सिंह ने आपत्ति ज़ाहिर की और कहा कि इसे छोटे–छोटे उद्योग के लिए लोगों के बीच वितरण किया जाएगा और मो. ताहिर की आवंटित ज़मीन को चार लोगों विजय कुमार एंड कंपनी, साईं ट्यूबेल सर्विस, बिहार बॉडी बिल्डर्स एवं शांता सर्विस जैसे ट्रेड के बीच बिना विज्ञापन प्रकाशित किए हुए आवंटित कर दिया गया, जबकि अभी भी आवंटित ज़मीन के मामले उच्च न्यायालय में लंबित पड़े हैं. चूंकि प्रकाश झा को 15 हज़ार वर्ग फीट ज़मीन नहीं मिली तो उन्होंने पूर्व मिली 24 हज़ार वर्ग फीट ज़मीन को दिलीप कुमार नामक व्यक्ति को स्थानांतरित कर दिया. बाद में बियाडा ने इस ज़मीन को स्थायी आवंटन 30 मई 2011 को कर दिया, जिसमें अभी भी मार्बल शोरूम चल रहा है. मज़े की बात यह है कि रामचंद्रपुर में बियाडा के कुल दस एकड़ ज़मीन में अभी भी दर्जनों व्यक्तियों का निजी आवास है, वहीं औद्योगिक कार्य के लिए दी गई ज़मीन पर रेडीमेड, महेंद्रा शोरूम के साथ–साथ अन्य कई तरह के व्यापार चल रहे हैं, पर इसे देखने वाला कोई नहीं है, जबकि इसकी देखरेख के लिए बियाडा द्वारा एरिया मैनेजर की स्थायी नियुक्ति की गई है. इस औद्योगिक प्रांगण के एरिया मैनेजर एस.एन लाल ने कहा कि इस प्रांगण में जो ज़मीन का बंदोबस्त किया गया है, उसकी सारी प्रक्रिया पटना बियाडा कार्यालय द्वारा की गई है. उधर बिहार शरीफ़ में बियाडा की फैक्ट्री के नाम पर दी गई ज़मीन पर निजी आवास हैं, जिनमें मेसर्स पाल इंडस्ट्रीज, लैट नं– डी–2 (पी–डी–2 (बी) इसे पांच हज़ार वर्ग फीट दाल मील के नाम पर दिया गया था, वहीं मेसर्स स्वर्ग लोक रेस्डेंसी को पांच हज़ार वर्ग फीट ज़मीन होटल मोटल के लिए आवंटित किया गया था, पर इसमें निजी आवास हैं. मेसर्स अजंता इंडस्ट्रीज को 63 सौ वर्ग फीट ज़मीन फैक्ट्री के लिए दी गई थी. इस पर भी निजी आवास हैं. इसी प्रकार भारती गुल इंडस्ट्रीज को 25 सौ वर्ग फीट ज़मीन गुल उद्योग के लिए आवंटित की गई थी. इसमें भी निजी आवास हैं. सर्वोदय इंजीनियरिंग वर्क्स के प्लाट नं. एफ–2 (पी) एंड एफ–3 (पी) जी–8 प्लॉट के 7 हज़ार वर्ग फीट ज़मीन गोबर गैस प्लांट के लिए आवंटित की गई थी, परंतु इसमें मारुति पार्ट्स की दुकान के साथ–साथ निजी आवास स्थापित हैं. इसके साथ अन्य आवंटित ज़मीन पर भी निजी कार्य हो रहे हैं.

कुमार प्रशांत

feedback@chauthiduniya.com

बैंकों से क़र्ज लेने की परंपरा ने एक तरफ़ जहां फ़र्ज़ीवाड़े को बढ़ावा दिया, वहीं बैंकों में भ्रष्टाचार बढ़ा है. अब किसानों को सीधे अनुदान देने से उन्हें बैंकों के चक्कर लगाने से निजात मिल सकती है.

दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीज़ों की संख्या को देखते हुए अनुमान लगाया जा सकता है कि इस मेडिकल कॉलेज अस्पताल की व्यवस्था में कितना सुधार हुआ है.

शकील पर आरोपों की बौछार

सुनील सौरभ

राजनीति में न कोई स्थायी दोस्त होता है और न कोई स्थायी दुश्मन. यह बात राजद के प्रवक्ता और लालू यादव के सबसे क़रीबी रहे शकील अहमद ख़ान का राजद छोड़कर नीतीश का दामन थामने के बाद स्पष्ट हो गई. कथित जंगल राज और लालू–राबड़ी के शासनकाल में सबसे अधिक मलाई काटने वाले शकील अहमद ख़ान ने नीतीश कुमार का दामन थामा तो उनके गृह ज़िला के मुस्लिम नेताओं में उबाल आ गया. जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष मसरूर आलम ने कहा कि शकील अहमद ख़ान हमेशा मुसलमानों के ख़ून पर राजनीति करते रहे हैं. भागलपुर दंगा कांड के सैकड़ों अभियुक्तों को विशेष कर मुख्य अभियुक्त चुनचुन यादव को हाई कोर्ट के सरकारी वकील होकर बचाने का काम उन्होंने किया था. इसी के फलस्वरूप लालू यादव ने पहले उन्हें विधान पार्षद बनाया और फिर मंत्री पद भी दिया. गया ज़िले के मुसलमानों में शकील अहमद ख़ान के प्रति घृणा है, क्योंकि भदेया में वक्फ़ की ज़मीन को अपने परिवार के नाम लिखवा लिया, तो दूसरी ओर चेरकी यतीमख़ाने की ज़मीन को सुरेंद्र यादव को दिलवा दिया. कोठी में हुए मुसलमानों की हत्या के मामले में किसी तरह का मुआवज़ा दिलाने का काम शकील अहमद ने नहीं किया. यहां मुसलमानों में उनकी कोई पैठ नहीं है. कांग्रेस के पूर्व ज़िला महासचिव मुन्ना हसन ने कहा कि भागलपुर दंगे के बाद मुसलमानों की लाश पर राजनीत कर शकील अहमद विधान पार्षद बने थे और अब 15 वर्षों के बाद सत्ता से अलग होने का दर्द उन्हें बर्दाश्त से बाहर हो गया, तो फारबिसगंज गोली कांड में मारे गए एक मासूम समेत चार मुसलमानों की लाश पर राजनीति करते हुए वह जदयू का दामन थामा, लेकिन इससे जदयू को कोई लाभ होने वाला नहीं है. भाजपा के साथ राजनीति करने वाला जदयू कभी भी सेकुलर नहीं हो सकता है. दिखावे के लिए मुसलमानों का हमदर्द बना है. पूर्व ज़िला पार्षद सदस्य मो. आसिर ने कहा कि शकील अहमद ख़ान के राजद छोड़ने से ज़िले के मुसलमानों में ख़ुशी है, क्योंकि राजद में रहकर वे मुसलमानों का कोई काम नहीं करते थे. वे परिवारवाद में ही फंसे रहे. शकील अहमद ख़ान के पुराने विधानसभा क्षेत्र गुरुआ के प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष बांके ख़ां ने उनके राजद छोड़ने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इससे न तो जदयू को फ़ायदा होगा और न ही राजद को कोई नुक़सान. कांग्रेस को इसका लाभ ज़रूर मिलेगा, क्योंकि शकील अहमद ख़ान को गया के मुसलमान एक धोखेबाज़ के रूप में जानते हैं. वह मुसलमानों से हमेशा वोट लेने के नाम पर सिर्फ़ धोखेबाज़ी ही करते रहे. ज्ञात हो कि 1990 के पहले शकील अहमद ख़ान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में थे और गया की सड़कों पर लाल झंडे के सहारे अपनी राजनीति करते रहे. उन्होंने गया शहर विधानसभा क्षेत्र से कई बार चुनाव भी लड़ा, लेकिन सफलता नहीं मिली तो लाल झंडे को छोड़कर हरा झंडा थामकर लालू के सहारे बिहार की राजनीति के अहम मुक़ाम पर पहुंचे, लेकिन आज राजद छोड़ने पर शकील अहमद ख़ान को गया ज़िले में मौक़ापरस्त राजनीति करने पर लोगों को आश्चर्य लग रहा है. सच यह है कि ज़िले के मुस्लिम वोट बैंक पर शकील अहमद ख़ान की कभी मज़बूत पकड़ नहीं रही. राजद छोड़कर जदयू में जाने से मुसलमानों के वोट बैंक पर कोई असर नहीं पड़ने की बात राजद के वरिष्ठ नेता व पूर्व सांसद रामजी मांझी कहते हैं. उन्होंने कहा कि ख़ान नीतीश कुमार को मुसलमानों का कौन सा मसीहा कहेंगे.

रामजी माझी मुन्ना हसन

feedback@chauthiduniya.com

सिमरिया घाट में अर्द्धकुंभ
सरकार, संत और विवाद

दिव्या कुमारी

[illegible]

अमरेंद्र उर्फ लल्लू बाबू

स्वामी चिदात्मन जी महाराज

बिहार के लिए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का है और सिमरिया घाट का कुंभ आयोजन सांस्कृतिक और आर्थिक विकास की राह में मील का पत्थर बनेगा. कुंभ आयोजन में सरकारी हस्तक्षेप की बात पर रजनीश कहते हैं कि कहीं भी सरकार कुंभ का आयोजन नहीं करती, बल्कि सहयोग करती है. एमएलसी विनोद चौधरी भी कुंभ आयोजन को तार्किक बताते हुए कहते हैं कि उनका प्रयास होगा कि सरकार वहां आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता पक्की करे. राज्य के पर्यटन मंत्री सुनील कुमार पिंटू अपने पुराने स्टैंड पर क़ायम हैं. पर्यटन मंत्री कहते हैं कि कुंभ का आयोजन धार्मिक मसला है और इसका आयोजन सरकार नहीं करती, बल्कि आयोजन की व्यवस्थाओं में सहयोग करती है. सुनील कुमार पिंटू कहते हैं कि कुंभ का आयोजन कौन करेगा? यह आयोजकों और धर्माचार्यों का विषय है, परंतु सरकार ने इसके ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए सिमरिया घाट के विकास के लिए डेढ़ करोड़ रुपए की राशि को स्वीकृति प्रदान की है. पर्यटन मंत्री की मानें तो उक्त राशि से घाट, शौचालय, चेंज रूम का निर्माण किया जाना है, जिसके लिए पच्चीस लाख रुपए तत्काल निर्गत कर दिए गए हैं. कुंभ आयोजन पर उत्पन्न विवाद से जुड़े लोगों और घटनाओं–प्रक्रियाओं को गौण कर यदि निष्पक्षतापूर्वक मामले को समझने का प्रयास किया जाए तो सिमरिया घाट में अर्द्धकुंभ लगना तय है. ऐसा सिर्फ़ आयोजकों की तैयारियों को देखकर नहीं कहा जा रहा है, बल्कि घटनाक्रम भी इस ओर इशारा करते हैं. आरएसएस प्रमुख का बिहार दौरे पर सिमरिया घाट अर्द्धकुंभ को समर्थन देना, मध्य प्रदेश के मंडला और गुजरात के पंपा सरोवर में संघ द्वारा कुंभ आयोजित कराना, सत्ताधारी गठबंधन के नेताओं की सक्रियता सरकार द्वारा राशि की स्वीकृति और कुंभ आयोजन पर स्टैंड स्पष्ट न करना स्पष्ट इशारा करते हैं कि गुपचुप तैयारियां जारी हैं. सरकार भी टकराव मोल लेने के मूड में नहीं है और वह गेंद आयोजकों के पाले में फेंक रही है. कुंभ के आयोजन पर एक दूसरे को आईना दिखाने का दौर जारी है. कुंभ स्नान की पवित्र डुबकी तो भक्त पवित्र कार्तिक में लगाएंगे, परंतु राजनीति की दरिया में विवादों की डुबकी हर कोई लगाने को आतुर है. लेकिन सरकार की तरफ़ से अब तक कोई भी बयान नहीं आया है.

feedback@chauthiduniya.com

सर्जरी डरने की चीज़ नहीं : डॉ. अजय

आज के दौर में रोग के इलाज में सर्जरी का महत्व काफ़ी बढ़ गया है. इसके कारण क्या हैं और क्यों लेना पड़ता है चिकित्सकों को सर्जरी का निर्णय. कोसी प्रमंडल के मुख्यालय सहरसा के प्रसिद्ध सर्जन डॉ. अजय कुमार ने इस बारे में बातचीत की. प्रस्तुत है ख़ास अंश.

● **आज सर्जरी चिकित्सा में भारी वृद्धि हुई है, क्या कारण है ?**

डॉ. अजय– ऐसी बात नहीं है. जनसंख्या की वृद्धि और इलाज के प्रति लोगों की बढ़ती जागरुकता से रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई है. इसीलिए सर्जरी आंकड़ों में अधिक होती दिखती है. वास्तविकता में ऐसी बात नहीं है. हालांकि कुछ रोग ऐसे हैं, जिसमें सर्जरी के बिना इलाज संभव नहीं है.

डॉ. अजय कुमार सिंह

● **क्या सर्जरी से पूर्व रोगी को मानसिक रूप से तैयार किया जाना चाहिए.**

डॉ. अजय– निश्चित तौर पर सर्जरी के लिए जाने वाले रोगी को मानसिक रूप से तैयार करना सर्जरी की सफलता का प्रतिशत बढ़ाती है. इसके लिए रोगी से चिकित्सक लगातार कांसेलिंग करते रहते हैं जिससे सर्जरी के प्रति इनका डर निकल जाता है और रोगी सर्जरी को भी इलाज का एक हिस्सा मानने लगते हैं. साथ ही ज़रूरत पड़ने पर अन्य विशेषज्ञों व कुछ दवाओं की सहायता भी ली जाती है.

● **लेप्रोस्कोपिक सर्जरी क्या है? इससे रोगी को क्या सहूलियतें मिलती हैं?**

डॉ. अजय– यह सर्जरी की सबसे आधुनिक खोज है. जो कम छिद्र करके रोग का उपचार ही नहीं करता, बल्कि रोगी को अस्पताल से जल्दी छुट्टी भी मिल जाती है और सर्जरी के दौरान रोगी को दर्द भी कम होता है. अपने यहां भी इसकी सुविधा उपलब्ध है, परंतु कम ही रोगों में इसकी सहायता लेने की सुविधा यहां प्राप्त है.

● **प्रसव कार्य में सर्जरी की सहायता लेने की चलन में भारी वृद्धि के विषय में क्या कहना चाहेंगे ?**

डॉ. अजय– ऐसी बात नहीं है कि नॉर्मल प्रसव कम होते हैं, बल्कि इसके अनुपात सर्जरी बहुत कम होती है. पहले सुविधा का अभाव था व इलाज के प्रति लोगों में जागरुकता कम थी, जिसके कारण प्रसव कार्य गांव–घर में संपन्न हो जाता था. परंतु अब लोग अस्पताल में चिकित्सक की सहायता लेने से जच्चा–व–बच्चा दोनों को सुरक्षित बचा पाते हैं, जिसके कारण सर्जरी की संख्या बढ़ी हैं.

मनोज ठाकुर
feedback@chauthiduniya.com

कृषि के विकास में बिचौलिये बने रोड़ा

विजयेन्द्र कुमार

कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे सभी प्रयासों का वास्तविक लाभ किसानों को मिलना सारण ज़िले में टेढ़ी खीर साबित हो रहा है. किसानों को कृषि क्षेत्र में आधुनिक व विकासपरक बनाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड से लेकर कृषि यंत्रों की ख़रीददारी कर उन्नत खेती के गुर बताए जाने वाले सभी कार्यक्रमों में बिचौलिये की घुसपैठ से कृषि के विकास के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे सभी प्रयासों पर ग्रहण लगता दिख रहा है. हक़ीक़त यह है कि ज़िले के अधिकांश बैंकों में किसान क्रेडिट कार्ड बनाने की प्रक्रिया मूलरूप से बिचौलियों की गिरफ्त में है, जिसमें बैंक कर्मियों की सांठ–गांठ बताई जाती है. बिचौलियों के मार्फत भूमिहीन व्यक्ति जहां केसीसी का लाभ लेने में सफल सिद्ध हो रहा है, वहीं वास्तविक किसानों के लिए केसीसी का लाभ मिलना दिवास्वप्न बनकर रह गया है. इसी प्रकार अनुदानित दर पर किसानों को मिलने वाले कृषि यंत्रों का फ़ायदा अक्सर बिचौलिये मार लेते हैं, जबकि इस बाबत विभाग द्वारा किसानों को इसकी सूचना तक उपलब्ध नहीं कराई जाती है. ज़िले में सरकार द्वारा किसानों को श्री विधि के धान की रोपाई किए जाने की बात महज़ बेमानी है. इस मद में किसानों को उपलब्ध कराए जाने वाले सभी खाद बीज का वितरण मनमाने रूप में करके कृषि को बढ़ावा देने की सरकारी घोषणा पर पलीता लगाए जाने का मामला प्रकाश में आता है.

यह बात सर्वविदित है कि कृषि के विकास के बिना बिहार के विकास की बात बेमानी होगी. राज्य सरकार ने खेती के आधुनिकीकरण का एक ठोस प्रयास किया है. किसानों को आधुनिक यंत्रों से लैस कराकर लागत मे कमी लाना और उत्पादन में वृद्धि इसका मूल उद्देश्य है. ख़ास बात यह है कि इस वर्ष बैंकों से लोन लेने की कई यंत्रों के लिए अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है तो कई कृषि यंत्रों पर अनुदान बढ़ा दिए गए हैं. किसानों को दिए जाने वाले इन यंत्रों को सरकार ने शिविर लगाकर बांटने का निर्देश दिया है. ऐसी हालत में अनुदान की राशि देने में सरकार और किसानों के बीच विचौलियों की गुंजाइश न के बराबर है, लिहाज़ा, किसान अपनी पसंद की किसी दुकान से कृषि यंत्र ख़रीद सकते हैं. अनुदान का लाभ लेने के लिए यह ज़रूरी नहीं है कि कृषि अधिकारियों द्वारा चिन्हित विक्रेता से ही वे यंत्र ख़रीदें. बैंकों से क़र्ज लेने की परंपरा ने एक तरफ़ जहां फ़र्ज़ीवाड़े को बढ़ावा दिया, वहीं बैंकों में भ्रष्टाचार बढ़ा है. अब किसानों को सीधे अनुदान देने से उन्हें बैंकों के चक्कर लगाने से निजात मिल सकती है. साथ ही दलालों से मुक्ति मिलने की संभावना बनती है. मगर हालत यह है कि अनुदान के लिए आने वाले किसानों के मामले में संबंधित अधिकारियों द्वारा पेंच फंसाकर विचौलिये की शरण में जाने के लिए मजबूर कर दिया जाता है. वहीं दूसरी ओर ज़िले के कई जगहों पर बिचौलियों ने कृषि यंत्रों की काग़ज़ी दुकान खोल रखी है. जहां लाचार होकर किसानों को अपना कोटेशन लेने के लिए जाना पड़ता है. इस बाबत बात करने पर ज़िला कृषि पदाधिकारी सुरेंद्र नाथ का कहना है कि कृषि को बढ़ावा देने के मक़सद से सरकारी निर्देशों का पालन करते हुए किसानों को इसका लाभ पहुंचाने के लिए विभाग प्रयासरत है, जबकि इस संबंध में किसानों का कुछ अलग कहना है. उनके मुताबिक़ इन सब प्रयासों के बावजूद बिचौलियों का साम्राज्य कायम है.

feedback@chauthiduniya.com

दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल बदहाल

उत्तर बिहार का सबसे बड़ा और सर्वाधिक साधन संपन्न दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल बुरी तरह बीमार है. स्वास्थ्य व चिकित्सा को गुणवत्तापूर्ण बनाए जाने के उद्देश्य से सभी सरकारी अस्पतालों का कायाकल्प करने का दावा सिर्फ़ काग़ज़ों में ही दिख रहा है. इस अस्पताल के विभिन्न वॉर्डों में वर्षों पूर्व जो पंखे लगाए गए थे, उनमें से अधिकांश पंखे बेकार पड़े हैं. बेड की कमी के कारण मरीज़ों को फ़र्श पर लिटाकर इलाज करवाना पड़ता है. यह राज्य का दूसरा बड़ा मेडिकल कॉलेज अस्पताल है, फिर भी यह सरकारी उपेक्षा का शिकार बना हुआ है. दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दस से बीस मरीज़ों पर एक नर्स और वॉर्ड अटेंडेंट की ही सुविधा उपलब्ध है. इस कारण सुई दिलाने या अन्य सुविधाओं में मरीज़ों के बीच मारामारी होती रहती है. इस अस्पताल में दवा पर सालाना 8 करोड़ रुपये ख़र्च होते हैं, लेकिन हालत यह है कि मामूली से मामूली दवाएं भी रोगियों को बाहर से ख़रीदनी पड़ती हैं, जबकि स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार को लेकर राज्य सरकार ने कई योजनाओं का श्रीगणेश भी किया, लेकिन विभागीय अधिकारियों की लापरवाही व अनदेखी के कारण यहां की अधिकांश ग़रीबोन्मुखी योजनाएं दम तोड़ रही हैं. दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आउटडोर के मरीज़ों के लिए 39 प्रकार की दवाएं उपलब्ध कराई जानी हैं. इसी प्रकार इंडोर के मरीज़ों के लिए 104 प्रकार की दवाएं एवं ओटी के मरीज़ों के लिए 34 प्रकार की दवाएं तथा ऑरथो ओटी के मरीज़ों के लिए 141 प्रकार की दवाएं उपलब्ध कराई जानी है, लेकिन अस्पताल प्रशासन द्वारा गिनी–चुनी कुछ ही दवाएं मरीज़ों को दी जा रही हैं. ब्लड बैंक शोभा के लिए है, बिना ब्लड दिए गंभीर हालत वाले मरीज़ को भी यहां के ब्लड बैंक से ख़ून नहीं मिलता है. ब्लड के अभाव में कई मरीज़ अब भी ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं. विशेषकर डायलसिस के मरीज़ों की हालत और भी दयनीय है. दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सरकारी सुविधा के नाम सिर्फ़ खानापूर्ति की जाती है और जर्जर भवन उपलब्ध है. 1030 शय्या वाले इस अस्पताल में आधे से ज़्यादा शय्याएं टूटीं और गद्दे फटे हैं. चादर, तकिये और मच्छरदानी की व्यवस्था भी मरीज़ों को स्वयं करनी पड़ती है. मुश्किल से दस–पंद्रह प्रतिशत मरीज़ों को ये सुविधाएं अस्पताल की ओर से उपलब्ध कराई जाती हैं, जबकि इस अस्पताल का वार्षिक बजट 55 करोड़ 89 लाख 83 हज़ार रुपये का है. बिहार सरकार के संयुक्त सचिव विश्वमोहन प्रसाद सिंह ने इस वर्ष 28 अप्रैल को ही ग़ैर योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2011–2012 में भी वेतन आदि एवं अन्य प्राथमिक इकाइयों में ख़र्च के लिए 34 करोड़ 96 लाख 92 हज़ार 100 रुपये के आवंटन की स्वीकृति दी है. दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में विशेषज्ञ के रूप में 51 बड़े चिकित्सक, 93 वरिष्ठ चिकित्सक और 57 सीनियर रेजिडेंस नियुक्त हैं. साथ ही 176 पीजी एवं 90 इंटर्न जूनियर चिकित्सक कार्यरत हैं, लेकिन हालत यह है कि जूनियर चिकित्सकों को छोड़ कर अधिकांश चिकित्सक कभी–कभार ही अस्पताल में आते हैं. इन्हें अपनी निजी क्लीनिकों और प्राइवेट नर्सिंग होम से फ़ुर्सत ही नहीं मिल पाती है.

भारतीय चिकित्सा परिषद ने तीन शय्याओं पर एक नर्स की सेवा अनिवार्य बताई है, लेकिन यहां दस से बीस शय्याओं पर एक नर्स कार्यरत है. रात में तो एक–दो नर्स पर पूरा वॉर्ड ही छोड़ दिया जाता है. रात्रि पाली की अधिकांश नर्सें रात सोकर गुज़ारती हैं. मरीज़ों के परिजन सुबह होने की प्रतीक्षा करते हैं. सफ़ाई और वॉर्डों की देखभाल के लिए 329 सफ़ाई कर्मचारी और कक्ष सेवक हैं, इनके अलावा दिल्ली की प्राइवेट कंपनी (बिमला इंटर प्राइजेज) के ज़िम्मे भी साफ़–सफ़ाई की व्यवस्था है, पर गंदगी का यह आलम है कि हर वार्ड में मलमूत्र, कूड़े–कचरे आदि का अम्बार लगा हुआ है. चौबीस घंटे में मात्र एक बार सुबह सफ़ाई होती है और फिर सारा दिन गंदगी फैलती रहती है. सुअर, कुत्ते, बकरियां, गाय, बैल, घोड़े, सांड़ जैसे जानवर दिन–रात मरीज़ों के बीच रोगों के कीटाणु फैलाते रहते हैं, जबकि इस अस्पताल में 95 प्राइवेट सुरक्षा कर्मी (बिमला इंटर प्राइजेज) भी तैनात किए गए हैं, जो तीन शिफ्टों में कार्य करते हैं, जिस पर प्रति माह 3 लाख 65 हज़ार रुपये ख़र्च होता है फिर भी सुरक्षा के नाम पर सिर्फ़ मरीज़ के परिजनों को वॉर्ड से बाहर करने और अस्पताल प्रशासन या चिकित्सक के विरुद्ध बोलने वालों की ख़बर लेने का कार्य करते हैं. दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दो एक्सरे यूनिट बंद हैं. कर्मियों की कमी के कारण इमरजेंसी वॉर्ड का एक्सरे यूनिट एक शिफ्ट में बंद रहता है. ऐसे में अगर कोई मरीज़ गंभीर हालत में आ जाए तो फिर उसकी जान भगवान भरोसे ही समझिए.

इतना ही नहीं इस अस्पताल में वायरस जांच करने वाली पॉलीमरेज चेनरिएक्शन मशीन (पीसीआर) भी एक वर्ष से धूल फांक रही है. यह मशीन न सिर्फ़ इंसेफेलाइटिस की प्रारंभिक जांच कर सकती है, बल्कि अन्य वायरसों की जांच के लिए भी कारगर है. यह मशीन माइक्रो बायोलाजी विभाग के एक कमरे में बंद पड़ी है.

दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक डॉ. सूरज नायक का कहना है कि मरीज़ों की संख्या को देखते हुए अनुमान लगाया जा सकता है कि इस मेडिकल कॉलेज अस्पताल की व्यवस्था में कितना सुधार हुआ है. उन्होंने कहा कि मेरे कार्यकाल में ही कई कार्य हुए हैं. कुछ कार्य भवन निर्माण, पी.एच.ई.डी. एवं विद्युत विभाग के अधीन हैं. इसमें भी सुधार के लिए विभागों को लिखा गया है. बातचीत में उन्होंने कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत एक जगह पर एम.आर.आई. की सुविधा उपलब्ध है. साथ ही सी.टी.स्कैन एवं अति आधुनिक लैब की भी सुविधा उपलब्ध है. उन्होंने कहा कि अति अधुनिक ट्रोमा सेंटर भी डी. एम. सी. एच. में जल्द शुरू हो जाएगा.

दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दस से बीस मरीज़ों पर एक नर्स और वॉर्ड अटेंडेन्ट की ही सुविधा उपलब्ध है. इस कारण इंजेक्शन दिलाने या अन्य सुविधाओं में मरीज़ों के बीच मारामारी होती रहती है.

अफ़ज़ल इमाम मुन्ना
feedback@chauthiduniya.com

इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एण्ड रिसर्च
We Impart:- POST GRADUATE COURSES: MPT, MOT, MPO, MASLP · BPT, BOT, BPO, BASLP, BMRT, BMLT, B.Ed., B.Ophth. · DIPLOMA COURSES: DPT, DPO, DMLT, D-X-Ray, DHM, DOTA, DECG · 1 Yr. ABRIDGED DEGREE For DPT & DOT
[illegible]

ऋण सुविधा
वाहन ऋण, सावधि ऋण, कैश क्रेडिट, पैक्सों के वास्ते
ऋण, सुविधा सस्ते ब्याज दर पर उपलब्ध है
विशेष जानकारी के लिए सम्पर्क करें
दि कोशी सेन्ट्रल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड
[illegible]

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं
शैलेन्द्र कुमार · बबलू चौधरी
आलू व्यापार कृषक व्यवसायी संघ
लक्ष्मा सिंह दरबार लाइन होटल
पूर्णिया ज़िला खनन कार्यालय के कर्मियों की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

उत्क्रमित मध्य विद्यालय, रामपुर छतवन
स्वतंत्रता दिवस के शुभअवसर पर समस्त देशवासी व समस्त रामपुर छतवन के ग्रामवासी एवं विद्यालय के सभी शिक्षकगण को हार्दिक शुभकामना
निवेदक कामेश्वर यादव (प्रधानाचार्य)
उत्क्रमित मध्य विद्यालय, रामपुर छतवन प्रखण्ड नवहट्टा, जिला सहरसा (बिहार)

पूर्णियावासियों को स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक बधाई
सुनील कुमार सिंह थाना प्रभारी

सुपर वन्दना सिन्दूर

A fastest Growing Company — Maker Of ACOBA CAP/SYP/INJ, ASRFEN-P, FLUCEN, Carbo-XT, ECTALOPAM, MUSTAL — Griskon

बाबा धाम का महाप्रसाद बाबा सिन्दूर

Enjoy with Nature MOULDED FURNITURE — CENTURY POLYPLAST INDUSTRIES — NATURE

PATALIPUTRA SCHOOL OF FIRE & SAFETY MANAGEMENT

EIILM UNIVERSITY SIKKIM
Courses: BA, BSc. B.Com. M.A., Misc. Mcom., Mphil, B.C.A, B.B.A., M.C.A., M.B.A.
Study Centre at ST. MICHAEL ANGLO VIDYALAYA, TIWARI CHOWK, DEOGHAR
ENGLISH MEDIUM UNDER C.B.S.E · HOTEL FACILITY
RUN BY KERALA EDUCATIONAL & SOCIAL WELFARE SOCIETY
Mob. : 9430345258 (J.C.RAJ)